हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

खण्ड 1, अंक 3

अधिकृत विवरण

विशय सूची

बुधवार, 19 फरवरी, 1986

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(3)1
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट	(3)18
वर्श 1985–86 के लिए सप्लीमैंटरी ऐस्टीमैटस (दूसरी कि त) पे ा करना	(3)22
एस्टीमैटस कमेटी की वर्श 1985–86 के सप्लीमैंटरी ऐस्टीमैटस (दूसरी कि त) पर रिपोर्ट पे ा करना	(3)22
बिल्ज (इंट्रोडयूस्ट सदन की अनुमति से)	(3)

(1) दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाईटीज (अमैंडमैंट) बिल, 1986	(3)22
(2) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एवं वैलिडै ान) बिल, 1986	(3)23
(3) दि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमी ान (एडी ानल फंक ांज) अमैंडमैंट बिल, 1986	(3)24
(4) दि महर्शि दयानन्छ यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिलख 1986	(3)24
(5) दि हरियाणा पब्लिक प्रिमि ाज एंड लैंड (एविक ान एंड रेट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल, 1986	(3)25
राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)26
राज्यपाल के अभिभाशण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर मतदान	(3)71

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 19 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाला, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ में 14–00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहिबान, अब सवाल होंगे।

तारांकित प्र न संख्या 1054

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री राम बिला ा भार्मा, सदन में उपस्थित नहीं थे।

Share of Ambala Cantt. in S.Y.L. Canal Water

***1089. Seth Ram Dass Dhamija:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the Government has taken up the matter for the early construction of S.Y.L. Canal with the Central Government; if so, the results thereof; and

(b) whether Ambala Cantt. will get any share out of S.Y.L. Canal Water; if so, the quantity therof ?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala)

(a) Yes. The construction of S.Y.L. Canal is scheduled for completion by 15-8-1986 and Haryana Government has asked Government of India to ensure its timely completion.

(b) Yes 12 Cusecs.

सेठ राम दास धमीजाः स्पीकर साहब, मेरे सवाल के जवाब में यह लिखा है कि सतलुज यमुना योजक नहर का निर्माण कार्य 15–8–1986 तक पूरा होना नि चत है और हरियाणा सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह इसका समय अनुसार निर्माण सुनि चत करे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अगर यह नहर 15–8–1986 तक न बनी तो फिर सरकार की क्या पोजी ान होगी ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः सर, हमने यह नहीं लिखा है कि 15–8–1986 तक नहर तैयार हो जाएगी। मैंने यह कहा है कि 15–8–1986 तक बनाने का ि ाडयूल है।

सेठ राम दास धमीजाः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह 12 क्यूसिक पानी सारे अम्बाला जिले के लिए है या सिर्फ अम्बाला कैन्ट के लिए है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, यह पानी अम्बाला कैन्ट के लिए है और आर्मी अथोरिटीज की रिक्वैस्ट पर यह पानी एलोकेट किया गया है।

सेठ राम दास धमीजाः इस पानी को स्टोर करने के लिए इरीगे ान विभाग ने क्या प्रबन्ध किया है ?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः पानी स्टोर करने काम इरीगे ान डिपार्टमैंट का नहीं है, पब्लिक हैल्थ का है या कैन्ट्रोनमैंट बोर्ड का है जिन्होंने पानी के लिए रिक्वैस्ट की है।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि नहर के बनने की ि ाडयूल्ड डेट 15–8–1986 है। स्पीकर साहब, पिछले दिनों अखबार में आया था कि चौधरी भाम ेर सिंह जी खुद जाकर नहर का काम मौका पर देख कर आये हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस बात से सन्तुश्ट हैं कि उनके पास जो ि ाडयूल है या गवर्नमैंट आफ इंडिया ने जो ि ाडयूल्ड टाइम दिया है, उस टाईम तक नहर तैयार हो जायेगी ? वे सन्तुश्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है; अगर नहीं हैं तो उन्होंने आगे के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः हरियाणा सरकार इस बात से कतई सन्तुश्ट नहीं है क्योंकि नहर की प्रोग्रैस ि ाडयूल के अनुसार नहीं है। 15–8–1986 तक प्रैजैंट प्रोग्रैस के मुताबिक पूरी होने की बहुत कम उम्मीद है। हमने इस बात के लिए उपाय किये हैं कि काम में तेजी अ ाये। हमने बार बार पंजाब सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि जिन कमियों के कारण नहर नहीं खुद रही है उन्हें पूरा किया जाए। थोडे से पार्ट में तो

अभी तक लैण्ड एक्वीजि ान भी नहीं हुई है। मैं हाउस को बताना चाहूंगा कि टोटल जमीन 3805.49 एकड एक्वायर करनी थी जिसमें से 214244 एकड एक्वायर हो चुकी है और 1663.05 एकड की अभी तक फाइनल एक्वीजि ान नहीं हुई है। 166305 में से 157205 एकड के सैक ान छः के नोटिस इ ाू हो चुके हैं और बाकी 91 एकड के बारे में सैक ान छः के नोटि ा इ ाू नहीं हुए हैं। हमें इन्क्वारी करने पर पता लगा है कि जिस जमीन के सैक ान छः और सात के नोटिस इ ाू नहीं हुए हैं उसके रेटस डिप्टी कमि नर से आने हैं, इसलिए वे अभी तैयारी में हैं। वे इन्फर्में ान कलैक्ट कर रहे हैं और जहां और उपायों की बात है उस बारें में गवर्नमैंट आफ इंडिया को लिखकर भी भेजा है। मुख्य मंत्री जी ने जबानी तौर पर भी बार बार बात की है कि पंजाब सरकार की जो एस0वाई0एल0 कन्सट्रक ान की म ाीनरी है वह ि ाडयूल के मुताबिक काम नहीं कर रही है, इसलिए काम तेजी से करवायें ताकि समय पर नहर बन सके।

कल ही बरनाला साहब की और हमारे मुख्य मंत्री जी की दिल्ली में मीटिंग थी जिसमें होम मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे। उसमें बरनाला साहब ने हमारे मुख्य मंत्री जी को आ वासन दिया है कि वह जल्दी ही बनेगी। यह भी बात कल ही हुई है कि दोनों चीफ मिनिस्टर नहर का इंसपैक ान करेंगे और बरनाला साहब कुछ दिनों में हरियाणा के मुख्यमंत्री को वहां लेकर जायेंगे। उन्होंने वायदा किया है कि इस काम में तेजी लायेंगे। स्पीकर

साहब, मैं भी कल प्रधान मंत्री जी से मिलता था और इस बात पर चर्चा हुई थी। प्रधान मंत्री जी भी इस नहर के बनाने में बडे उत्सुक हैं वे चाहते हैं कि यह नहर जल्द से जल्द बने, इसके लिए वे कारगर उपाय ले रहे हैं।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आज तक इस नहर के लिए कुल कितना पैसा दिया गया है क्योंकि पंजाब वाले कहते हैं कि पैसे की कमी के कारण काम रूका हुआ है ? अगर इसी धीमी गति से ही काम चलता रहा तो क्या हरियाणा सरकार भारत सरकार को कहेगी कि यह काम आप अपने हाथ में ले लो ? क्या इस बारे में कोई पहले भी बातचीत हुई है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार ने 110.5 करोड रूपया पंजाब सरकार को कै ा दियसा है और 2.80 करोड रूपए की म ीनरी दी है। रूपए की कमी के कारण इस नहर की खुदाई में कोई खराबी आई हो, यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। इस साल में भी पचास करोड से ज्यादा रूपया दिया जा चुका है। अभी काफी रूपया पंजाब सरकार के पास बाकी हैं जिसे खर्च करना है। यह कहना कि पैसे की कमी के कारण यह नहर पूरी नहीं हुई, यह बात उचित नहीं है।

जहां तक भले राम जी की दूसरी बात का सम्बंध है कि हरियाणा सरकार भारत सरकार से यह रिक्वैस्ट करे कि वह इस

नहर का काम अपने हाथ में ले ले। इस बात के बारे में हरियाणा सरकार भारत सरकार को रिक्वैस्ट कर चुकी है क्योंकि पिछले पांच छः महीने से यानि बारि ा के मौसम के बाद तेजी से काम नहीं हुआ है। हमने कहा है एकोर्ड के टाईम टेबल के हिसाब से तेजी से काम होना चाहिए या इस नहर के काम को खुद भारत सरकार अपने हाथ में ले ले या किसी आर्गेनाइजे ान के माध्यम से करवाये ताकि इस काम में तेजी लाई जा सके।

चौधरी फूल चन्दः स्पीकर साहब, जैसा कि मन्त्री जी ने बताया है कि वे मौके पर गए थे और नहर की खुदाई से वे सन्तुश्ट भी नहीं हैं। क्या मन्त्री जी ने मौके पर यह बात भी देखी थी कि जो 110.5 करोड रूपया नहर की खुदाई के लिए दिया था उसकी बजाय पंजाब के अधिकारियों ने इस पैसे से अपनी कोठियां बना ली हैं। अगर ऐसा है तो क्या इस बात पर भी कोई कार्यवाही करने के लिए भारत सरकार से मंत्री जी ने बातचीत की है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः सर, मैंने तो न किसी की कोठियां देखी हैं, और न किसी ने कोठियों की बात मुझे बतायी है। जहां तक इस बात का सवाल है कि जो रूपया खर्च हो रहा है, उसका लेखा जोखा किया जाए, उसने इन सारी बातों के लिए एक कमेटी बनाई हुई है। सैंट्रल वाटर कमी ान के मैम्बर उस कमेटी को चेयर करते हैं। उसमें अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उस खर्च का आडिट करवाया जाए और न ही हम करवा सकते हैं। वह तो पंजाब सरकार का इन्टरनल मामला है।

वह आडिट जरूर करवाते होंगे। लेकिन हम यह जरूर प्रैस करते हैं कि जो भी रूपया कि जो भी रूपया खर्च हो, वह ठीक खर्च हो। हम किसी ने किसी स्टेज पर यह इं योर करेंगे कि जो रूपया हरियाणा का खर्च होगा, उसका बराबर हिसाब किताब हम देखें और उसका सारा हिसाब किताब हमको मिले। दूसरी बात कोठियों की जो इन्होंने पूछी है, उसके बारे में मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि मुझे इस तरह की कोई ि ाकायत नहीं मिली है। हां, इस बात की कई बार ि ाकायत मिलती रहती है कि लैण्ड एक्वीजी ान का ज्यादा रूपया वहां पर लोगों को दिया जा रहा है। इस बारे में कई बार चिटिठयां भी आती रहती है लेकिन जिस बारे में मैम्बर साहब ने पूछा हैं, उस बारे में हरियाणा सरकार को कोई ि ाकायत नहीं मिली है।

चौधरी इन्द्र सिंह नैनः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने बताया है मैंने कोठियां तो नहीं देखी है और न ही किसी ने मुझे इस बारे में बताया है कि उन पर पैसा खर्च हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार जो नहर की खुदाई के लिए या कंस्ट्रक ान के वास्ते पैसा देती है, वह किसी दूसरी जगह पर खर्च न हो, यह कैसे एन् योर करती है। एक बात मैं और पूछना चाहता हूं। मंत्री जी ने फरमाया है कि प्रधान मंत्री जी से भी वे कल मिले हैं। क्या मंत्री जी बताएंगे और इस बात का अ योरैंस देंगे कि नहर की खुदाई अगर पंजाब सरकार नहीं करवाती है तो सैंट्रल गवर्नमैंट अपने हाथों में लेकर नहर को

जल्दी खुदवायेगी क्योंकि एस0वाई0एल0 हरियाणा की लाईफ लाईन है और सारा हरियाणा इसकी खुदाई की तरफ देख रहा है, पानी बहुत जरूरी है।

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः सर, दोनों बातों का जवाब वैसे तो मैं दे चुका हूं, लेकिन फिर बता देता हूं। जहां तक इस बात का कन्सर्न है कि यह लिंक हरियाणा के लिए लाईफ लाईन है, आदरणीय मैम्बर के साथ, पूरा हाउस, सरकार और हरियाणा का बच्चा बच्चा इस बारे में कोई दो राय नहीं रखता और सरकार इस बारे में पूरी तरह से जागरूक है। मैंने पहले ही कहा है कि प्रधान मंत्री जी इस बात के बारे में बडे उत्सुक हैं और बडे कीन हैं कि यह नहर जल्दी पूरी हो। जब प्रधान मंत्री ऐसा सोचते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसी फरदर बात की गुंजाई ा नहीं रहती। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इसका काम एक्सपीडाईट होगा। पंजाब के मुख्य मंत्री जी ने भी इस बारे में बहुत दिलचस्पी दिखाई है कि हम इसको जल्दी पूरा करेंगे और भारत सरकार भी पूरी तरह से इसमें दिलचस्पी ले रही है।

श्री कंवल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि एस0वाई0एल0 के जरिए जो रावी ब्यास के पानी का हमारा 3.5 एम0ए0एफ0 भोयर हरियाणा में आयेगा, उसका टैंटेटिवली डिस्ट्रिब्यू ान किस प्रकार से होगा, कितना कितना किस किस जिले में वह पानी जाएगा ?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः सर, वेसे तो इस सवाल का मेन सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि यह तो आलरेडी तय हुआ है कि हरियाणा के अन्दर कहां कहां पानी जायेगा, लेकिन फिर भी मैं चौधरी कंवल सिंह जो को यह कहना चाहूंगा कि अगर वे इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो किसी वक्त भी मेरे पास आ जायें मैं उनको यह उपलब्ध करवा सकतेा हूं। वे देख लें कि उस पानी की डिस्ट्रिब्यू ान किस प्रकार से की हुई है। मेनली यह पानी लिफ्ट इरीगे ान स्कीम में गुड़गांव कैनाल के एरिया में, यमुना के एरिया में और पुरानी भाखडा के एरिया में जायेगा। चूंकि इस वक्त इसका कोई सवाल नहीं था इसलिये पूरी जानकारी इस समय मेरे पास मौजूद नहीं है।

राव इन्द्रजीत सिंहः अभी मंत्री जी ने यह बताया है कि हमारी सरकार ने भारत सरकार को एप्रोच किया है कि वह इस नहर की कंस्ट्रक ान का काम अपने हाथ में ले ले। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि भाखडा ब्यास मैंनेजमैंट बोर्ड के अंदर हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारों के रिप्रेजैंटेटिव हैं लेकिन जो हैडवर्क्स के सोलूज गेटस हैं, उनका कन्ट्रोल पंजाब सरकार के हाथ में हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात के लिए कोि ा ा की है कि सोलूज गेटस का कन्ट्रोल ज्वाइंट रहे वरना अगर हमें पानी मिल भी जायेगा तो पूरा पानी नहीं मिला करेगा। कन्ट्रोल तो उनके हाथ में है इसलिये पंजाब सरकार के अधिकारी जिधर जितना पानी देना चाहेंगे उतना उधर दे देगे।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः कौन से गेटस से इनका मतलब है, मैं समझ नहीं पाया क्योंकि वह तो पूरा एक सिस्टम है। भाखडा का जो मेन हैड वर्क्स है वहां पर बी0बी0एम0बी0 का कन्ट्रोल है। वहीं से वे लोग उसको आपरेट करते हैं।

श्री नेकी रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस नहर की टोटल लम्बाई कितनी है, उसमें से कितनी बन चुकी है और कितनी बननी अभी बाकी है ? जिस दिन इस नहर को बनाने के लिये पैसा मंजूर हुआ था, उस दिन कितना मंजूर हुआ था और आज महंगाई को देखते हुए कितना रूपया बढ गया है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः सर, इस नहर की कुल लम्बाई 120 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर के करीब पर अर्थ वर्क हो चुका है। और बाकी अभी कहीं पर भी अर्थ वर्क नहीं हुआ है। टोटल जितनी वहां पर लाइनिंग होनी है, उसकी अभी तक केवल एक परसैंट लाइनिंग हुई है। बाकी का मोटा मोटा काम जो है, वह इस तरह से है। मेजर क्रौस ड्रेनेज वर्क्क 11 हैं जिनमें से 5 के ऊपर काम चल रहा है मीडियम क्रौस ड्रेनेज वर्क्स 42 हैं इनमें से 6 के ऊपर काम चल रहा है। 4 बिग ब्रिज हैं। ए0आर0 3, रेलवे ब्रिज 8 और डी0आर0 ब्रिज आदि उसमें कई छोटे छोटे काम हैं। इनमें से एक रेलवे ब्रिज पर काम चल रहा है। इस प्रोजैक्ट का रिवाईज्ड एस्टीमैट 270 करोड रूपये का है। उसमें

हरियाणा सरकार ने सैवन्थ फाईव ईयर प्लान में 160 करोड रूपये रखा है। 70 करोड रूपया 1985–86 में और 90 करोड रूपया 1986–87 में है। जैसे मैंने बताया हरियाणा सरकार ने अभी तक 110.5 करोड रूपया नकद दे दिया है इसके मुकाबले में पंजाब सरकार केवल 13 करोड रूपया दिया है जबकि उनका 22 करोड रूपया 1985–86 के अन्त तक देना बनता है।

श्री कंवल सिंहः मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि नहर जो भी डिपार्टमैंट बनाता है, उसके लिये बाकायदा कुछ न कुछ नार्म्ज बने हुए हैं कि कितने उस पर खर्चे आयेंगे। क्या उन नार्म्ज के मुताबिक एस0वाई0एल0 पर रूपया खर्चे हो रहा है या नहीं। अगर नहीं तो क्या हमारी सरकार अपनी ओर से कुछ मौनिटरिंग कर रही है कि जो खर्चा हो रहा है वह जायज हो रहा है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने यह बताया है कि 1985–86 में 70 करोड रूपये और 1986–87 में 90 करोड रूपये की इसके लिये एलोके ान की है। जब इसके लिये पूरा पैसा ही नहीं रखा गया है तो आप इसकी कम्पली ान कैसे करेंगे।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः सर, इनका पहला सवाल खर्च के बारे में है। क्योंकि वह काम कन्टीन्यू कर रहा है और पंजाब सरकार के कायदे के मुताबिक वे उसका आडिट भी करवाते हैं। इसकी मौनिटरिंग हम जरूर कर रहे हैं। मौनिटरिंग हम आडिट की सैंस में नहीं करवाते। यह काम तो पंजाब का है, हरियाणा सरकार का नहीं है। न ही ऐसा पौसीबल होगा कि हम

इस स्टेज पर इस बारे में कुछ करें। फाईनल स्टेज पर हम यह देखेंगे कि जो रूपया खर्च हुआ है, वह ठीक खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। जहां तक फन्डज एलोके ान की बात इन्होंने पूछी है, वह मेरी समझ में नहीं आयी है।

श्री कंवल सिंहः 270 करोड रूपये का आपने एस्टीमैट बताया है। लेकिन आपने इसके लिये सिर्फ 160 करोड रूपया रखा है। बिना पूरे पैसे की एलोके ान के इसको पूरा कैसे करेंगे ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः इसमें पंजाब को भोयर भी आयेगा। इसके अलावा हम और रूपया भी दे सकते हैं। इसके लिये पैसे का और इन्तजाम भी हो सकता है। हमने गवर्नमैंट आफ इंडिया से इस बारे में रिक्वैस्ट बार बार की है और उनकी तरफ से हमें आ वासन भी दिलाया गया है कि जरूरत पडेगी तो वे हमें असिस्टैंस भी देंगे।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, पिछली बार इस नहर की अलाइनैंट के बारे में कुछ झगडा था। पंजाब के फारमर्ज धरने पर बैठे थे कि इसकी अलाइनमैंट ठीक की जाए। पंजाब सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाई थी। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अलाइनमैंट का फैसला हो गया या नहीं ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, पंजाब सरकार ने तो यह अनाऊंस कर दिया था कि वह आलरेडी डिसाइडिड अलाइनमैंट पर स्टिक करती है यानि वह अलाइन्मैंट

चैंज करने के लिए तैयार नहीं है लेकिन हमारी इंफरमे ान है कि फारमर्ज अभी भी ऐजीटेटिड हैं, वे मान नहीं रहे हैं।

श्री अमीर चन्द मक्कड़: क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जहां किसानों ने धरना दिया था, वहां खुदाई का काम भाुरू हो गया है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, जहां पर फारमर्ज बैठे थे वह जमीन ऐक्वायर हो चुकी थी और उसमें खुदाई का काम भाुरू हो गया था और कुछ क्रौस ड्रेनेज वर्क्स थे उनका काम भी भाुरू हो गया था लेकिन फारमर्ज के धरना देने पर वह सस्पैंड हो गया।

श्री निर्मल सिंह: स्पीकर साहब, अखबरों में आया था कि किसान स्टे लेने के लिए कोर्ट में गए थे। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करैंगे कि क्या यह बात सही है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, हमारे पास इस बारे में कोई इत्ताह नहीं है।

चौधरी इन्द्र सिंह नैन: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या सैक ान 4 और सैक ान 6 की कार्यवाही पूरी हो चुकी है और अगर कार्यवाही अधूरी रहती है तो वह कौन से हिस्से की रहती है ?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, टोटल जमीन 380549 एकड एक्वायर करनी थी लेकि 2142.44 एकड जमीन एक्वायर हुई है। 1663.05 एकड एक्वायर करना बाकी रहती है। इसमें से 1572.05 एकड जमीन का सैक ान 6 के तहत नोटिफिके ान हो चुका है। लेकिन अगली कार्यवाही नहीं हुई। 91 एकड जमीन का सैक ान 6 के तहत नोटिफिके ान होना अभी बाकी है।

सेठ राम दास धमीजाः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि एक परसैंट लाइनिंग हुई है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस एक परसैंट लाइनिंग को हम निल समझें क्योंकि एक परसैंट तो कुछ भी नहीं होता ?

श्री अध्यक्षः जो फैक्ट है वही मंत्री महोदय बताएंगे।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि लगभग सत्तर किलोमीटर जो नहर है उसकी खुदाई का काम जारी है। स्पीकर साहब, हमने जो पैसा पंजाब सरकार को दिया वह उसकी डिमान्ड पर दिया। एक स्टेज ऐसी आई थी जब पंजाब गवर्नमैंट ने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि हरियाणा सरकार हमें पैसा नहीं देती। अगर हमें पैसा पूरा दिया जाए तो हम इमिजिएटली निर्माण का कार्य भुरू कर देंगे। हमारी सरकार के मुताबिक हमने पंजाब गवर्नमैंट की डिमान्ड पर पूरा पैसा दे दिया। दूसरी बात हमारे मन्त्री महोदया बार बार कहते हैं और वह

ठीक भी है कि पंजाब गवर्नमैंट को दिया है उसका कांट्रक्ट दे दिया है या नहीं दिया ? दूसरी और बात क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हमारे प्रान्त को, इस हाउस को, और हमारी सरकार को कैसे तसल्ली हो कि जितना पैसा हमने दिया वह ि ाडयूल के मुताबिक खर्च किया गया है या नहीं किया गया ? पंजाब गवर्नमैंट ने आगे कांट्रैक्टस दिए उन पर काम भाुरू हुआ या नहीं हुआ ? 110 करोड रूपया जो हमने दिया उसका ठीक यूटिलाइजे ान हो गया या नहीं हुआ ? जो अनडिसप्यूटिड लैंड हैं, जिस पर कोई झगडा नहीं है और जो ऐक्वायर भी हो चुकी है उस पर काम क्यों नहीं भाुरू करवाया ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, दो सवाल बनते हैं। एक तो इन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने कहा था कि हरियाणा सरकार ने पैसा देना बन्द कर दिया था इसलिए काम नहीं हो सका। दूसरा सवाल यह है कि जो पैसा हमने पंजाब सरकार को दिया उसकी ठीक ऐप्लीके ान हुई है या नहीं हुई है, इस बात की तसल्ली कैसे हो सकती है। स्पीकर साहब, पहले सवाल के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि 1982 में मौजूदा सरकार आने के बाद तक तो रूपया दिया था उसके बारे में हम इस नतीजे पर पहुंचे कि पंजाब सरकार ने एस0वाई0एल0 के लिए इतना टौप हैवी एडमिनिस्ट्रे ान खड़ा कर दिया था जिसमें चीफ इंजीनियर्ज, सैकडों एक्सीयन, एस0डी0ओज0, ओवरसीयर्ज आदि थे। उन्होंने बहुत से व्हिकल्ज खरीद लिए लेकिन उस वक्त तक

जमीन ऐक्वायर नहीं की। तब हमने इस बारे में प्रोटैस्ट किया और फरदर रूपया देना बन्द कर दिया। हमने कहा कि हमने जो रूपया पहले दिया है उसकी ऐप्लीके ान नहर के काम में नहीं हुई बल्कि उस रूपए से टौप हैवी एडमिनिस्ट्रे ान को काफी प्रोन करके कम किया और उसके बाद जैसे जैसे काम चला हम इंस्टालमैंटस में पैसा देते रहे। स्पीकर साहब, बीच में भी जब हमने यह समझा कि काम ठीक नहीं चल रहा है और रूपया हमसे मांग रहे हैं तो हमने उनको कहा कि पहले जमीन ऐक्वायर करो तब हम पैसा देंगे। स्पीकर साहब, 1984 में पंजाब गवर्नर के एडवाइजर श्री सुरेन्द्र नाथ होते थे। उनके साथ हमारी मीटिंग हुई और उन्होंने उस वक्त हमें आ वासन दिया कि जो रूपया हमने दिया है वह लैंड ऐक्वीजी ान पर और नहर के काम पर ही खर्च होगा। उनकी कमिटमैंट पर हमने फिर पैसा दिया। स्पीकर साहब, इस साल पिछले दिनों और ज्यादा रूपया दिया। हमने उनको इस साल में 60–65 करोड रूपया दिया और वह इसलिए दिया कि राजीव लोंगौवाल जो ऐकोर्ड हुआ उमसें नहर की कम्पली ान की डेट का टारगेट 15 अगस्त था। यह नहर 15 अगस्त तक पूरी होनी थी। हम चाहते थे कि वह काम ऐक्सीलरेट हो इसलिए लिबरली फण्ड दिए ताकि वह काम 15 अगस्त तक पूरा हो लेकिन मौके को देखने के बाद और दूसरी रिपोर्टस के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि काम ऐक्सीलरेट नहीं हुआ। स्पीकर साहब, जहां तक रूपए की स्कूरटनी का सम्बन्ध है, अगर पी0ए0सी0 चाहे तो एक एक बात के बारे में तसल्ली कर सकती है। स्पीकर साहब,

पी0ए0सी0 ही एक ऐसा तरीका है जो हाउस को तसल्ली करवा सकती है।

श्री भले रामः अध्यक्ष महोदय, वैस्ट्रन यमुना कैनाल की ब्रांचिज हमारे सोनीपत और रोहतक जिलों में से गुजरती हैं और इन ब्रांचिज का 40 फीसदी पानी लोहारू लिफट इरीगे ान कैनाल व महेन्द्रगढ कैनाल में जाता है। मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब एस0वाई0एल0 नहर बनकर तैयार हो जाएगी तो उसमें हमारा जो 40 फीसदी पानी का भोयर है, वह रेस्टोर कर देंगे या नहीं ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः सर, चौधरी भले राम जी किस 40 परसैंट पानी के हिस्से की बात कर रहे हैं, इसका मुझे नहीं पता कि किस का पानी काटकर किस तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन मैं इनको इतना बता देता हूं कि जब एस0वाई0एल0 का पानी आएगा तो रोहतक, सोनीपत को भी मिलेगा, लिफट इरीगे ान स्कीम्ज को भी दिया जाएगा बल्कि सारे हरियाणा में इसका पानी जाएगा।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरा दूसरा सवाल स्पश्अ था कि हरियाणा सरकार पंजाब सरकार को इस नहर के कंस्ट्रक ान वर्क के लिए या दूसरी जरूरी म ाीनरी खरीदने के लिए जो पैसा दे रही है, क्या सरकार को इससे पूरी सन्तुश्टि है

कि वह पैसा उसी काम पर खर्च हो रहा है जिस काम के लिए दिया गया है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार की सन्तुश्टि या असन्तुश्टि का प्र न नहीं है। यह एक रनिंग प्रोजैक्ट है जिसके लिए एडवान्स पैसा दिया जाता है। कई तरह की म ीनरी खरीदनी होती है, मैटीरियल खरीदना होता है और दूसरी जरूरी चीजें खरीदनी होती हैं। सन्तुश्टि का समय जब आएगा तो सरकार इसके लिए पूरी स्करूटनी करेगी लेकिन अभी इसका समय नहीं आया है।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, फर्ज करो इस नहर के निर्माण का काम भारत सरकार अपने हाथ में ले लेती है या कोई दूसरी एजैन्सी ले लेती है और इस नहर के निर्माण के लिए पूरी मैन पावर म ीनरी वगैरह तथा दूसरी सभी सहूलतें मुहैया कर दी जाती हैं, तो क्या सरकार इस नहर को 15 अगस्त 1986 तक मुकम्मल करवा देगी या नहीं ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से इस नहर का 15 अगस्त 1986 तक मुकम्मल होना नामुमकिन है क्योंकि कई बडे बडे काम जैसे क्रास ब्रिजिज बनाये जाने हैं। चूंकि पिछले चार पांच प्रि ियस महीनों में उतनी तेजी से इस नहर का काम नहीं हुआ जितनी तेजी से होना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं यह कह सकता हूं कि अगर राईट अरनैस्टनैस

और तेजी से नहर का काम भाुरू हो जाए तो इस साल नहर बनकर तैयार हो सकती है और हरियाणा को पानी मिल सकता है।

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैम्बर साहेबान ही सवाल पूछ सकते हैं लेकिन रूल्ज आफ प्रोसीजर के रूल्ज 40 से 56 तक इस बात की कहीं मनाही भी नहीं है कि कोई मिनिस्टर सवाल न पूछ सके। इसलिए मैं आपसे इसकी परमि ान चाहता हूं।

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमें हरियाणा के हिस्से का जो 3.5 एम0ए0एफ0 पानी मिलना था, आया यह नहर 3.5 एम0ए0एफ0 पानी ले आएगी ? दूसरे अब जो पानी हमें भाखड़ा कैनाल से मिल रहा है, वह कितना मिल रहा है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो हम मौजूदा कपैसिटी के मुताबिक 1.9 एम0ए0एफ0 पानी ले सके हैं लेकिन जो चैनल बन रहा है उसके बाद हम अपने हिस्से का पूरा पानी 3.5 एम0ए0एफ0 ले सकेंगे।

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह तो बता दिया कि 3.5 एम0ए0एफ0 की बजाए 1.9 एम0ए0एफ0 पानी अब मिल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस नहर की लम्बाई कितनी है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः इसकी लम्बाई 120 किलोमीटर है।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह एस0वाई0एल0 का मामला बडा ही सीरियस है लेकिन नेहरा साहब ने अभी जो कुछ पूछा उसको सुनकर मुझे बडा दुःख हुआ कि एक मंत्री महोदय ने दूसरे मंत्री साहेबान को कन्फीडैंस में नहीं लिया। मंत्री महोदय यह पूछ रहे हैं कि नहर की लम्बाई कितनी है। अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री महोदय को अगर सरकार की कारगुजारी का नहीं पता तो अच्छा नहीं लगता कि वे यहां हाउस में किसी बात के बारे में पूछें।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी मिनिस्टर को कन्फीडैंस में नहीं ले रहे हैं। मिनिस्टर्ज तो स्वयं सरकार की हैं, उनको कन्फीडैंस में किसने लेना है, वे तो सब कुछ जानते ही हैं।

Ch. Surrender Singh: It means that the Governmnet does not know anything.

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है सरकार सब कुछ जानती है।

श्रीमती भाारदा रानीः अध्यक्ष महोदय, एस0वाई0एल0 बनने में अभी तो बडा झमेला है। मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहती हूं कि जब यह नहर बनकर तैयार हो जाएगी उस

समय हमारे हिस्से का 3.5 एम0ए0एफ0 पानी तो मिलेगा ही उसमें से फरीदाबाद के हिस्से में कुछ आयेगा या नहीं ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः फरीदाबाद जिले की जो नहर है, उनको आगरा कैनाल से पानी मिलता है लेकिन गुडगांव कैनाल को इससे अव य पानी मिलेगा। इस नहर के बनने के बाद कितना पानी फरीदाबाद जिले को मिलेगा, इस बारे में अभी आफ हैन्ड नहीं बताया जा सकता।

बहिन भाान्ति देवीः अध्यक्ष महोदय, मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहती हूं कि इस निर्माणाधीन नहर के रास्ते में जो चार पांच रेलवे ओवर ब्रिजिज पडते हैं। क्या उनके मामले में भारत सरकार से बातचीत हो गई है ? वे ब्रिजिज बनने भाुरू हो गये हैं या अभी भारत सरकार से अनुरोध ही कर रखा है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः अध्यक्ष महोदय, इस नहर पर तीन रेलवे ओवर ब्रिजिज बनने हैं और इस बारे में रेलवे मिनिस्टरी से कौरसपौंडैंस भी हुई है। रेलवे मिनिस्टर इस काम के लिए बडे ही कीन हैं। पंजाब सरकार को उनहोंने सीधा लिखा था और पहले जो गवर्नर थे, उनको भी इस बारे में लिखा था। उनकी तरफ से कोई देर नहीं है। एक रेलवे ब्रिज पर काम भाुरू हो चुका है। पंजाब सरकार ने पैसा दे दिया है लेकिन थोड़ा दिया है। हमें सूचना मिली है कि पंजाब सरकार ने चार साढ़े चार करोड रूपया रेलवे मिनिस्टरी के पास डिपोजिट करवा दिया है।

तारांकित प्र न संख्या 1055

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री राम बिलास भार्मा, सदन में उपस्थित नहीं थे।

तारांकित प्र न संख्या 1096

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य मास्टर ि ाव प्रसाद तथा श्री फतेह चन्द विज, सदन में उपस्थित नहीं थे।

Widening of Ambala Jagadhri Road

***1090. Seth Ram Dass Dhamija:** Will the Minister for Public Works (B&R) be pleased to state-

(a) whether any decision has been taken to widen the Ambala Jagadhri road into 4 lanes form Howard Circus to Tangri bridge; and

(b) whether any funds have been provided for the widening of the said road and the time by which the said road is likely to be widened ?

Public Works Minister (Sh. Amar Singh):

(a) No.

(b) In view of (a) above, question does not arise.

सेठ राम दास धमीजाः अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने मेरे सवाल पार्ट (ए) के उत्तर में केवल 'नो' कह कर टाल दिया

है। यह एक ऐसी घनी आबादी वाली सडक है कि इसको चौडा करके फोरलेन बनाने का प्रंबन्ध किया जाना चाहिये। इस सडक पर रात दिन बहुत ज्यादा आवाजावी रहती है और रोज ही कोई न कोई ऐक्सीडैंट होता रहता है। इस सडके के ऊपर ओरिएंटल साइंटिफिक आप्रेटस का कारखाना है जिसमें 600 के लगभग वर्कर काम करते हैं। इसके इलावा डी0ए0वी0 स्कूल है, एस0डी0 कालेज है, सनातन धर्म की सभी 11 संस्थाएं और एस0डी0 भारतीय पब्लिक स्कूल विद्यामान है। यह सडक इस घनी आबादी वाले एरिया में से गुजर रही है। मैं हैरान हूं कि सरकार गैर जरूरी जगहौं पर तो पैसा खर्च कर रही है लेकिन जहां पैसा खर्च करने का लाभ हो सकता है, वहां सरकार की तरफ से पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। मैं आपके द्वारा सरकार से जानना चाहूंगा कि अगर फोरलेन बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत है तो उस सडक को थ्री लेन ही बना दिया जाए ताकि आने जाने में लोगों को न तो किसी प्रकार की दिक्कत हो और न ही रोज एक्सीडैंट हों।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, अम्बाला जगाधरी रोड 52.14 किलोमीटर लम्बी है। आनरेबल मैम्बर ने पूछा है कि हावरड सर्कस से टांगरी पुल तक इस सडक को फोर लेन किया जायेगा या नहीं। मैंने बताया है कि नहीं। पहले इन्होंने कहा था कि इस रोड को अम्बाला कैन्टोनमैंट बोर्ड से पी0डब्ल्यू0डी0 ले। यह रोड 27–2–84 को पी0डब्ल्यू0डभ्0 के अन्डर आ गई थी और उसके बाद 31–1–86 तक इस पर 518847 रूपये खर्च हो चुके हैं। सबसे

पहले इसकी रिपेयरिंग करवाई गई। अब हम इनकी मांग को ध्यान में रखते हुए और हैवी ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए इस सडक को 30 फुट चौडी करने जा रहे हैं। यह मामला हमारे विचाराधीन है और अगले फाइनैंि ायल ईयर में काम भुरू करवा देंगे।

चौधरी फूल चन्दः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने अपने जवाब में फोर लेन बनाने के लिए तो कहा कि 'जी नहीं' लेकिन अभी जवाब में कह दिया, विचारधीन है, अगले साल में बना देंगे। अम्बाला जगाधीर रोड इंटर स्टेट रोड है। इधर हमें यू0पी0 से मिलाती है और उधर पांजब से मिलाती है। क्या इस सड़क को नै ानल हाई वे करार दे दिया गया है, अगर नहीं तो कब तक दे दिया जाएगा ?

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, यह सडक स्टेट हाई वे है, ने ानल हाई वे बनाने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। जहां तक आनरेबल मैम्बर ने फोर लेन बनाने के लिए पूछा, उस पर 37 लाख रूपए खर्च होंगे लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। पैसे के अभाव से हम अभी फोर लेन बनाने पर खर्च नहीं कर सकते। फिलहाल हम इसको 30 फुट चौडी बना रहे हैं। अगले फाइनैंि ायल ईयर में मैंने 30 फुट सडक चौकी करने के लिए कहा था न कि फोर लेन बनाने के लिए कहा था। अगले साल में भी तक भुरू कर पाएंगे अगर हमें कोई रूकावट न आई। जैसे रास्ते में टैलीफोन के खम्बे आ जाते हैं उनको हटाना होता है।

इसलिए संबंधित महकमे को कंफिडैंस में लेकर और उनसे सारी बातें तय करके अगले साल काम भ्रारू करवाएंगे।

चौधरी इन्द्र सिंह नैनः स्पीकर साहब, आज आपका सप्लीमैंटरी पूछने के बारे में लिब्रल एटीच्यूड है। मेरा क्वै चन डायरैक्टली तो इस क्वै चन से लिंकड नहीं है लेकिन इसी महकमे से संबंधित है। मैं इसे पब्लिक इंट्रैस्ट में पूछना चाहता हूं। जो नई सडकें बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, वह तो ठीक है, लेकिन जो इनकी मैंटीनैंस की बात है, वह ठीक नहीं है। सड़क के दोनों तरफ से जब मिटटी हट जाती है तो सडक कट जाती है। हम जब बरवाला से गुजरते हैं तो देखते हैं कि वहां जो सडक है वह सारी टूटी पडी है। क्या मंत्री जी ऐसी सडकों को ठीक करवाएंगे ? इसी तरह से कापडो बनमोरी की लिंक रोड है जो मेरे हल्के में पडती है। इसकी एडमिनिस्ट्रैटिव और टैक्नीकल एप्रूवल हो चुकी है। इस बारे में मैं मन्त्री महोदय से कई बार मिल भी चुका हूं और लिख कर भी दे चुका हूं। क्या उस पर जल्दी काम भ्रारू करवाएंगे ? इसी तरह से मेरे हल्के में हसनगढ कल्लर भैनी रोड पर अर्थ वर्क हो चुका है, क्या उस पर भी जल्दी काम भ्रारू करवा देंगे ?

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि सडकों की मैंटीनैंस के लिए हमारे पास पैसा बहुत कम है जिसकी वजह से रिपेयरिंग का काम बहुत हद तक नहीं हो पाता। इस काम के लिए 1985–86 में हमें 12 करोड रूपया मिला है जबकि

हमें 33 करोड रूपए की जरूरत है। फिर भी हमने कोि ा ा की है कि ज्यादा से ज्यादा रोडज की मैंटीनैंस हो। जिन सडकों के बारे में आनरेबल मैम्बर ने पूछा है, उनके बाकायदा एस्टीमैंटस तैयार करवाए जा रहे हैं, हम उनकी रिपैयर का भी ध्यान रखेंगे।

श्री बृज मोहनः क्या मंत्री जी, जी0टी0 रोड को छोड कर, हरियाणा की किसी एक रोड का नाम बताएंगे जो अच्छी हो ?

श्री अमर सिंहः मैंबर साहब किसी एक रोड का नाम बता दें, जो खराब हो।

श्री बृज मोहनः स्पीकर साहब, जीन्द से गोहाना, जीन्द से सफीदों, जीन्द से कैथल और जीन्द से करनाल वाली सडकी की वर्स्ट हालत है। दूसरी बात यह है कि कुछ महीने पहले मैंने अपने हल्के की एक एक किलोमीटर की कुछ सडकों के बारे में मन्त्री मोदय को बताया था। उनके एस्टीमैंटस भी अब तक एक्सीयन से नहीं मंगवाए हैं। हम जब भी इनसे मिलते हैं तो कह देते हैं कि एस्टीमैंटस मंगवा रखे हैं।

श्री अमर सिंहः आनरेबल मैंबर ने कहा कि कुछ सडकों के एस्टीमैटस अभी नहीं मंगवाए हैं, हम उस पर कार्यवाही कर रहे हैं। इन्होंने मुझे लिखा था कि सड़कों पर ठीक तरह से काम नहीं हो रहा है लेकिन यह नहीं बताते कि क्या ठीक नहीं हो रहा है। जहां तक रोडज की हालत खराब होने का संबंध है, आनरेबल

मैंबर दूसरे प्रान्तों में जाकर देखें, फिर पता चलेगा कि हरियाणा की सडकें कितनी बढिया हैं। यह ठीक है कि हमारी स्पैसिफिके ान के मुताबिक ये सडकें और बढिया होनी चाहिएं लेकिन दूसरे सूबों की बैस्ट सडकों से हमारी वर्स्ट सडकें बढिया हैं। इन्होंने जो दो तीन रोडज बताई थीं, उनके एस्टीमेटस हमने मंगवा रखे हैं, पैसा होते ही उन पर काम करवा देंगे।

श्री नेकी रामः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हल्का रतिया में जो पीछे काम भुरू हुआ था, वह अधूरा पडा है। रंगोई नाले के ऊपर दो पुल हैं (विघ्न) अब यह बताना मु ि कल है कि उन पुलों को कौन बना रहा है। (हंसी) मैं जानना चाहता हूं कि इनको कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, एक दिन मैंबर साहब ने मेरे को बताया कि इनके हल्के में दो ड्रेनेज के ब्रिज बनने हैं। मैंने इनसे पूछा कि कौन सा महकमा बना रहा है, क्योंकि पी0डब्लयू0डी0 तो ड्रेनेज के पुल बनाता नहीं है।

श्री नेकी रामः स्पीकर साहब, ये पूछ रहे हैं कि कौन सा महकमा बना रहा है, इसका जवाब तो आप इनसे दिलवाएं।

श्री अध्यक्षः चौधरी साहब, ऐसे पुल इरीगे ान महकमा बनाता है।

चौधरी लीला कृश्णः स्पीकर साहब, हरियाणा के अन्दर जो पांच पांच किलोमीटर के लिंक रोडज हैं, वे पूरे नहीं बने हैं। कहीं पर आधा किलोमीटरी और कहीं पर एक किलोमीटर का टुकडा बनना बाकी रहता है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन अधूरे लिंक रोडज को बनाने के लिए सरकार प्रायर्टी देगी ?

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि इस तरह से जो लिंक रोडज अधूरे पडे हुए हैं, उनको पूरा कर दिया जाए। वे सारी सडकें सर्कल वाइज और डिवीजन वाइज पूरी करवाएंगे।

चौधरी दिलू राम बाजीगरः स्पीकर साहब, चौधरी बंसी लाल जी के टाईम पर कुछ ऐसी सडकें बनाई गई थीं जो गांवों के लाल डोरे के पास छोड दी गई थीं, ऐसी सडकें तकरीबन सारे हरियाणा के अन्दर ही होंगी। मेरे हल्के में लगभग सभी गांवों की सडकें लाल डोरे के पास छोडी हुई हैं यायनि फिरनी तक बनाई हुई हैं। जो लाल डोरा होता है वह गांव से लगभग एक या आधा किलोमीटर की दूरी पर होता है। गांव से इतनी दूर सडक होने से गांव वालों को उसका कोई फायदा नहीं है। वे सडकें न तो स्कूलों तक पहुंची हैं, न ही हरिजन बस्तियों तक पहुंची हैं तथा न ही मंदिर गुरूद्वारों तक पहुंची हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी जानना चाहता हूं कि क्या उन सडकों को जल्दी ही बनवाने की कृपा करेंगे ताकि गांव वालों को कोई दिक्कत न हो ?

श्री अध्यक्षः आपकी बात तो सरकार ने पहले ही मानी हुई है।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार ने पहले ही यह फैसला लिया हुआ है कि जो रोडज लाल डोरे से बाहर हैं, उनको स्कूल, डिस्पैंसरी और हौस्पिटल तक बनाया जाए, लेकिन यह काम एक दिन का नहीं है। इस प्रकार की रोडज लगभग 955 किलोमीटर लम्बी बनानी हैं और उस पर 24 करोड रूपए खर्च होंगे। ज्यों ज्यों हमारे पास धन की उपलब्धि होती जा रही है, हम यह काम करते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर की आपसे यहय रिक्वैस्ट है कि आप कुरूक्षेत्र जिले की तरफ ज्यादा ध्यान दें और हिसार और भिवानी जिलों की तरफ जरा कम ध्यान दें।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, जहां तक माननीय सदस्य के हलके की बात है, मैंने खुद जाकर इनका हलका देखा है। सारे हरियाणा के दूसरे हलकों से इनके हलके में ज्यादा रोडज बनी हुई है।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया कि रोडज की रिपेयर के लिए पैसा कम होने की वजह से इस साल केवल 12 करोड रूपए ही दे पाए। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसी नीति नहीं बना सकती कि जब तक पुरानी रोडज की रिपेयर नहीं कर दी जाती तब तक एक

आध बहुत जरूरी रोड को छोड कर नई सडकें नहीं बनाई जाएंगी ताकि वे सडकें मोटरेवल तो रहें। अगर सडक खराब हो तो गाडियों के टायर साहब होते हैं क्योंकि रोडज पर बडे बडे रोडे पडे होते हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार रोडज की मेंटीनैंस के लिए ज्यादा पैसा देने के लिए विचार करेगी ?

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, आनरेबल मैंम्बर का सुझाव बहुत बढिया है। नई सडकें भी बनेंगी और उसके साथ साथ पुरानी सडकों की मैंटीनैंस की तरफ भी पूरा ध्यान दिया जाएगा।

मास्टर राम सिंहः स्पीकर साहब, सहारनपुर, जमनानगर, रादौर और कुरूक्षेत्र की सडक स्टेट हाईवे है जिसको एस0के0 रोड भी कहते हैं। इस रोड पर बहुत नैरा ब्रिज बने हुए हैं जिनके ऊपर से एक व्हीकल बहुत ही मु कल से गुजर सकता है। इसलिए उन पर एक्सीडैंटस बहुत होते रहते हैं। अभी पिछले दिनों धुंध के कारण एक नैरो ब्रिज पर एक एक्सीडैंट हुआ जिसके कारण वहां पर ट्रैफिक जाम हो गया। काजलों, जोबल और रादौर गांव जमना नगर कुरूक्षेत्र रोड पर हैं। इन गांवों के पास एक नैरो ब्रिज है जिसके ऊपर से दो व्हीकल इकट्ठे पास नहीं हो सकते। जो गन्ने से लदे हुए ट्रैक होते हैं उनका ऐक्सीडैंट हो जाता है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उन नैरो ब्रिजिज के कब तक चौडा करवा दिया जाएगा।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि धुंध के कारण तो ऐक्सीडैंट कहीं पर भी हो सकता है।

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैंम्बर के कहने का मतलब यह है कि उन गांवों के पास जो सडक पर पुल बने हुए हैं वे बहुत छोटें हैं और रोड बडी हैं इसलिए अंधेरे की वजह से वहां पर ऐक्सीडैंट हो जाते हैं।

श्री अमर सिंहः माननीय सदस्य इस बारे में लिख कर भेज दें, हम जांच पडताल करवा लेंगे।

चौधरी अजमत खांः स्पीकर साहब, जिस समय गुड़गांव कैनाल बनाई गई थी, उस समय उस पर पुल तामीर हुए थे और उस कैनाल की माइनर्ज पर भी पुल तामीरी हुए थे। उसके बाद जब सडकें बनाई गई तो उन्हीं पुलों को काम में लिया गया है। जो सडकें बनाई गई हैं, वे नेहर की अलाइनमैंट के हिसाब से गलत हैं और वे पुल टेढे हैं जिसके कारण उन पर एक्सीडैंटस होते रहते हैं और नहर के अन्दर ऊंट गडडे गिर जाते हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे पुल मेवात से एरिया में हैं, उनको दोबारा बनवाया जाए ताकि लोग एक्सीडैंटस से बच सकें।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, माननीय सदस्य इस बारे में लिख कर के भेज दैं। हम उसकी जांच पडताल करवा लेंगे और अगर जरूरत हुई तो उस बारें में विचार कर लेंगे।

चौधरी फूल चन्दः स्पीकर साहब, यह सवाल तो अम्बाला जगाधरी सडक को चौडी करके फोर लेन बनानेके बारे में था लेकिन आपकी बडी अनुकम्पा है कि आपने सारे हरियाणा की सडकों के बारे में सप्लीमैंटरीज पूछने के लिए लिबर्टी दी है। स्पीकर साहब, यह बडी खु ाी की बात है हरियाणा के हर गांव को सडक के साथ जोड दिया गया है लेकिर मेरे हलके में दो ऐसें बदकिस्मत गांव हैं जिनको अभी तक सडक से नहीं जोडा गया है। स्पीकर साहब, अम्बाला जिले में रैवैन्य एस्टेट से सम्बन्धित सहला गांव नम्बर वन है। इस गांव को सडके के साथ न जोडने का एक कारण यह है कि इसके बीच में नदी पडती है। लेकिन मैं इस बारे में सरकार को सुझाव दूंगा कि इस गांव को सढौरा और अराइंवाला गांव की सडक के साथ जोडा जा सकता है, यदि उस सडके के साथ इस गांव को जोडा जाए तो बची में कोई नदी नहीं पडती। इसी तरह से एक साहबापुर गांव है जिसको अभी तक सडक के साथ नहीं जोडा गया है। इस सडक के बारे में केस अदालत में है, लेकिन मैं इस बारे में सरकार को सुझाव दूंगा कि इसकी अलाइनमैंट के बारे में अदालत में जो केस चल रहा है, उस मामले को छोड कर इस गांव को गोला गांव से

जोडने की कृपा करें क्योंकि इसके लिए लैंड एक्वायर करने की भी जरूरत नहीं है।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने दो गांवों की सडकों के बारे में सवाल पूछा है। उसमें से एक गांव की सडक के बारे में तो आनरेबल मैम्बर ने खुद स्वीकार किया है कि उसका केस अदालत में चल रहा है, इसलिए वह सडक नहीं बन पाई। दूसरा सवाल इन्होंने यह किया है कि उस गांव की सडक की अलाइनमैंट को चेंज कर दिया जाए। स्पीकर साहब, आप बडे लरनड वकील रहे हैं आप जानते हैं कि एक बार यदि अलाइनमैंट बन जाए तो वह सारे गांव की राय से ही चेंज की जा सकती है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि आप सारे गांव की तरफ से प्रस्ताव लाएं और उसको रिकमैंड कर दें। हम उस पर बाकायदा एक ान लेंगे और उन गांवौं को भी सडक से जोडेंगे।

श्री भल रामः स्पीकर साहब, पिछली बार हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि जो 40 फीसदी पैसा मार्किट कमेटियों ने सरकार के पास जमा करवाया है, उससे सडकों का काम करवाया जाएगा। हरियाणा के अन्दर बहुत सी ऐसी सडकें हैं जिनको बनाने के लिए मिटटी डालने का काम पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक उन पर बजरी वगैरह नहीं पडी है। वह मिटटी बरसात में बह जाएगी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी सडकों को जल्दी बनवाने की कृपा करेंगे ताकि वह मिटटी बरसात में न बह जाए ?

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, हम चौधरी भले राम जी की मिटटी नहीं बहने देंगे। (हांसी) बाकायदा उन रोडज का ध्यान रखेंगे जिन पर मिटटी का काम हो चुका है। चौधरी भले राम जी रोड रोलर का काम खुद ही करते हैं, मिटटी कहां बह जाएगी। माननीय सदस्य मुझे रोडज के नाम लिख कर के भेज दें, हम उस बारे में विचार करेंगे।

सेठ राम दास धमीजाः स्पीकर साहब, 5 दिसम्बर 1983 को चीफ मिनिस्टर साहब अम्बाला कैंट में यह एलान करके आये थे कि इस सडक को फोरलेन बनवाएंगे। हरियाणा सरकार का यह फैसला भी था कि इस साल हर हल्के में पांच पांच किलोमीटर सडकें बनाई जाएंगी लेकिन अम्बाला कैंट में एक इंच भी सडक नहीं बनी है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी ने अम्बाला कैंट की सडक को 30 फुट चौडी करने का जो वायदा किया है, उसको अगले साल में ही पूरा करें ताकि वहां पर ऐक्सीडैंट न हों।

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, मैंने माननीय सदस्य की पहले ही तसल्ली कर दी है कि जो एस0डी0 स्कूल तक सडक है उसकी वाइडनिंग करने पर 1 लाख 37 हजार 300 रूपए खर्च होंगे। उस सड़क को 22 फुट से 30 फुट तक चौडा करना है और दूसरी तरफ रोड पर लगभग 10 लाख रूपए खर्च होंगे। इस बारे में नैक्स्ट फाइनैंि ायल ईयर में एस्टीमैटस बना कर हम काम भाुरू करवा देंगे।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट

15.00 बजे।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब मैं वेरियस बिजनैस के बारे मैं बिजनैस एडवाइजरी कमेटी द्वारा फिक्स किया गया टाईम टेबल रिपोर्ट करता हूं–

"The Committee met at 12.15 P.M., on Tuesday, the 18tlh February, 1986, in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and adjourn at 6-30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put.

(i) On Tuesday, the 25th February, 1986, the Assembly shall meet at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M.

(ii) On Wednesday, the 26th February, 1986 there shall be two sittings of the Assembly i.e. first sitting from 9.30 A.M. to 1.30 P.M. and the second sitting from 2.00 P.M. to 6.30 P.M.

(iii) ON Friday, the 28th February, 1986 the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn after the conclusion of the business entered on the list of Business for the day.

The Committee, after some discussion, also recommends that the business from 19th February to 21st February, 1986 and 25th February to 28th February, 1986, be transacted by the Sabha as follows-

Wednesday, the 19th February, 1986 (2.00 P.M.)	1	Question Hour.
	2	Presentation and adoption of the Second Report of the Business Advisory Committee.
	3	Presentation of Supplementary Estimates (Second Installment) 1985-86 and the Report of the Estimate Committee thereon.
	4	Leave to introduce and introduction of Government Bills.
	5	Resumption of discussion on Governor's Address and voting on Motion of Thanks.
Thursday, the 20th February, 1986 (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Non Official Business
Friday, the 21st	1	Question Hour.

February 1986 (9.30 A.M.)		
	2	Papers to be laid/re-laid on the Table of the House, if any.
	3	Discussion and voting on Supplementary Estimates.
Saturday, the 22nd February, 1986		Off day,
Sunday, the 23rd February, 1986		Holiday
Monday, the 24th February, 1986		Holiday
Tuesday, the 25th February 19867 (200 P.M.)	1	Question Hour.
	2	Presentation of Budget for the year 1986-87
Wednesday, the 26th February 1986 (9.30 A.M.) (First Sitting)	1	Question Hour.
	2	Leave to introduce and introdutopm pf Government Bills, if any.
	3	General Discussion on Budget

		for the year 1986-87
Wednesday, the 26th February 1986 (2.00 P.M.) (Second Sitting)	1	Motion under rule 30 regarding transaction of Government business on Thursday, the 27th February, 1986.
	2	Resemption of general discussion on Budget for the year 1986-87 and reply by the Finance Minister.
Thursday, the 27th February, 1986 (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Discussion and voting on Demands for grants on Budget for the year 198687.
Friday, the 28th February, 1986 (9.30 A.M.)	1	Question Hour.
	2	Motion under rule 15 regarding non-stop sitting.
	3	Motion under rule 16 regarding adjournment of the Sabha Sine die.
	4	Presentatiton of Reports of the Assembly Committees, if any.

	5	The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates (Second Instalment) 1985-86.
	6	The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget for the year 198687.
	7	Legislative Business.
	8	Any other Business, if any."

अब मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि यह हाउस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट में दी गई रिकोमैंडे ांज से सहमति प्रकट करता है।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Speaker, Sir, I beg to move-

That this house agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पे ा हुआ–

कि यह हाउस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट में दी गई रिकोमैंडे ान्ज से सहमति प्रकट करता है।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह (तो ाम): अध्यक्ष महोदय, 26 तारीख को डबल सिटिंग रखी गई है। इस बारे में मेरी रिक्वैट है

कि उस दिन डबल सिटिंग रखने की बजाये किसी नौन औफि ियल डे को औफि ियल डे में कनवर्ट कर लिया जाये ताकि उस दिन काम का अधिक भार भी न रहे।

श्री अध्यक्षः आपने देखा होगा कि टाईम टेबल के हिसाब से 2 नौन औफि ियल डै बनते हैं। उनमें से एक नौन औफि ियल डे को पहले ही औफि ियल डे में कनवर्ट कर दिया गया है।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः यदि संभव हो तो किसी नैक्सट मनडे को डबल सिटिंग वाला बिजनैस टेकअप कर लिया जाये।

श्री अध्यक्ष्ज्ञः आपको सारी बातों का पता ही है कि किस वजह से यह टाईम टेबल चेन्ज किया गया है।

प्र न है–

कि यह हाउस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट में दी गई रिकोमैंडे ान्ज से सहमति प्रकट करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भले रामः अध्यक्ष महोदय, मेरी एक रिक्वैस्ट है कि कल क्वै चन आवर के दौरान रूलिंग पार्टी के सदस्यों के सवाल नहीं हैं। यदि आपकी इजाजत हो तो कल के लिए क्या हम दो चार सवाल पूछने के लिए आज दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्षः कल सवाल तो होंगे।

श्री भले रामः कल जो सवाल लिस्ट पर आएंगे वे रूलिंग पार्टी के मैम्बरों के नहीं हैं। सारे सवाल अपोजी ान पार्टी वालों के हैं। वे सदन में आएंगे नहीं जिसकी वजह से कल सवाल नहीं पूछे जा सकेंगे।

श्री अध्यक्षः कल की लिस्ट पर रूलिंग पार्टी के मैंम्बरों के भी सवाल हैं। हम आपको पूरा बिजी रखेंगे। (हंसी)

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, कल मुख्य मंत्री जी दिल्ली गऐ थें यदि पब्लिक इन्ट्रैस्ट के खिलाफ कोई बात न हो तो दोनों चीफ मिनिस्टरों में जो बातचीत हुइ है उसका ब्यौरा सदन में दे दें।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): इस बारे में, मैं गवर्नर एड्रैस पर जवाब देते समय बता दूंगा।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः ठीक है।

वर्श 1985–86 के लिए सप्लीमैंटरी (दूसरी कि त) पे ा करना

श्री अध्यक्षः अब फाईनैंस मिनिस्टर साहब, वर्श 1985–86 के सप्लीमैंटस (सैकिन्ड इंस्टालमैंट) प्रजैन्ट करेंगे।

Finance Minister (Sh. Sagar Ram Gupta): Sir, I beg to present to this August House the Supplementary Estimates (Second Instalment) 1985-86.

ऐस्टीमैटस कमेटी की वर्श 1985–86 के सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेटस (दूसरी कि त) पर रिपोर्ट पे ा करना

श्री अध्यक्षः अब चौधरी कुन्दल लाल, मैम्बर ऐस्टीमैटस कमेटी, वर्श 1985–86 के सप्लीमैंटरी ऐस्टीमैटस (सैकिण्ड इंस्टालमैंट) पर कमेटी की रिपोर्ट प्रजैन्ट करैंगे।

चौधरी कुन्दन लाल (मैम्बर, ऐस्टीमेटस कमेटीः सर, मैं 1985–86 के अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय कि त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

बिल्ज (इन्ट्रोडयूस्ड–सदन की अनुमति से)

(1) दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज (अमैंडमैंट) बिल, 1986

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब, दि हरियाणा को–आप्रेटिव सोसाइटीज (अमैंडमैंट) बिल, 1986 को इंट्रोडयूस करने के लिए हाउस से परमि ान लेंगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That leave be granted to introduce the Haryana Cooperative Societies (Amendment) Bill, 1986.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पे ा हुआ कि–

दि हरियाणा को आप्रेटिव सोसाइटीज (अमैंडमैंट) बिल, 1986 को इंट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि–

दि हरियाणा को आप्रेटिव सोसाइटीज (अमैंडमैंट) बिल, 1986 को इंट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब बिल इन्ट्रोडयूस करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I introduce the Bill.

(2) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एंड वैलीडे ान) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब, दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एवं वैलिडे ान) बिल, 1986 को इंट्रोडयूस करने के लिए हाउस से परमि ान लेंगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That leave be granted to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill, 1986.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पे ा हुआ कि–

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एवं वैलिडे ान) बिल, 1986 को इंट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एवं वैलिडे ान) बिल, 1986 को इंट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब बिल इन्ट्रोडयूस करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I introduce the Bill.

(3) दि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमी ान (एडी ानल फंक ंज) अमैंडमैंट बिल, 1986

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब, दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एवं वैलिडे ान) बिल, 1986 को इंट्रोडयूस करने के लिए हाउस से परमि ान लेंगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That leave be granted to introduce the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Bill, 1986.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पे ा हुआ कि–

दि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमी ान (ऐडी ानल फंक ांज) अमैंडमैंट बिल, 1986 को इंट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि–

दि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमी ान (ऐडी ानल फंक ांज) अमैंडमैंट बिल, 1986 को इंट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब बिल इन्ट्रोडयूस करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I introduce the Bill.

(4) दि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब, दि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1986को इंट्रोडयूस करने के लिए हाउस से परमि ान लेंगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That leave be granted to introduce the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill, 1986.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पे ा हुआ कि–

दि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1986 को इंट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि–

दि महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1986 को इंट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब बिल इन्ट्रोडयूस करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I introduce the Bill.

(5) दि हरियाणा पब्लिक प्रिमिसिज एंड लैंड (एविक ान एंड रैंट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल, 1986

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब, दि हरियाणा पब्लिक प्रिमिसिज एंड लैंड (एविक ान एंड रैंट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल, 1986 को इंट्रोडयूस करने के लिए हाउस से परमि ान लेंगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That leave be granted to introduce the Haryana Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Bill, 1986.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पे ा हुआ कि–

दि हरियाणा पब्लिक प्रिमिसिज एंड लैंड (एविक ान एंड रैंट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल, 1986 को इंट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाये।

श्री अध्यक्षः प्र न है कि–

दि हरियाणा पब्लिक प्रिमिसिज एंड लैंड (एविक ान एंड रैंट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल, 1986 को इंट्रोडयूस करने की परमि ान दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब बिल इन्ट्रोडयूस करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I introduce the Bill.

राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्षः अब गवर्नर ऐड्रैस पर डिस्क ान रिज्यूम होगी। कल श्री अमीर चन्द मक्कड़ बोल रहे थे। वे कृपया अपनी स्पीच कन्टीन्यू करें।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी): अध्यक्ष महोदय, मैं कल सरकार से प्रार्थना कर रहा था, कि मार्किट कमेटी का जो एक परसैंट सैस लगाया गया था वह सारा व्यापारियों की जेब में गया है। व्यापारी तो हमे ाा अपनी पडत से माल खरीदते हैं। वह सैस या तो किसान को मिलना चाहिए या सरकार उसे अपने फंड में

जमा करवाए। उसका व्यापारियों की जेब में जाना नाजायज बात है।

अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब ने अपने अभिभाशण में लेबर के बारे में भी जिक्र किया है। उनहोंने कहा है कि एन0आर0ई0पी0 और आर0एल0ई0जी0पी0 के तहत हरियाणा के देहात में काफी उन्नति हुई है और गरीब लोगों को काम मिला है। जहां लेबर की तरफ इतना ध्यान दिया जा रहा है वहां मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि हांसी में जो हैफड मिल है उसके मजदूरों की मांगें जायज हैं। उन्हें मान लिया जाए ताकि मजदूर लोग अपना काम करके पूरा वेतन ले सकें।

अध्यक्ष महोदय, यहां 23 जनवरी का जिक्र आया था। आपोजी ान पार्टीज ने यह दावा किया है कि वे हरियाणा के हित में काम कर रही हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है। हरियाणा सरकार ने भाांति को बनाए रखने के लिए काम किया लेकिन अपोजी ान ने पब्लिक प्रौपर्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सडकों पर दरख्त काट कर गिराए गए, बसों को आग लगाई गई, दुकानों को लूटा गया और उनके आगे लगे हुए तरपालों को जलाया गया। उनका मकसद था कि भाांति को भंग किया जाए ताकि सरकार उत्तेजित होकर कोई कार्यवाही करे। जो लौग ऐजीटे ान कर रहे थे वे चाहते थे कि हरियाणा में भाांति न रहे बल्कि गडबड हो ताकि वे उस गडबड का फायदा उठा सके। उनहोंने कहा है जोतीन आदमी मारे, गए वे भाहीद हुए है। (**इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए**)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस बात की सराहना करता हूं कि हरियाणा की पुलिस ने भाांति कायम रखने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि ऐजीटेटर्ज ने पुलिस पर पत्थर फैंके, बसें जलाने की कोि ा ा की, मकान और दुकानें जलाने की कोि ा ा की लेकिन पुलिस ने बडे संयम से काम किया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं हाउस में निवेदन करना चाहता हूं कि अपोजी ान पार्टी ने हरियाणा की बहबूदी के लिए नहीं बल्कि हरियाणा के नुकसान के लिए काम किया है।

ऐजुके ान के बारे में गवर्नर महोदय ने बताया कि ऐजुके ान का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कई जगह 10+2 प्रणाली के स्कूल बनाए जा रहे हैं और गांव गांव में हाई स्कूल बनाए जा रहे हैं। लड़कियों के लिए 100 प्राईमरी स्कूल खोलने का भी प्रोग्राम है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां ि ाक्षा का इतना विस्तार किया जा रहा है वहां मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि हांसी के अन्दर कालेज की बिल्डिंग नहीं है। हांसी के आसपास के इलाके में साईंस कालेज भी नहीं है। वहां के लोगों की यह मांग काफी सालों से है। इस समय वहां के लडकों को हिसार या भिवानी जाना पडता है। परिणामस्वरूप बसों में बहुत भीड हो जाती है। लडके बसों में आगे पीछे लटक कर जाते हैं। कई लडकों की तो डैथ भी हो चुकी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि हांसी में एक कालेज जरूर बनाया जाए।

इन्हीं भाब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी इन्द्र सिंह नैन (बरवाला): डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय राज्यपाल ने जो इस औगस्ट हाउस में अपना एड्रैस पढा और जिस पर श्री ई वर सिंह जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव हाउस के सामने रखा, मैं उसके समर्थन में खडा हुआ हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने इस ऐड्रैस को पढा ही नहीं, समझा भी है और समझने के बाद मैं यह कह सकता हूं कि यह बहुत ही अच्छा ऐड्रैस है। इसमें हरियाणा सरकार की जो पिछले साल की उपलब्धियां हैं, वे बतलाई गई हैं और आगामी वर्श की योजनाएं द ार्ाई गई हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि पडौसी पंजाब में, अ ाांति और अहिंसा का वातावरण कई दिनों से चल रहा है और जब पडौस के प्रान्त में ऐसे हालात हों तो उसका असर हरियाणा पर पडना स्वाभाविक है लेकिन मुझे बडी खु ाी है कि हमारी सरकार ने हरियाणा के अन्दर ला एंड आर्डर को बहुत कायम रखा और पंजाब में जो दूशित वातावरण चल रहा है, उसका असर हरियाणा पर नहीं पडने दिया। डिप्टी स्पीकर साहब, यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बडी बात हैं कह देना तो आसान है लेकिन करना बडा मु कल है। इस बात के लिए मैं हरियाणा सरकार को और खास तौर से मुख्य मंत्री और पुलिस के विभाग को बधाई देता हूं। ए0सी0 चौधरी जी कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब को भी बधाई देनी चाहिए, उन्होंने भी बडा भारी

काम किया है। मैंने तो सारी ही सरकार का नाम ले दिया है इसलिए उनको भी साथ ही बधाई दे दी। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी पुलिस ने बहुत बडा काम किया है। यहां पर कोई ऐसी घटना नहीं घटने दी जिससे लोगों के अन्दर भय का वातावरण उत्पन्न हो। पडौसी राज्य पंजाब में इनोसैन्ट लोगों को बिना किसी बात के मारा जाता है लेकिन हमारे यहां हरियाणा में ला एण्ड आर्डर की सिचुए ान बहुत बढिया हैं डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी भले राम जी की बात भी ठीक है कि अपोजी ान तो बैठी नहीं है इसलिए बोलने में मजा नहीं आता लेकिन हमारी सरकार ने जो कार्य किये हैं, उनके विशय में बताना तो हमारा फर्ज बनता ही है। डिप्टी स्पीकर साहब, पंजाब और हरियाणा का टैरीटोरियल और वाटर डिसप्यूट है। इसको खत्म करने के लिए और पंजाब के वातावरण को सुधारने के लिए हमारे प्रधान मंत्री और लौंगोवाल जी के बीच एक समझौता हुआ। प्रधान मंत्री जी ने संत लौंगोवाल को दिल्ली बुलाया था, दोनों के बीच एक समझौता हुआ था जिसे राजीव लौंगोवाल समझौता कहते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, उस समझौते के अन्तर्गत एक कमी ान का गठन हुआ जिस मैथ्यू कमी ान कहते हैं। इस मैथ्यू कमी ान ने डिस्प्यूटिड एरिया का फैसला करना था कि जब चण्डीगढ पंजाब को दिया जायेगा तो उसके बदले में हरियाणा को कौन कौन से हिन्दी भाशी क्षेत्र दिये जायेंगे। मैथ्यू कमी न ने पंजाब के उन एरियाज की जनगणना करवायी जो चण्डीगढ के बदले में हरियाणा को दिये जाने थे। उस जनगणना के हिसाब से 83 गांव और दो कस्बे हिन्दी भाशी

क्षेत्र कमी ान ने बताये लेकिन कमी ान के सामने कंटीग्यूटी की बात भी थी जिसके कारण उसके हाथ बन्धु हेए थे। इस रिपोट के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पंजाब के एरिया में 83 गांव और दो कस्बे हिन्दी भाशी क्षेत्र हैं, वे हरियाणा के हैं और उन पर हरियाणा का कलेम बनता है।

डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी बात पानी के बारे में है। पानी के बारे में सुबह क्वै चन आवर में भी एस0वाई0एल0 का जिक्र आया था। एस0वाई0एल0 नहर हरियाणा की लाईफ लाईन है। The entire economy of the Haryana State is dependent on this canal water. हरियाणा कृशि प्रधान प्रदे ा है बल्कि हमारा सारा ही दे ा कृशि प्रधान है। हरियाणा के लिए पानी की बहुत जरूरत है। हरियाणा का हर किसान, मजदूर भाई पानी की तरफ देखता है। हरियाणा में रेतीला इलाका है इसलिए यहां पानी की आव यकता है। पानी के बंटवारे के लिए केन्द्र सरकार ने इरेडडी कमी ान बनाया है जिसने एस0वाई0एल0 के पानी का फैसला करना है। इस बारे में सरकार को सुझाव देना चाहता हूं। वैसे तो हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं छोडी है, पहले भी अपने केस को बहुत अच्छे ढंग से पुट करती रही है और अब भी मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कमी ान के सामने पानी के क्लेम को बहुत अच्छे तरीके से पुट करें, मेरा सुझाव है कि नीड बेस पर बात होनी चाहिए कि पानी की किस को आव यकता है ? एक तरफ पंजाब के अन्दर वाटर लोगिंग है और दूसरी तरफ हमारा पानी

पाकिस्तान को जा रहा है। पंजाब वाले उस पानी को पडौसी प्रदे ा को नहीं देना चाहते हैं। इससे ज्यादा दु:ख की और क्या बात हो सकती है ? हम सैंट्रल सरकार के सामने इस बात को बडे अच्छे ढंग से रखें ताकि यह नहर भी जल्दी से बन सके और हमें पानी भी जल्दी मिल सके। मुख्य मंत्री जी अभी दिल्ली होकर आये हैं। मैं इस नहर के बनाने के बारे में मुख्य मंत्री जी को पहले भी कहता रहा हूं कि यह नहर पंजाब वाले नहीं बनायेंगे। मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि इसे सैन्टर सरकार अपने हाथ में ले ले तभी यह बन सकती है वरना इसमें ऐसे ही डिले होती रहेगी। आज हरियाणा की जनता प्यासी है उसे पानी की बहुत ही जरूरत है।

डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा ने आल राउन्ड प्रोग्रेस की है, आर्थिक मामलों में भी और सामाजिक मामले में भी। हमारी गवर्नमैंट ने काफी काम लोगों की भलाई के लिये किये हैं। हमारा सातवां पांच साला प्लान 2900 करोड रूपये का है और सन 1986–87 के लिए 525 करोड रूपये का प्लान एप्रूव हो चुका है। डिप्टी स्पीकर साहब, आज के जमाने में बिजली की बहुत ही आव यकता है। बिजली तरक्की की बैकबोन है। जहां भी तरक्की हुई है वह बिजली से हुई है। बिजली के बारे में मैं यही कहूंगा कि हरियाणा में जितनी आव यकता है उतनी बिजली नहीं है। पिछले दिनों बम्बई में हमारी कांग्रेस पार्टी का अधिवे ान हुआ था। वहां पर बिजली बिल्कुल नहीं गई और न ही कभी जाती है।

वहां पर बिजली का उत्पादन प्राईवेट सैक्टर में होता है। लेकिन हमारे यहां पब्लिक सैक्टर में होता है। क्या कारण है प्राईवेट सैक्अर में तो ठीक तरह से बिजली का उत्पादन होता है लेकिन पब्लिक सैक्टर में मिलता है। मेरा इस बारे में सुझाव है कि सरकार को देखना चाहिये कि यह कमी कहां पर है, उस कमी को दूर करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिएं क्योंकि हमें बिजली की बडी भारी जरूरत है। डिप्टी स्पीकर साहब, सातवें फाईव ईयर प्लान में 113 मैगावाट बिजली पैदा करने का प्रावधान है। सन 1986–87 में बहुत से नये सब स्टे ान लगाये जायेंगे और जो मौजूदा सब स्टे ान हैं उनकी परफारमैंस ठीक की जायेगी। डिप्टी स्पीकर साहब, उकलाना मंडी मेरे हल्के में पडती है। वहां के लिए 132 के0वी0 सब स्टे ान का केस आया हुआ है, इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसे जल्दी से लगवाया जाये क्योंकि वहां पर बिजली की बहुत कमी हैं

डिप्टी स्पीकर साहब, सिंचाई सारी इकोनोमी का आधार है। सिंचाई के लिए एस0वाई0एल0 का बनाया जाना बहुत जरूरी है। दूसरे जो वाटर कोर्सिज पक्के किये जा रहे हैं, वे डिफैक्टिव बनाये जा रहे हैं। उनका लेवल ठीक नहीं बनाया जाता। इसलिए उनका लेवल ठीक किया जाना चाहिए और ठीक भी बनाये जाने चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी गांव के रहने वाले हैं और मैं भी गांव का रहने वाला हूं। आपको मालूम है कि गांव में लोगों को काफी दिक्कत है। इस दिक्कत को दूर किया जाये।

पब्लिक डिस्ट्रिब्यू ान के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। पब्लिक डिस्ट्रिब्यू ान सिस्टम को बडे अच्छे ढंग सें आर्गेनाइज किया गया। इस बारे में सरकार को एक सुझाव दूंगा कि जो 6129 फेयर प्राइस भााप्स खोली गई है उनको तो फेयर प्राइस भााप्स कहा जाता है, लेकिन जो दूसरी दुकानें हैं, क्या वे अन फेयर प्राइस भााप्स हैं ? गांवों में फेयर प्राइस भााप्स पर सब चीजें नहीं पहुंचती हैं, जैसे कपडा है और दूसरी चीजें हैं। सरकार ने जो एम बनाया है, उसे पूरा करना चाहिए और आम आदमी तक सारी चीजें पहुंचानी चाहिए। सारा सामान उन दुकानों तक नहीं जाता है। इसलिए मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

डिप्टी स्पीकर साहब, आजकल आबादी बहुत बढ रही है जिसकी वजह से अन एम्पलायमैंट भी बहुत ज्यादा है। जब हम कहीं पर जाते हैं या कभी हल्के में जाते हैं तो एक ही बात सामने आती हैं और वह है अनएम्पलायमैंट। 90 प्रति ात तो नौकरी चाहने वाले होते हैं और 10 परसैंट बदली वाले होते हैं। न कोई सडक की बात करता है और न कोई कालेज के लिये कहता है। मेरा कहना यह है कि लोगों की भलाई के लिये जो कुछ यह सरकार कर रही है, वह काफी नहीं है। इस सरकार ने बहुत कुछ अन एम्पलपायेंट दूर करने के लिए किया है। इस एड्रैस के अन्दर बताया गया है कि सैंट्रल गवर्नमैंट की एक स्कीम है जिसका नाम सैल्फ एम्पलायमैंट स्कीम है। उसके तहत 25000 रूपया लोन

इंडस्ट्री डिपार्टमैंट की तरफ से दिया जाता है। इंडस्ट्री डिपार्टमैंट का जो जी0एम0 होता है उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, वह तो स्कीम को पास कर देती है लेकिन जब वह नौजवान बैंक के पास जाता है तो बैंक वाले पैसा कम कर देते हैं। मेरे विचार में ऐसा अधिकार बैंक के अधिकारियों के पास नहीं होना चाहिये। खास करके ऐसा देहात के आदमियों के साथ किया जाता है उससे बडी परे ाानी और दिक्कत पैदा हो जाती है। मेरा सरकार को यह सुझाव है कि वह इसकी तरफ ध्यान दे। ि ाक्षा के क्षेत्र में भी हरियाणा में काफी उन्नति हुई है। हमारे ि ाक्षा मंत्री जी जगह जगह जाते हैं और खुद जाकर देखते हैं। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि मेरे हलके के बरवाला टाउन की आबादी 25000 है। वह एक कस्बा है। वहां से 30—40 किलोमीटर की दूरी तक कोई कालेज नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पब्लिक इन्ट्रैस्ट में वहां पर एक कालेज अव य खोला जाना चाहिये। कालेज खोलने से धिराय हल्का, भटटु कलां हलका, नारनौंद हल्का, टोहाना हल्का और बरवाला हल्का के लोगों को फायदा होगा। डिप्टी स्पीकर साहब, जैसे मैंने बरवाला में कालेज खोलने के बारे में बात कही, इस के साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वहां पर मैं मुख्य मंत्री जी के कई बार पब्लिक जलसे भी करवा चुका हूं। 27—10—1984 को मैंने आदरणीय मुख्य मंत्री जी के सामने लोगौं की एक मांग रखी थी कि वहां पर तहसील बना दी जाये। इन्होंने अ योरैंस दे दिया था। मैंने उस वक्त इनका धन्यवाद भी किया था और आज भी धन्यवाद करता

हूं। वहां पर तहसील बन जाने से नारनौंद, भटटू कलां, टोहाना, धिराय और बरवाला आदि के सब हल्कों के लोगों को फायदा होगा। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं हैल्थ के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हैल्थ के बारे में एक कहावत भी है' पहला सुख निरोगी काया' अगर हमारी हैल्थ ठीक है, हर चीज ठीक है। हमारी सरकार ने इसके लिये काफी प्राईमरी हैल्थ सैंटर्ज, सब सैंटर्ज और कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर्ज बनाये हुए हैं और सरकार आगे भी बनाने की स्कीम बना रही है। मेरे हल्के में उकलाना मंडी में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 23—11—1985 को एक सामुदायिक सैंटर का उदघाटन किया था। इसके अलावा बरवाला में एक रीजनल इंस्टीच्यूट आफ पब्लिक हैल्थ नर्सिंग भी बनाया गया है। यह उत्तरी भारी में अपने किस्म का एक पहली इंस्टीच्यूट है। इसके वहां पर खोलने के लिये मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस इंस्टीच्यू ान में नर्सों को, 10 महीने का कोर्स करने के बाद डिप्लोमा मिलेगा। जहां तक ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक है, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हमारे लिये एक फखर की बात है कि हमारी रोडवेज सारे हिन्दुस्तान में लगातार तीन बार प्रथम रही है। इसके लिये मै। सरकार को मुबारिकवाद देता हूं। सडकों की बात भी मैं कहना चाहता हूं। मैंने क्वै चन आवर में कहा था कि जब बजट आयेगा तब भी मैं सडकों की बाबत कुछ कहूंगा। बरवाला और उकलाना में दोनों जगह बस स्टैंड बनाने के लिये पत्थर रखा जा चुका है। पैसा भी भाायद पर जल्दी से जल्दी काम भाुरू करवाया जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं हैफेंड के बारे में

एक बात कहना चाहूंगा। (घंटी) बस एक दो मिनट में खत्म कर दूंगा। पैडी की प्रौक्योरमैंट हैफैड भी करती है और दूसरी सरकारी एजेंसियां भी करती हैं। इस साल यानि 1985–86 में टोटल पैडी की प्रोक्योरमैंट 1 लाख 92 हजार टन की हुई है जिसमें से 1.61 लाख टन अकेले हैफेड ने की है। कहने का मतलब यह है कि टोटल प्रोक्योरमैंट का 84 परसैंट प्रोक्योरमैंट हमने किया है। डिप्टी स्पीकर साहब, जब भी कोई ऐजेंसी खरीदने से इन्कार करती थी तो हम सामने आते थे। लोगों की आसानी के लिए और किसानों के फायदे के लिये इतना बडा काम किया है। मैं मुख्य मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि एफ0सी0आई0 हमारे काम में रूकावट बन रही है। एफ0सी0आई0 माल की डिलीवरी नहीं लेती, स्टाक को उठाती नहीं है। इससे हमें बडा भारी नुक्सान हो रहा है। मैं सरकार से यह कहूंगा कि एफ0सी0आई0 से बात की जाये ताकि हैफेड, जो किसानों की समय समय पर सेवा करती रही है। उसको लाभ हो सके। (घंटी) आपने घंटी बजा दी है। मैं बोलतना तो बहुत चाहता था लेकिन अन्त में मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए एक बात ही कहना चाहूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे अपोजी ान के भाईयों को हाउस में आना चाहिये था। यहां आकर सजै ान्ज देंने चाहियें थे, लोगों की बात कहनी चाहिये थी लेकिन उनको तो एक ही नि ाना है कि प्रान्त में गडबड किसी ने किसी तरह बनी रहे। डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी देहात के रहने वाले हैं। उनका क्या नि ाना है वह मैं अपने भाब्दों में आपको समझा देता हूं। ठहरा हुआ पानी अगर किसी

जगह होता है तो वह गंदा न रह कर साफ हो जाता है क्योंकि मिटटी नीचे हो जाती है लेकिन जो चालाक आदमी होता है, वह उसमें पत्थर फैंकता रहता है ताकि उसकी मिटटी नीचे न बैठ जाये। उनकी भी यही कहानी है कि वे 1987 तक एजीटे ान चलाते रहें, ताकि वह पानी रूपी ऐजीटे ान की गंदगी नीचें न बैठ जाये। धन्यवाद।

श्री दया नन्द भार्मा (राजौंद): डिप्टी स्पीकर साहब, 17 फरवरी को गवर्नर महोदय ने इस सदन में जो भाशण दिया है, मैं उसके लिये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खडा हुआ हूं। वैसे तो इनके भाशण पर काफी बहस हो चुकी है लेकिन इसमें मैं भी कुछ बातें कहना चाहूंगा। वैसे तो इसमें कोई भी टैक्नीकल बात नहीं है लेकिन दो तीन बातें जिस पर सारे सदस्य बोले हैं, मैं भी बोलना चाहता हूं। पिछले साल हरियाणा सरकार ने ि ाक्षा की नई प्रणाली चालू की और कुछ एक जिलों में कहीं 10, कहीं 15 स्कूलों में 10 प्लस 2 की नीति चलाई। यह एक बडा भारी कार्य था। हमारी सरकार का एक ही मकसद है कि सारे हिन्दुस्तान के अंदर ि ाक्षा का एक ही स्तर बनाया जाये ताकि जो लोग आजकल पढ लिखकर बेकार हो जाते हैं, इस नई ि ाक्षा नीति के तहत उनकी संख्या कम करने में मदद मिल सके। लोग बी0ए0 कर लें, चाहे एम0ए0 कर लें, इससे ि ाक्षा का एम पूरा नहीं होा। बी0ए00, एम0ए0 करने के बाद नौकरी के लिए धक्के खाते फिरते हैं। यह जो नई ि ाक्षा प्रणाली है; इसके अन्दर 10वीं

तक जो लडके पढते हैं, उस दौरान उनको साइकौलोजीकली देखते हैं कि वह किस तरफ चल सकते हैं। उसके बाद उनको उस पार्टिकुलर विशय की ि ाक्षा दी जाती है। पिछले साल इस ि ाक्षा के बारे में जो स्कूल टेक अप कियो, सरकार ने उनमें न तो पूरे सब्जैक्ट ही दिये, न टीचर दिये और न ही साईंस का सामान दिया। इस बारे में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। यह प्रणाली तब तक अच्छी प्रकार से लागू नहीं की जा सकती जब तक हम टीचर नहीं दे पाते, जब तक हम इन्स्ट्रूमैंट नहीं देते और जरूरी सामान नहीं देते। मेरा कहना यह है कि स्कूलों को अच्छी तरह से सुसज्जित करके इस नई प्रणाली को लागू किया जाये। जहां तक इरीगे ान की बात का ताल्लुक है, यह तो सब को पता है कि एस0वाई0एल0 के पानी के बिना हरियाणा के अन्दर सिंचाई पूरी तरह से नहीं हो सकती लेकिन मैं इस बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। एम0आई0टी0सी0 वहां पर टयूबवैल्ज लगाती है जहां पर पानी अच्छा हो, जैसे करनाल और कुरूक्षेत्र के एरिया में। मेरा कहना यह है कि उस एरिया में जहां टीलों के नीचे पानी अच्छा है जैसे जींद और भिवानी के एरियाज में है, वहां पर अगर टयूबवैल्ज लगाये जायें तो मैं समझता हूं कि काफी एरियाज की सिंचाई हो सकती है। इससे काफी हद तक सिंचाई की समस्या हल हो सकती है। मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि एम0आई0टी0सी0 को यह डायरैक ान दी जाये कि वह ऐसे इलाकों में जहां टिल्लों के नीचे ठीक पानी है, वहां टयूबवैल्ज

लगाये ताकि जो बारानी जमीन पडी हुई है, उसकी कुछ न कुछ सिंचाई की जा सके।

डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक अनएम्पलायमैंट का सम्बंध है, हरियाणा के अन्दर बहुत अधिक अन एम्पलायमैंट है। कोई भी लडका चाहे वह मैट्रिक पास है, चाहे आठवीं पास है, चाहे बी0ए0 पास है, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए दौड़ता फिरता है। अभी नैन साहब ने बताया कि जब वे हिसार जाते हैं तो बहुत से लडके उनके पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें नौकरी दिलवाओ। उपाध्यक्ष महोदय, सैल्फ एम्प्लाएमैंट की स्कीम बहुत अच्दी है और इसमें पच्चीस हजार रूपया दिया जाता है लेकिन यह रूपया उनको दिया जाता है जो अन्ट्रेंड हैं। ऐसे लोगों के पास जब रूपया आता है तो वे ठीक तरह से कोई काम नहीं चला सकते और न ही कोई इंडस्ट्री चला सकते हैं क्योंकि वे ट्रेंड नहीं होते। मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि जिन लोगों को यह रूपया दिया जाए, उनको पहले ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अगर कोई लडका कैमिस्ट की दुकान खोलना चाहता है तो उसको कैमिस्ट की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और अगर कोई टेलीविजन की दुकान खोलना चाहे तो उसको टेलीविजन की ट्रेनिंग दी जाए यह ट्रेनिंग कम से कम दो या तीन महीने की दी जानी चाहिए। अनट्रेंड आदमी को दुकान खोलने के लिए पच्चीस हजार रूपया देने का कोई फायदा नहीं है। वे लोग पैसा तो ले लेते हैं लेकिन उस पैसे को वे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। वह पैसा बेकार

जाता है। कोई काम न चलने की वजह से जब वे कि त नहीं भर सकते तो अधिकारी उनको तंग करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार गाय या भैंस के लिए भी लोन देती है लेकिन इसमें एक बडा भारी डिफैक्ट है। लोन तो सैंक ान हो जाता है, लेकिन जब वह बैंक के पास जाता है तो बैंक्स उसको पैसा नहीं देते। कोई न कोई टैक्नीकल अडचन लगा देमते हैं। पिछले सै ान में भी हमने मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना की थी कि इसका कोई हल निकालना चाहिए ताकि लोगों को लोन पूरा मिल सके और कोई परे ाानी न हो। यह रूपया लैंड मौरगेज बैंक या कोआप्रेटिव बैंक के थ्रू दिलवाया जाये। नै ानेलाइज्ड बैंक्स से पैसा लेने में लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि वे लोग कर्जा लेने वालों को काफी परे ाान करते हैं, इसलिए उस सिस्टम में सुधार किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं हैल्थ के बारे में कहना चाहता हूं। यह बात ठीक है कि हरेक गांव में डिस्पैंसरी है। चाहे वह आयुवेर्दिक डिस्पैंसरी है, चाहे दूसरी है, इनमें मैडीसन्ज तो मिल जाती हैं लेकिन इन डिस्पैंसरियों को कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहां कोई लेबोरेटरी नहीं होती। मेरा सुझाव है कि चार पांच गांवों को एक समूह बना कर एक टैंस्टिंग लेबोरेटीर खोल दी जाए। वह लेबोरेटरी इन चार पांच गांवों को कवर करेगी। अगर ऐसा कर दिया जाए तो लोगों की डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाट्रर पर जाना नहीं पडेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाशण के अन्दर एग्रीकल्चर के

बारे में काफी कुछ कहा ग्रया है लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं आज हम देखते हैं कि फसलों को बीमारी लग जाती है। किसान जब छिडकने के लिए बजार से दवाई लाता है और उस दवाई को फसलों पर छिडकता है तो उसका कोई असर नहीं होता क्येांकि वह दवाई डुप्लीकेट होती है। बाजार में जो पैस्टीसाइडज मिलते है वे डुप्लीकेट होते हैं और उनका असर बिल्कुल नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, जो पैस्टीसाइडज फैक्टरियां हैं, वे ज्यादातार प्राईवेट सैक्टर में हैं और ये नकली चीजें बनाती हैं। इन फैक्टरियों को पब्लिक सैक्टर में लगाना चाहिए ताकि अच्छे पैस्टीसैक्टर बाजार में मिल सकें और फसलों को बीमारी से बचाया जा सके। पब्लिक सैक्टर में पैस्टीसाइडज की एक भी फैक्टरी नहीं है। गवर्नमैंट को इस तरह की फैक्टरी जरूर लगानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ओवरल आल डिवैल्पमैंट का ताल्लुक है हरियाणा ने काफी तरक्की की है लेकिन आज कल साइंस के युग में जितनी अधिक तरक्की हो जाए वह थोडी है। आज रेस का युग है और रेस के जमाने में हरेक आदमी की यही भावना होती है कि ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो। उपाध्यक्ष महोदय, क्रिटीसीजम तो होता ही रहता है, इसकी परवाह न करते हुए सरकार को आगे बढते रहना चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं गवर्नर ऐड्रैस पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

चौधरी हुक्म सिंह (सालहावास): उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर चौधरी ई वर सिंह ने जो

धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने हमारी सरकार की कारगुजारी का अपने अभिभाशण में जिक्र किया है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले राज्यपाल महोदय ने 24 जुलाई 1985 को हुए राजीव लौंगोवाल समझौते का जिक्र किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैथ्यू कमी ान ने साफ तौर पर माना है कि अबोहर, फाजिल्का तथा उसके 83 गांव हिन्दी भाशी हैं और इन पर हरियाणा का हक बनता है। इनको हरियाणा प्रदे ा में भाामिल कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि कन्डूखेडा पंजाबी भाशी होने के कारण ये 83 गांव हरियाणा को नहीं मिल सकते क्योंकि कमी ान के ऊपर कंटीग्यूटी की भार्त लगी हुई है। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने यह माना है कि ये 83 गांव तथा अबोहर और फाजिल्का हरियाणा के हैं। भारत सरकार इनको देना चाहे तो ये 83 गांव तथा अबोहर और फाजिल्का हरियाणा को दिए जा सकते हैं

उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाशण में बाढ की रोकथाम के लिए सरकार जो कदम उठाने जा रही है, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। अगर बाढ की रोकथाम हो जाए तो किसान की जो जमीन बाढ से बरबाद हो जाती है, वह बच सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे रोहतक जिले में जे0एल0एन0 कैनाल गुजरती है। इससे सीपेज होने की वजह से किसान की बडी जमीन बरबाद हो जाती है और किसान लुट जाता है। किसान अपनी

जमीन पर पैसा खर्च करता है और मेहनत करता है लेकिन उसको मेहनत का फल नहीं मिल पाता। आने वाले सालों में अगर जमीन को बाढ से बचाने की योजना पूरी हो जाती है तो किसान को बहुत अधिक फायदा होगा। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जितनी अधिक जमीन इस बाढ से बचाई जाए उतना ही अच्छा है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाशण में बिजली के बारे में लिखा है कि 220, 120, 132 और 66 के0वी0 के सब स्टे ांज बनाए जाएंगे। इन सबके चालू हो जोन पर हरियाणा में बाहर हजार नलकूपों और साठ हजार घरों को बिजजी के कनैक ांज मिल जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में सरकार के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं। 1975 में पानीपत के थर्मल प्लांट की नींव रखी गई थी और उसके साथ 1975 में ही पंजाब में भटिंडा के थर्मल प्लांट की नींव रखी गई थी। भटिंडा का प्लांट 660 मैगावाट बिजली पैदा करता है लेकिन पानीपत का थर्मल प्लांट केवल 220 मैगावाट बिजली पैदा करता है। इसका मतलब यह है कि भटिंडा का थर्मल प्लांट 420 या 440 मैगावाट ज्यादा बिजली पैदा करता है। सौ मैगावाट में पच्चीस लाख यूनिट बिजली पैदा होती है जो किसान को मिल सकती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां कुछ न कुछ कमी जरूर रही है और बराबर के प्रदे ा के प्लांट की तरह हमारा प्लांट काम नहीं करता। सरकार चाहे तो इसकी जांच के लिए कमेटी बना सकती है। आज हमारे किसान के लिए बिजली बहुत जरूरी चीज है। अगर आज किसान

दस काम करता है तो सात काम बिजली के माध्यम सेम करने पडते हैं। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बिजली की तरफ अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। जितना सरकार इस तरफ ध्यान देगी उतना ही प्रदे ा के लिए अच्छा रहेगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं मंडियों का जिक्र करना चाहता हूं। इसका जिक्र राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाशण में भी किया है कि वर्श 1986–87 में सरकार की योजना है कि सात नई मार्केट कमेटियां बनायी जाएं और 29 नये सब मार्केट यार्ड और 30 खरीद केन्द्र स्थापित किये जाएं। ये वर्तमान 93 मार्केट कमेटियों, 146 विकसित सब मार्केट यार्डों और 107 खरीद केन्द्रों के अतिरिक्त होंगे। इससे सातवीं योजना में कृशि क्षेत्र के उत्पादन में भरी वृद्धि होगी। यह बडी अच्छी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत सरकार के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं कि मेरे इलाके कोसली में 10–12 सालों से 80 एकड भूमि सरकार ने मंडी बनाने के लिए एक्वायर कर रखी है। वहां पर पलटस भी कट चुके हैं और लोगों ने ज्यादा से ज्यदा प्लाटस ले रखे हैं परन्तु बडे अफसोस के साथ कहना पडता है कि वहां पर आज तक सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मिनिस्टर महोदय से व मुख्य मंत्री महोदय, से मेरी प्रार्थना है कि जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, किसान की तकलीफों को देखते हुए और उस इलाके के किसानों की द ाा को समझते

हुए कोसली मंडी में डिवैल्पमैंट का काम जल्दी ही भाुरू करवाया जाए।

इससे आगे उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब ने अपने अभिभाशण में कहा है कि वर्श 1986–87 के दौरान, 40 नयी प ाु चिकित्सा डिस्पैंसरियां खोले जाने और विद्यमान 30 प ाु चिकित्सा डिस्पैंसरियों का दर्जा बढा कर प ाु चिकित्सा अस्पतालों में बदलने के लिए सरकार का प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इससे अलग एक बात सरकार के सामने रखना चाहता हूं। आ ाा है कि मेरी बात को बुरा नहीं माना जाएगा। मैं हकीकत कहता हूं कि हमारे प्रदे ा में 7154 गांव हैं और 81 कस्बे हैं जिनमें कुल 772 प ाु चिकित्सालय हैं। अगर हम औसत निकालते हैं तो लगभग 10 गांव के पीछे एक प ाु चिकित्सालय हिस्से में आता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि हमारा हरियाणा प्रदे ा कृशि प्रधान प्रदे ा है। हमारे जो किसान हैं उनकी आमदनी का आधा भाग प ाु पालन पर निर्भर करता है। इसलिये वे प ाु पालन को ज्यादा महत्व देते हैं। कुल मिलाकर उनको 40–50 परसैंट आमदनी, प ाु पालन से होती है। किसान हर प्रकार का दूध देने वाले गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और दूसरे प ाु पालते हैं। आज एक भैंस छः सात हजार रूपए के करीब आती है। अगर किीस का प ाु समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए तो किसानों के प ाुओं को मरने से बचाया जा सकता है। इसलिये मेरी सरकार से गुजारि ा है कि हस्पतालों की संख्या और बढायी

जाए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि सरकार की तरफ से प ाु चिकित्सा की जो मौजूदा सहूलियतें हैं, ये बहुत थोडी हैं। आदमी अगर बीमार होता है तो उसको साईकल पर, बस पर या कार में बेठा कर हस्पताल ले जाया जा सकता है लेकिन प ाु को न बस में, न साईकल पर और न कार में ले जाया जा सकता है इसलिये सरकार को चाहिये कि हर गांव में नजदीक से नजदीक प ाुओं के हस्पताल खोलें। इस तरफ सरकार खास ध्यान दे।

इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की जो एन0आर0ई0पी0 और आर0एल0ई0जी0पी0 स्कीमें हैं उनमें जो पैसा आता है उससे देहाती लोगों को काफी फायदा पहुंच रहा है और रोजगार के साधन भी मुहैया हो रहे हैं। यह बडी अच्छी स्कीमें हैं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि भविश्य में भी ऐसी जितनी स्कीमें लोगों की भलाई के लिये बनाई जाएं, थोडी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ि ाक्षा के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में यह कहा गया है कि सातवीं पंचवर्शीय योजना में केवल लड़कियों के लिये ही 500 प्राईमरी स्कूल खोलने का प्रस्ताव है जिनमें से चालू वर्श में 100 स्कूल खोले जा चुके हैं इस बारे में मेरा यह सुझाव है। जहां तक प्राइमरी स्कूल खोलने का ताल्लुक है, अगर किसी गांव में प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिये नहीं है, वहां अव य खोल दियश जाए, लेकिन अलग से लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूलों

की व्यवस्था करना मेरी समझ से बाहर की बात है। प्राइमरी स्कूल तक तो लडके लड़कियों की सह ि ाक्षा का प्रबन्ध कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि इस आयु में अभी बच्चे बिल्कुल नादान होते हैं और उनको किसी भी बात का पता नहीं होता। अगर लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोलने की आव यकता महसूस हो तो प्राइमरी के बाद 10वीं क्लास तक खोल दिये जाएं और जो पैसा लड़कियों के लिए अलग प्राइमरी स्कूल खोलने में लगाया जाएगा, इसका कहीं अन्य जगहों पर हाई स्कूल खोल कर सदुपयोग किया जाए। लडके लड़कियां 10वीं क्लास के बाद तो अपने आप ही कालेज में इकटठे हो जाते हैं क्योंकि उस समय तक बच्चों को समझ आ जाती है और वे अपने भले बुरे को स्वयं समझने लगते हैं। इसलिये अगरे प्राइमरी स्कूल अलग खोलने की बजाये, प्राइमरी के बाद मैट्रिक तक लडके और लड़कियों के अलग अलग स्कूल खोले जाएंगे तो इव य ही लडके और लड़कियों दोनों को ही फायदा होगा।

इससे आगे डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तकनीकी ि ाक्षा के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। इस अभिभाशण में तकनीकी ि ाक्षा के बारे में किसी किस्म का जिक्र नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे प्रदे ा में 25 आई0टी0आई0 संस्थाएं चल रही हैं और 14 जगह गैस्ट क्लासिज चल रही हैं इस तरह से हमारे प्रदे ा में 39 सैन्टर्ज में टैक्नीकल ट्रेनिंग दी जा रही हैं। जो बच्चे इन इंस्टीयू ांज से ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं वे बाहर

निकल कर अपना काम करा सकते हैं, उनको दे ा और विदे ा में नौकरी मिल सकती है क्योंकि आजकल टैक्नीकल आदमी की ज्यादा आव यकता है, और अगर उस आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी तो वह भारत सरकार की सैल्फ एम्पलाएमैंट की जो स्कीम है और जिसके अन्डर पच्चीस हजार रूपया मिल जाता है उसके माध्यम से वह आदमी पैसा लेकर अपना कोई काम धन्धा भुरू कर सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि टैक्नीकल आदमी बेकार नहीं रह सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ हालात यह है कि आज हमारे स्कूलों और कालिजिज से लाखों बच्चे डिग्रियां लेकर निकलते लेकिन उन डिग्रियों के आधार पर उनको नौकरी नहीं मिलती। इस तरह से बेरोजगारी का अम्यूनी ान बढता जाता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि प्रदे ा के अन्दर अधिक से अधिक आई0टी0आई0 कालिजिज खोलें जिससे कि बेरोजगारी की समस्या हल हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जो 39 संस्थाएं चल रही हैं जिनमें हमारे प्रदे ा के बच्चों को तकनीकी ि ाक्षा दी जाती है वे थोडी हैं। हमारे वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं मेरी उनसे प्रार्थना है कि अगर एक बजट में ज्यादा आई0टी0आई0 खोलने के लिए पैसा प्रोवाईड नहीं कर सकते तो धीरे धीरे डिविजन लैवल पर, तहसील लैवर पर और सब तहसील लैवल पर चार चार, पांच पांच आई0टी0आईज0 हर साल खोल दिए जाएं जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे टैक्नीकल ट्रेनिंग लेकर बाहर आएं और वे अपना काम

धन्धा भुरू करें। उपाध्यक्ष महोदय, आए दिन आप देखते हैं कि अपने प्रदे ा से, दे ा से और विदे ा से भी तकनीकी नौजवानों की मांग बढती जा रही है। अगर हमारे प्रदे ा में अधिक टैक्नीकल इंस्टीटयू ांज होंगे तो हमारे नौजवान अधिक से अधिक तकनीकी ि ाक्षा प्राप्त कर सकेंगे और हमारे प्रदे ा से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। (घण्टी)

16.00 बजे।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक मिनट आपसे और लूंगा। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाशण में एक्स सर्विसमैन और स्वतन्त्रता सेनानियों को पैन् ान देने के बारे में भी जिक्र किया है। यह बडा सराहनीय कदम हैं सरकार ने उनकी पैन् ान एक सौ रूपये से दो सौ रूपए महीना की है। मुझे उम्मीद है कि सरकार आगे के लिए भी इन लोगों को सहूलियत देती रहेगी। पिछले साल अपने अभिभाशण में राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया था कि हम हरियाणा प्रदे ा में दूसरा सैनिक स्कूल खोलने जा रहे हैं। मैंने भी इस बारे में पिछले साल जिक्र किया था लेकिन अब तक उस स्कूल को खालने के बारे में कोई आव यक कार्यवाही नहीं हुई है। हमारे रोहतक जिले की झज्जर तहसील में 1962 में, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर सरदार प्रताप सिंह कैरों ने सैनिक स्कूल खोलने के लिए पत्थर रखा था। कुछ दिनों के बाद वहां से वह स्कूल उठा कर कुंजपुरा में ले जाया गया जिसका नाम 'सैनिक स्कूल, झज्जर एट कुंजपुरा' है। हमारे जिले में लगभग 60 हजार

एक्स सर्विसमैन हैं जो कि सारे हरियाणा के एक्स सर्विसमैन का चौथा पांचवां हिस्सा बनता है। अकेली झज्जर तहसील में 24–25 हजार एक्स सैर्विसमैन हैं। इसलिये मै। सरकार से निवेदन करूंगा कि सब तहसील मातनहेल के गांवों ने 250 एकड जमीन दे रखी है जो कई लाख रूपए की है। उस जमीन पर सैनिक स्कूल बना दिया जाए। इन भाब्दों के साथ मैं राज्यपाल के अभिभाशण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भले राम (बड़ौदा–अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, बहुत से हमारे साथियों ने गवर्नर अभिभाशण का समर्थन किया और मैं भी इसका समर्थन करते हुए यह कहना चाहूंगा कि गवर्नर साहब ने अपने अभिभाशण में कहा है कि हरियाणा एक भाान्तिप्रिय प्रदे ा है। अगर किसी भाान्ति प्रिय प्रदे ा के साथ ज्यादती हो तो यह अच्छी बात नहीं है। आपको पता है, जब ज्वायंट पंजाब था तो उसमें मौजूदा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल भाामिल थे। आप रिकार्ड निकाल कर देख लें, उस समय हमारे जो डिवैल्पमैंट के कार्य थे, चाहे वह बिजली का काम था या सडकों का काम था उनमें हमारे साथ हमे ाा ज्यादती होती थी। हमारे यहां रूपये में से चार आने खर्च होता था बाकी सारा पैसा पंजाब में खर्च होता था। जब 1966 में बंटवारा हुआ तो उसके बाद भी हमारे साथ ज्यादती हुई। उस समय असैटस में जो हिस्सा हमें मिलना चाहिए था वह रे ाो के हिसाब से हमें नहीं मिला। बडी बदकिस्मती की बात है कि हमारा पडौसी राज्य यह नहीं सोचता

कि हरियाणा भी उसका छोटा भाई है। बंटवारे के बाद कमी ान ने चण्डीगढ हरियाणा को दिया था लेकिन चण्डीगढ इसलिये वापिस देना पडा कि उस समय फेरूमान ने मरण वर्त किया था। हमने यह सोचा कि कोई बात नहीं पंजाब हमारा बडा भाई है, चण्डीगढ के बदले में हमें कुछ और मिल जाएगा। बाद में एवार्ड हुआ कि चण्डीगढ के बदले में हरियाणा को अबोहर फाजिल्का के इलाके दे दिए जाएं। इतने लम्बे समय से यह मामला लटकता आ रहा है। पंजाब में कितनी गडबडी हुई फिर उसके बाद मैथ्यू कमि ान बनाया गया। इस कमि ान ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि अबोहर फाजिल्का तथा उसके 83 गांव हरियाणा को मिलेंगे जिसको हमारे मुख्य मंत्री ने वैलकम किया। उन्होंने कहा कि कमि ान ने जो फैसला किया है, हमें स्वीकार है। आपने पिछले दिनों अखबारों में पढा होगा कि बरनाला जी कई बार बुलाने के बाद भी खिसक जाते थे क्योंकि उनको पता था कि यह रिपोर्ट हरियाणा के हक में हैं। पिछले दिनों अपोजी ान के भाईयों ने भी बडा भाोर भाराबा किया जबकि हमारे मुख्य मंत्री जी का स्टैंड वहीं था जो पहले था। इन्होंने अब भी प्रधान मंत्री जी को मिलने के बाद अपना स्टैंड वही रखा था कि जब तक 83 गांव और दो कस्बे हमें नहीं मिलेंगे तब तक हम किसी कीमत पर चण्डीगढ नहीं दे सकते। हमने भी अपनी पार्टी मिटिंग में मुख्य मंत्री जी को कह दिया था कि हम आपके साथ हैं, अगर आपको हमारे अस्तीफों की जरूरत पडे तो दे देंगे, आप अपने स्टैंड से न बदलें। मैं मुख्य मंत्री जी से अब भी कहूंगा कि अगर हरियाणा के

साथ अहित होता है तो हम अस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। इसलिये हम कभी भी यह बर्दा त नहीं करेंगे कि हरियाणा के साथ ज्यादती हो। अपोजी ान के भाईयों ने बगैर किसी कारण के रास्ता रोको आन्दोलन किया और हमें कहते हैं कि आप भी अस्तीफा दें। हम बगैर किसी कारण क्यों अस्तीफा दें, हम अपने स्टैंड पर कामय हैं। 26 जनवरी को जो समझौता लागू होना था उसके बारे में बडे चाव से देखा जा रहा था कि क्या होगा। बी0बी0सी0 तक से खबरें आ रही थीं। किस तरह से सरदारों ने भाहर को सजाया था लेकिन बात वहीं बनी कि जैसे कोई बारात बिना दुल्हन के वापिस चली जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा का क्लेम बिल्कुल वाजिब है। मुझे पूरा यकीन है कि हरियाणा अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ साथ जिस ढंग से सरकार ने ला एंड आर्डर को कायम रखा है, वह सबके सामने है। कोई भी प्रदे ा तभी तरक्की करता है जब वहां भाान्ति हो। आल राउंड प्रौग्रैस तभी होती है जब वहां के नागरिक सरकार का साथ दें। इसके आगे गवर्नर महोदय ने अपने एड्रैस में कहा है कि सातवीं पंचवर्शीय योजना 2900 करोड रूपए की है जिसमें से आने वाले साल में सवा पांच सौ करोड रूपए खर्च होंगे। इस सवा पांच सौ कराड रूपए में से ज्यादा खर्चा सिंचाई पर होगा। यह बहुत अच्छी बात है। हमारे हरियाणा में दो तरह से नुकसान होता है। एक तो फलड से और दूसरा पानी की कमी की वजह से। सातवीं योजना में हरियाणा सरकार ने मीडियम साइज और मेजर साइज की स्कीमों पर चार सौ करोड रूपए रखे हैं। जब ये स्कीमें बन

जाएंगी तो सातवें लान के अन्त तक हमारा 22 लाख हैक्टेयर से ज्यादा रकबा सिंचाई के अन्डर होगा। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये स्कीमें तो बनती रहेंगी लेकिन कुछ ऐसी स्कीमें भी हैं जो फौरी तौर पर लागू करनी जरूरी हैं। जैसे बहुत से छोटे छोटे माईनर्ज हैं, वे मंजूर तो हुए पडे हैं लेकिन उनको इम्पलीमैंटे ान नहीं होती। इसलिये मैं चाहूंगा कि छोटी स्कीमों को भी जरूर पूरा किया जाए। लाइनिंग के काम के लिए सातवों प्लान में 113 करोड रूप्ए रखे गए हैं। लेकिन यह आम आदमी की ि ाकायत है कि खाल बनाते समय उसका लैवल ठीक नहीं रखा जाता जिस वजह से कई खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता। इसलिये इस तरफ भी पूरा ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ गवर्नर महोदय ने कहा है कि सातवें प्लान में हरिजनों, बैकवर्ड क्लासिज और दूसरी जातियों के लोगों को सो ाली और इकनोमीकली ऊपर उठाने का प्रोगाम है। इस पर 34 करोड रूपया खर्च किया जाएगा। मैं यह समझता हूं कि यह पैसा बहुत कम है क्योंकि हरियाणा में इन लोगों की संख्या 30—35 लाख के करीब होगी। इस हिसाब से एक हरिजन के हिस्से बहुत कम आता है। यह रा ि ा बहुत कम है, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा रा ि ा रखी जाए। हरिजन कल्याण निगम की पूंजी बढाई जाए। इसके साथ साथ समाज कल्याण विभाग का महकमा है। उस महकमें में कोई खास काम नहीं हैं उस महकमें के पास केवल दो तीन स्कीमें हैं। बाकी सारा काम हरिजन कल्याण निगम करती है। मैं कहना चाहूंगा कि सो ाल वैल्फेयर डिपार्टमैंट में तहसील वैल्फेयर

आफिसर हैं। उस आफिसर को एक क्लर्क और एक चपडासी भी मिलना चाहिए लेकिन उसको न क्लर्क मिला हुआ है और न ही चपडासी मिला हुआ है। यदि बाहर कोई डाल ले जानी पड जाए तो उसके लिए उसके पास कोई चपडासी नहीं है। क्या वह आफिसर डाल लेकर खुद जाएगा ? ऐसा नहीं होना चाहिए कि दफतर में आफिसर हो और क्लर्क तथा चपडासी न हों। हमारे वित्त मंत्री जी मेरी इस बात को नोट करें। किसी भी तहसील वैल्फेयर आफिसर के साथ चपडासी नहीं है जो कि होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, किसी एम्पलाई के साथ डिस्क्रिमिने ान नहीं होनी चाहिये चाहे वह किसी भी महकमें का हो। आप हरियाणा सरकार के किसी भी महकमे को देख लें सभी महकमों में एम्पलाईज के साथ डिस्क्रिमिने ान किया जाता है। सो ाल वैल्फैयर डिपार्टमैंट में तहसील वैल्फेयर आफिसर्ज के ग्रेडज में फर्क है। इस महकमे में ऐसा है कि जो तहसील वैल्फेयर आफिसर मैट्रिक है उसका ग्रेड सवा पांच सौ रूपए है और जो बी0ए0 है उसका ग्रेड 600 रूपए है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहूंगा कि एक स्पै ाल कम्पोनैंट स्कीम है। उस स्कीम का टोटल खर्चा बता दिया जाता है लेकिन उस स्कीम पर किस महकमे में कितना पैसा खर्च हुआ, यह नहीं बताया जाता। यह भी नहीं बताया जाता कि इस स्कीम पर पिछले साल कितना खर्चा हुआ है और न ही यह बताया जाता है कि सातवीं पंचवर्शीय योजना में इस स्कीम पर कितना पैसा खर्च होगा। इसकी बाइफरके ान नहीं की जाती। यह नहीं बताया जाता कि इरीगे ान महकमे में इस स्कीम पर कितना

पैसा खर्च होगा और एग्रीकल्चर महकमे में इस स्कीम पर कितना पैसा खर्च होगा। दूसरे महकमे भी हैं, किसी भी महकमे के बारे में नहीं बताया जाता कि इस स्कीम पर कितना कितना पैसा खर्च होगा। जिस महकमे में इस स्कीम पर जितना पैसा खर्च होता है, उसके अलग अलग आंकडे रखने चाहिएं। हरियाणा सरकार के 26 महकमे हैं। इस बारे में सरकार को यह बताना चाहिए कि फलां महकमे में कम्पोनैंट स्कीम के लिए इतना पैसा है और दूसरे कामों के लिए इतना पैसा है। इस तरह करने से यह भी मालूम हो सकेगा कि कम्पोनैंट स्कीम के लिए जितना पैसा दिया गया था, वह उस स्कीम पर खर्च हुआ है या नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि हर महकमे में कम्पोनैंट स्कीम के लिए बजट में अलग पैसा रखा जाए। इसके अलावा, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हर बजट सै ान में कम्पोनैंट स्कीम की प्रोग्रैस रिपोर्ट भी हाउस के अन्दर आनी चाहिए ताकि हम उसको देख सकें। डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी अमर सिंह जी हाउस में बैठे हैं। आज जब मैं क्वै चन आवर में सडकों के बारे में सप्लीमैंटरी पूछ रहा था, उस समय इन्होंने मुझे एक बात कही थी कि हम आपकी मिटटी नहीं बहने देंगे लेकिन मुझे भाक है कि जिन सडकों पर मिटटी पडी हुई है वह बारि ा में बह जाएगी। यह अच्छी बात है कि इनके पास सडकें बनाने के लिए पैसा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 40 फीसदी पैसा मार्किट कमेटियां इनके पास जमा करवाएंगी। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो रोडज टूटी पडी हैं और जिन रोडज पर मिटटी डालने का काम

पूरा हो चुका है, उनको बनाने के लिए प्रैफरैंस दी जानी चाहिए। इसके अलावा, जो सडकें तहसील लैवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाती हैं, वे सिंगल रोडज हैं और बहु तंग हैं, इसलिए उन पर गाडियां पास नहीं हो सकती। मेरे हल्के में एक गोहाना से सफीदों रोड है। वह रोड इतनी तंग है कि उस रोड पर गाडियां पास नहीं हो सकती। सरकार उस रोड को वाइड करने की तरफ ध्यान दें

इसके अलावा, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं हैल्थ विभाग के बारे में बात कहना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में इस बात का जिक्र आया है कि सातवीं प्लान में 231 पी0एच0ईज0 बनाए जाएंगे और आने वाले साल में 31 प्राईमरीर हैल्थ सैंटर्ज बनाने हैं। यह सरकार की अच्दी पालिसी है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने जिला हैडक्वार्टज पर कहीं पर 500 बैड के और कहीं पर 200 बैड के होस्पीटल्ज बना दिए। क्या गांवों में रहने वाले लोग अपना इलाज करवाने के लिए उन होस्पीटल्ज में जाते हैं ? मेरा ख्याल है गांव में रहने वाला कोई आदमी अपना इलाज करवाने के लिए भाहर में नहीं जाता होगा। यह अच्छी पालिसी है कि पांच सात गांवों को मिलाच कर, जहां की 30 हजार की आबादी होती है, वहां एक पी0एच0सी0 बनेगी। (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक दो मिनट में खत्म करता हूं। यदि इस प्रकार से पी0एच0सीज0 बन जाएंगी तो देहात के लोग अपना इलाज आसानी से करवा सकेंगे। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 30 हजार की आबादी पर

पी0एच0सी0 खोलने पर सरकार 18–20 लाख रूपए लगाएगी। उसमें से जो 40 हजार रूपए गांव वालों को भरने पडेंगे वह सरकार खुद भरे क्योंकि गांव वालों के पास पैसे नहीं हैं। बहुत सी पंचायतें बहुत गरी हैं, उनके पास पैसे नहीं है इसलिए यह पैसा भी सरकार अपने पास से लगाए। गांव वाले इतने पैसे की कलैक ान भी नहीं कर सकते। गांव वाले सैंटर के लिए जमीन दे सकते हैं, पैसा नहीं दे सकते। जैसे सरकार ने पहले किया था कि वाटर सप्लाई स्कीम के लिए गांव वाले 12 परसैंट पैसा भरेंगे लेकिन वह सरकार ने माफ कर दिया है। इसी तरह से इन सैंटर्ज को खोलने पर भी गांव वालों से 40 हजार रूपए न लिए जाएं, वह भी माफ कर दिए जाएं। जो पैसा वाटर सप्लाई स्कीम पर हुए कुल खर्चे का 12 परसैंट पैसा गांव वालों से भरने के लिए सरकार ने कहा था वह माफ कर दिया है और वह पैसा सरकार खुद भरती है। उसी तरह से यह 40 हजार रूपया भी सरकार अपने पास से भरे। डिप्टी स्पीकर साहब, कटाई के बाद किसानों का अनाज मंडियों में आता है और वह अनाज सैंट्रल पूल में गया है। इस साल चारे का बहुत अभाव है। जो गेहूं की तूड़ी होती है उसका भी इस साल बहुत अभाव है जिसके कारण तूड़ी इस समय एक रूपए किलो के हिसाब से बिक रही है। एक रूपया किलो के हिसाब से भी किसानों को पूरी नहीं मिलती है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार अनाज खरीद कर स्टाक करती है उसी तरह से सरकार को चारे का भी स्टौक करना चाहिए और जिस समय किसानों को अपने प ाुओं के लिए चारे की जरूरत पडै उस

समय वह किसानों को दिया जाए। इस साल किसानों के पास चारे का बहुत अभवा है जिसके कारण उनको एक रूपया किलो के हिसाब से तूड़ी खरीदनी पड रही है, यह बडी अजीव बात है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार को चारे का स्टौक करना चाहिए ताकि समय आने पर किसनों को दिया जा सके। जैसे कई वार फल्ड का आ जाता है उस समय भी किसानों को चारे की जरूरत पडती है और कई बार किसानों की फसलें मारी जाती हैं उस समय भी उनको चारे की जरूरत पडती है। ऐसे समय में किसानों को चारा देने का इन्तजाम सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के बारे में कहना चाहूंगा। जो एग्रीकल्चर इनस्पैक्टर हैं वे गांवों में जाते ही नहीं हैं। अपने दफतरों में बैठ कर रजिस्टर भर देते हैं। वे डिमोंस्ट्रे ान नहीं करते और न ही किसानों को समझाते हैं कि कौन सा अच्छा बीज है, कौन सी खाद अच्छी है। फसलों को बीमारियों से कैसे रोका जाए। उनको गांवों में जाकर किसानों को इस बारे में बताना चाहिए लेकिन वे नहीं जाते हैं। इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जो 283 नम्बर गेहूं का बीज है उस बीज से बोई गई गेहूं में जो बथुआ पैदा होता है उसकी दवाई नहीं मिलती। वह गेहूं की फसल में बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा हो जाता है लेकिन उसको खत्म करने के लिए कोई दवाई नहीं मिलती है। यह बहुत अजीब बात है कि बथुवे को खत्म करने के लिए कोई दवाई नहीं खोज पाए हैं। इस बारे में सरकार ध्यान दे। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं

एक बात ि ाक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। प्राइमरी स्कूल खोले जाने चाहिएं ताकि देहात की लड़कियों को प्रोत्साहन मिल सके। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत से गांवों में दो दो, तीन तीन लाख रूपए चन्दे के इकटठे करके स्कूलों की बिल्डिंगें बनाई जा चुकी हैं। उन गांवों में प्राइमरी स्कूल हैं लेकिन उनको मिडल स्कूल चाहिए। जिस गांव में मिडल स्कूल है उसको हाई स्कूल चाहिए। इस बारे में गवर्नर साहब के ऐड्रैस में तो जिक्र नहीं आया लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उन स्कूलों को प्राइमरी से मिडल और मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड किया जाना चाहिए ताकि जिस प्राइमरी स्कूल के बच्चे दूसरें गांव के मिडल स्कूल में जाते हैं, वह वहीं पर पढ सकें। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे गोहाना में गवर्नमैंट कालेज हैं। दो तीन साल पहले चीफ मिनिस्टर साहब गोहाना गए थे, उस समय लोगौं ने चीफ मिनिस्टर साहब ये यह मांग की थी कि इस कालेज में साईंस की कलासें भाुरू की जानी चाहिएं। उस समय चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि इस साल से इस कालेज में साईंस की कलास भाुरू करवा देंगे। लेकिन दो तीन साल हो चुके हैं, वहां साईंस की कलास अभी तक भाुरू नहीं हो सकी है। डिप्टी स्पीकर साहब, नेहरा साहब हाउस में बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि रोहतक और सोनीपत में भी कालेजों के अन्दर साईंस की क्लासें नहीं है बच्चों को बहुत दूर जाना पडता है इसलिए गोहाना गवर्नमैंट कालेज में साईंस की क्लास जल्दी भाुरू करवाई जाए ताकि बच्चों को ज्यादा दूर न जाना पडे। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब,

मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि हरियाणा अन्दर जितने भी भूगर मिल्ज लगे हुए हैं उनको लगाने के बारे में यदि मैं यह कहूं कि यह फैसला पोलिटीकल लेवल पर लिया हुआ है तो कोई बुरी बात नहीं होगी। पोलिटीकल आदमियों ने जहां भूगर मिल लगवाना चाहा वहां पर लग्रवा लिया। जैसे पलवल में भूगर मिल है वहां पर इतना गन्ना पैदा नहीं होता है। इसलिए भूगर मिल लगाने के लिए यह क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए बल्कि क्राइटेरिया यह होना चाहिए कि जहां पर गन्ना ज्यादा हो वहां पर भूगर मिल लगना चाहिए। आप गोहाना के इलाके में सर्वे करवा कर देख लें, 10 किलोमीटर के एरिया में ही इतना गन्ना होता है कि वह भूगर मिल को आसानी से फीड कर सकता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि गोहाना में एक भूगर मिल अव य लगाया जाए। जो भूगर मिल इस समय लगे हुए हैं उनकी म ाीनरी तो उठा कर नहीं ले जाई जा सकती लेकिन नया भूगर मिल गोहाना में लगाया जा सकता है। इन भाब्दों के साथ मैं गवर्नर साहब के अभिभाशण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, 17 फरवरी को राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाशण सदन के सम्मुख रखा है जिस पर चौधरी ई वर सिंह जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खडा हुआ हूं। इस बारे में मेरे दूसरे साथियों ने बहुत सारी बातें

कहीं हैं। खासकर चौधरी भले राम जी ने सडकों पर मिटटी डाले जातने तक की बात का जिक्र अपने भाशण में किया है। इसके बाद ऐसी कोई गुजांइ ा नहीं रह जाती जिसका जिक्र यहां पर न आया हो। परन्तु मैं भी आपके जरिए कुछेक बातों का जिक्र इस अभिभाशण के बारे में करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस अभिभाशण को गौर से देखा जाये तो पता लगता है कि हमारी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम क्या क्या हैं। इस अभिभाशण में सरकार की पूरी रूप रेखा है। इस में साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं और विकास के कार्यों को किस कद्र तीव्र किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, कल मेरे एक साथी जिक्र कर रहे थे कि जो हरियाणा और पंजाब का समझौता हुआ है, वह इसमें नहीं आना चाहिए था। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह मसला दे ा के लिए और राज्य के लिए नासुर बना हुआ था। इस बारे में श्री निहाल सिंह जी ने कहा था कि यह एकोर्ड बेकार हुआ है। न तो यह दे ा के हित में है और न ही राज्य के हित में है। उनका तो यहां तक विचार था कि यह समझौता होना ही नहीं चाहिए था। ऐसे समय में वे ऐसी बातें करें, यह समझ में न आने वाली बात है। समय की नजाकत को और दे ा के हालत को देखते हुए उन्हें सोच समझ कर बात करनी चाहिए थी। जिस समय यह समझौता हुआ था उस समय दे ा के अन्दर एक अग्नि जल रही थी जिससे दे ा की आजादी के लिए खतरा पैदा हो

गया था। उस समय जो हालत पैदा हो गए थे, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि उनका सभी को अच्छी तरह से ज्ञान है। इसके बावजूद भी अगर वे यह कहें कि यह एकोर्ड होना ही नहीं चाहिए था, एक बेबुनियाद और अदूरदर्शिता की बात है। उनको चाहिए यह था कि वे इस समझौते के लिए प्रधान मंत्री जी को बधाई देते जिन्होंने ऐसे समय में एकोर्ड किया जब देश के अन्दर खतरे के बादल मण्डरा रहे थे और देश की आजादी के लिए एक बहुत भारी खतरा पैदा हो गया था। उन्होंने ऐसे समय में एकोर्ड किया जब देश में दो भाई आपस में गलत फहमियों की वजह से लड रहे थे और भारातती तत्वों द्वारा दंगा फैलाया जा रहा था। प्रधान मंत्री जी ने ऐसे समय में अपना हौसला न खो कर यह एकोर्ड किया था और जो मन मुटाव आपस में चल रहा था उसको समाप्त करवाया। इसलिए ऐसे हालात में जो एकोर्ड हुआ वह निहायत जरूरी था। यह फैसला जितना जल्दी हो सके उतना ही देश और प्रदेश के लिए अच्छा है। जहां तक फैसले की बात है, उसके बारे में सभी को मालूम है। अपोजीशन वालों का भी अपने प्रदेश और देश के प्रति उतना ही कर्तव्य है जितना रूलिंग पार्टी वालों का है। उन्होंने हरियाणा के हितों की रक्षा की बात 'रास्ता रोको आन्दोलन' करके जाहिर की है। मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने अपने प्रदेश के केस की लडाई में कोई कौताही नहीं बरती, जिसका नतीजा सबके सामने हैं। कमीशन की जो रिपोर्ट आई हैं, उसमें हरियाणा का पक्ष साफ व मजबूत हैं। किसी टैक्नीकल बात की वजह से यह फैसला सिरे

नहीं चढ पाया, वरना हरियाणा के हितों को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मैं तो यह समझता हूं कि अब हरियाणा का पक्ष पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत हुआ है। मुझे आ ा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बारे में पूरी तरह से जागरूक है और प्रधान मंत्री जी भी हरियाणा के हितों का नु कसान नहीं होने देंगें। हमारा यह सै ान चल रहा है और पार्लियामैंट का भी सै ान आ रहा है। प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि यह फैसला जल्दी से जल्दी हो जाये। इसके लिए दोनो मुख्य मंत्रियों की मीटिंग भी बुलाई गई है। उनका यह विचार है कि जितना जल्दी हो सके, इस मामले को निपटाया जाये। हमारी सरकार इस बारे में पूरी तरह से जागरूक है। सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि कहीं आपस के दबाव की वजह से कोई गलत बात न हो जाये पंजाब में दबाव की राजनीति चल रही है। अगर कहीं फैसले में कोई कौताही हुई तो उसका नतीजा हमारी सरकार को और हमें भुगतना पड सकता है। अपोजी ान के एक भाई ने कल एक बात कही थी कि अहिंसा का आन्दोलन चला कर न्याय के लिए लडना व्यायोचित है। कल मेरे इस साथी भाई से एक सच्चाई निकल गई कि हरियाणा में और पंजाब में जो लडाई चल रही है वह प्रदे ाों के हितों के लिए नहीं बल्कि कुर्सी के लिए लडी जा रही है। इन दोनों जगहों पर चल रहे आन्दोलन का मकसद दे ा के हितों से नहीं राजनीति से जुडा हुआ है। पंजाब और हरियाणा का एक फैसला स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने भी किया था। जब ये भाई सत्ता में थे तो उस समय उस फैसले को गलत

बताया करते थे लेकिन आज जब ये सत्ता में नहीं हैं तो उसी इन्दिरा गांधी जी के फैसले को उचित ठहरा रहे हैं। अब जब श्री राजीव जी ने फैसला किया तो ये कहने लगे कि इन्दिरा गांधी जी ने जो फैसला दिया था, वह लागू होना चाहिए। इनको असलियत का कुछ पता नहीं चलता। असल में राजनीतिक स्वार्थ ही इन भाइयों की असलियत है। मुझे एक बात पंजाब के बारे में कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हालात को देखते हुए कहनी पड रही हैं। पंजाब में सत्ताधरी पार्टी के अन्दर एक ऐसा ग्रुप है जो यह चाहता है कि पंजाब को कुछ न मिले। वे यह चाहते हैं कि जो कुर्सी पर बैठे हैं उनकी किसी तरह कुर्सी कमजोर हो जाये और हम उसे हथिया लें। हरियाणा में भी अपोजी ान के भाई यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के रहते हुए हरियाणा को कुछ न मिले और उसका राजनीतिक फायदा हम उठा लें। वे सोचते हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी के रहते हुए हरियाणा को कुछ मिल जाता है तो हमें नुकसान होगा। वे कोई सहयोग सरकार के कार्य में रूकावट खडी कर रहे हैं। उनकी यह मन ाा बन चुकी है कि कांग्रेस पार्टी के रहते हुए यदि फैसला हो जाता है तो उनके हाथ में कुर्सी नहीं आएगी और वे कहीं के नहीं रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्य की कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों का ताल्लुक है, उस बारे में इस अभिभाशण में साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा ने जितनी तरक्की की है, उसकी उम्मीद नहीं थी।

जो तरक्की हरियाणा ने की है वह बेमिसाल है। जिस समय हरियाणा बना था, उस समय भाायद ही कोई सोचता होगा कि हरियाणा अपने पैरों पर खडा हो सकेगा और तरक्की कर पायेगा। उस समय कहा जाता था कि हरियाणा भाायद कर्मचारियों की तन्खाह भी पूरी नहीं कर पाएगा। लैकिन आज हरियाणा दे ा के लिए एक मिसाल है। हरियाणा जब बना उस समय वह सेन्ट्रल पूल से अनाज लेकर अपना गुजारा करता था लेकिन आज वहीं हरियाणा है जो सैन्ट्रल पूल में काफी मात्रा में अनाज देता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक 7वीं योजना का ताल्लुक है उसके बारे में सभी को ज्ञात है। 7वीं योजना का व्यय लक्ष्य छठी योजना के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इससे सरकार की कल्याणकारी नीतियों और विकास ील नीतियों की मन् ाा साफ जाहिर होती है। 7वीं योजना में साल 1986–87 के लिए सरकार ने 525 करोड रूपये रखे हैं। इस पैसे में से 60 प्रति ात पैसे बिजली और सिंचाई के लिए रखे गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, किसी दे ा के लिए या प्रदे ा के लिए बिजली और पानी निहायत जरूरी है। आज चाहे इंडस्ट्री है, चाहे खेती है, सबका दारोमदार बिजली पर है। किसान के लिए तो पानी और बिजली बहुत ही जरूरी है। आज हर चीज बिजली पर निर्भर करती है। इन दोनों मदों कें लिए सरकार ने ज्यादा से ज्यादा पैसा रखने की कोि ा ा की है। यह एक अच्छा कदम है। बीस सूत्री कार्यक्रम और दूसरे कार्यक्रमों को यदि गौर से देखा जाए तो 80 फीसदी

पैसा देहात में, जहां गरीब जाना बसती है, लगाया जाता है। इस सरकार ने किसान के लिए जितना काम किया है उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम है। 1985–86 में एन0आर0ई0पी0 और आर0एल0ई0जी0पी0 के तहत 9.75 लाख और 9.58 लाख श्रम दिनों का काम, ग्रामीण आंचल में, गरीब लोगों को देने की कोि ा ा की गई। जहां तक बिजली का ताल्लुक है इस अभिभाशण में कहा गया है कि 110 मैगावाट का एक यूनिट मार्च में भाुरू हो जाएगा और दूसरा यूनिट अक्तूबर में भाुरू हो जाएगा। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, हमने अखबारों में साठे साहब का बयान पढा है जिसमें कहा गया था कि हरियाणा को अगली योजना में 850 करोड रूपया देंगे जिससे हरियाणा बिजली के मामले में आत्म निर्भर हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जलमर्गों का ताल्लुक है, लगभग साढे चौदह हजार किलोमीटर क्षेत्र में जलमार्ग पक्के कर दिए गए हैं जिसके फलस्वरूप न सिर्फ किसानों को ज्यादा पानी मिलने लगा है बल्कि सरकार की भी बचत हुई है।

डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक इंडस्ट्रियल यूनिटस का सम्बंध है, आपको पता है कि 1966 में हरियाणा में इंडस्ट्रीज की क्या हालत थी। उस वक्त हमारे यहां केवल 162 बड़े कारखाने मौजूद थे जो आज 344 के करीब हैं। इसी तरह से उस वक्त साढे चार हजार के लगभग छोटे मौजूद थे लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में जो क्रांति हुई है उसकी वजह से आज साढे साठ हजार के

करीब छोटे उद्योग हमारे प्रदे ा में मौजूद हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह खु ाी की बात है कि सरकार ग्रामीण आंचल में चार हजार से ज्यादा छोटे उद्योग लगाना चाहती है और बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार मुहैया करना चाहती है। लेकिन इस सम्बंध में मेरा निवेदन है कि उद्योग लगाने के लिए जो ऋण दिया जाता है उसका पूरा फायदा किसान के बच्चों को नहीं मिल पाता। इसके लिए सरकार कुछ ऐसा प्रबन्ध करे जिससे उन्हें ऋण मिल सके क्योंकि उनमें बेरोजगारी बहुत ज्यादा पनप रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ि ाक्षा का ताल्लुक है, इसके बारे में चौधरी भले राम जी पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि हरियाणा में काफी स्कूल हैं और यहां किसी को भी प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल की ि ाक्षा प्राप्त करने के लिए डेढ, दो या तीन मील से ज्यादा फासले पर नहीं जाना पडता। ि ाक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रदे ा का काफी नाम है लेकिन इस बारे में मैं एक छोटा सा सुझाव जरूर देना चाहूंगा। गांव में कई ऐसे स्कूल मौजूद हैं जिनकी बिल्डिंग्ज बहुत खस्ता हालत में हैं। पंचायतें और लोग भी उनके खर्चे को पूरा नहीं कर सकतीं। सरकार आीधी या पौनी मदद तो देती है लेकन उससे काम नहीं चलता। इसलिए मेरी गुजारि ा यह है कि उन स्कूलों की तरफ वि ोश ध्यान दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा इसमें दो राय नहीं कि ि ाक्षा के क्षेत्र में हमारे प्रदे ा में बहुत तरक्की हुई है लेकिन साथ ही साथ चरित्र में भी बहुत कमी आई है। इसके बारे

में मेरा सुझाव यह है कि हर स्कूल में नैतिक ि ाक्षा का पीरियड रोज लगना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसा करके हम आगे आने वाली जैनरे ान, प्रदे ा और दे ा के लिए बहुत बडा काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि भाहरों की काफी डिवैल्पमैंट हुई है। हुड्डा भाहर की जनता के लिए नो लौंस नो प्रोफिट बेस पर प्लौटस मुहैया करता है लेकिन मैं यहां पर फरीदाबाद का जिक्र करूंगा और उसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, बडै भाहर चूंकि काफी बढ गए हैं इसलिए सरकार को चाहिए कि भविश्य में इंडस्ट्रिल सैक्टर्ज और रैजिडैंन्ि ायल सैक्टर्ज छोटे भाहरों में कायम किए जाएं क्योंकि भाहर के बहुत बडा बन जाने से ला एंड आर्डर की स्थिति खराब हो जाती है और स्लम एरियाज भी बन जाते हैं। आज फरीदाबाद की भी यही हालत है। वहां स्लम एरियाज बनते जा रहे हैं। अनऔथोराइज्ड कालोनीज बन गई हैं। वह झुग्गी झोंपडियों का भाहर बन गया है। मुख्य मंत्री जी जब वहां गए थे तो मैंने इस बारे में इनसे अनुरोध किया था और इन्होंने माना था कि उनके लिए अलग कालोनी बनाई जाएगी ताकि भाहर की खूबसूरती बरकरार रखी जा सके। (घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आपकी इच्छा है कि मैं अधिक न बोलूं इसलिए अन्त में मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदे ा में जिस तरह की कल्याणकारी नीतियां चल रही हैं,

अगर उनको सही ढंग से इम्पलीमैंट किया गया तो मैं समझता हूं कि प्रदे ा तरक्की करेगा और प्रदे ा दे ा में एक आद र्ा राज्य के रूप में देखा जाएगा।

चौधरी साहब सिंह सैनी (थानेसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय द्वारा 17 फरवरी 1986 को दिए गए अभिभाशण और उसके सम्बन्ध में चौधरी ई वर सिंह जी द्वारा जो प्रस्ताव सदन में रखा गया है, उसका समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में जो कार्य हुए हैं और जो आगे होने प्रस्तावित हैं, उनकी चर्चा अभिभाशण में विस्तार से की गई है। सबसे पहले मैं कानून और व्यवस्था के बारे में अर्ज करूंगा। आप जानते हैं कि जब हमारे पडौसी राज्य में अ ाांति थी, हमारे प्रदे ा में उस समय पूरे तौर पर भाांति कायम रही। (**इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।**) अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पुलिस के कर्मचारियों ने कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मासिवाए कुछ छुटपुट घटनाओं के कोई वि ोश अप्रिय घटना हमारे प्रद्रे ा में नहीं घटी जिससे कोई अ ाांति यहां फैलती। हां, दो चार घटनाएं यहां हुई थी लेकिन दोशी व्यक्तियों को तुरन्त ही पकड लिया गया था और उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है। यह बहुत बडी बात है और इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र हैं

अध्यक्ष महोदय, पंजाब और हरियाणा का चण्डीगढ के बदले हरियाणा को मिलने वाले कुछ गांवों के बारे में और नहर

के बारे में जो झगडा चल रहा है, उसके विशय में प्रधान मंत्री जी ने जो समझौता लौंगोवाल जी के साथ किया है उसका स्वागत राज्य में ही नहीं बल्कि सारे दे ा में सभी नेताओं ने, जिनमें अपोजी ान के बडे बडे नेतागण भी भाामिल हैं, किया है क्योंकि यह समझौता उस समय हुआ जिस समय दे ा में कुछ लोगों ने बहुत ही अ ाांति फैला रखी थी और यह खतरा हो रहा था कि हमारा दे ा टूट न जाये या हमारे राज्य टूट न जाये। उस समय जो समझौता हुआ यह कोई छोटी बात नहीं थी। आजकल कुछ विरोधी पक्ष के भाई यह कह कर लोगों की भावनाओं को उभार रहे हैं कि हरियाणा के साथ अहित हुआ है। वे लोगों को भडकाने की कोि ा ा करते हैं। आप इसी बात से अन्दाजा लगाएं कि विरोधी पक्ष के बडे बडे नेता जो केन्द्र में यानि दिल्ली में बैठे हैं, वे इस समझौते का समर्थन करते हैं और जो राज्यों में बैठे हैं वे राजनैतिक लाभ उठाने के लिए उठाने के लिए इस समझौते का विरोध करते हैं। यह इनका अनु ाासन है। यहां कुछ बात करें और वहां कुछ करें। राजनैतिक लाभ उठाने के सिवाए इनका दूसरा कोई मकसद नहीं है। जब दे ा में भाान्ति होगी तो वे भी सुरक्षित रह सकते हैं और अगर अ ाान्ति होती है, झगड़े होते हैं तो कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता इसलिए यह जो फैसला हुआ है इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाये। कुछ रूकावटें पैदा हो रही हैं जो इधर उधर की बातों से हो रही हैं। आप अखबारों में भी पढते हैं कि पंजाब के भाई यह नहीं चाहते कि हरियाणा को पानी मिले या जो हिन्दी भाशी क्षेत्र मैथ्यू कमी ान ने बताए हैं, वे

हरियाणा को मिलें। हमारी सरकार और हमारी पार्टी इस मसले के लिए लड रही हैं। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने हरियाणा का पक्ष बहुत ही अच्छे ढंग से पे ा किया है। मैथ्यू कमी ान के सामने हरियाणा का केस पे ा करने के लिए जो कमेटी बनी थी, उसने बडे ही अच्छे ढंग से काम किया। उस कमेटी के सुरजेवाला साहब भी मैम्बर थे। वे सभी बधाई के पात्र हैं। उस समिति ने मैथयु कमी ान के सामने अच्छे ढंग से केस पे ा किया तभी तो 83 गांव और दो नहर हिन्दी भाशी क्षेत्र माने गए हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसी तरह से नहर का भी मसला बहुत अहम है। नहर के पानी के लिए अभी कमी ान मुकर्रर हुआ है। मुझे वि वास है कि हमारी सरकार वहां भी अपने केस को बडे अच्छे ढंग से पे ा करेंगी। हमारी सरकार को यह भी पता है कि पंजाब सरकार इस नहर को बनाने में रूचि नहीं रखती, इसलिए केन्द्र सरकार को इसे अपने हाथ में लेना चाहिए या किसी दूसरी एजेन्सी से यह काम कराया जाना चाहिए ताकि हरियाणा को जो पानी मिलने वाला है, वह मिल सके। इसके अतिरिक्त विरोधी पक्ष के भाई नाजायज फायदा उठाने की कोि ाश करते हैं। वे कहते हैं कि 1–7–85 को जो पानी पंजाब इस्तेमाल कर रहा था, वहीं पानी उसे मिलेगा यानि उससे कम नहीं किया जाएगा। यह बात केवल हमारे विरोधी पक्ष के भाई जनता को भडकाने के लिए कहते हैं। जैसा कि हमें बताया गया है कि पंजाब उतना पानी इस्तेमाल नहीं कर रहा है जितना वह बता रहा है। जो पानी फालतू रहेगा वह हमारे हिस्से में आयेगा। अगर फालतू पानी होता

है तो हरियाणा को अव य ही पूरा भोयर मिलेगा। हमारी सरकार की तरफ से पानी लेने की पूरी कोि ा ा जारी है।

इसके अतिरिक्त राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाशण में खेती को बढावा देने के लिए भी कुछ योजनाओं का जिक्र किया है। स्पीकर साहब, सिंचाई का सबसे बडा साधन नहर और नलकूप होते हैं। कुछ जिलों में नहर का पानी नहीं मिलता, केवल नलकूपों से ही वे अपनी खेती बाडी करते हैं। इस ऐड्रैस में बताया गया है कि जहां नहर के पानी की कमी है वहां नहर का पानी दिया जायेगा। चौधरी ई वर सिंह जी ने बताया था कि सिंचाई के अधिक से अधिक साधन जुटाए जाने के लिए हमारी सरकार के पूरे प्रयत्न हैं और जो बिजली की कमी है उसे भी पूरा करने की भी कोि ा ा की जा रही है। उसमें हमारे कुरूक्षेत्र जिले का भी जिक्र आया। मुझे आ ाा है कि सरकार इस काम को जल्दी करके लोगों की सहायत पहुंचायेगी। आप जातने हैं कि सिंचाई के बिना कृशि नहीं हो सकती, पैदावार नहीं बढ सकती इसलिए अस ओर खासतौर पर ध्यान देने की आव यकता है। स्पीकर साहब, सिंचाई के साधनों के लिए 1986–87 के साल में 90 करोड रूपया रखा गया है, यह बहुत अच्छी बात हमारी सरकार ने की है। इसी तरह से खेती के लिए बिजली की भी आव यकता होती है। टयूबवैल्ज के लिए बिजली की आव यकता होती है इसलिए हमारी सरकार ने बिजली की आव यकता होती है इसलिए हमारी सरकार ने बिजली की अलग अलग तरीकों से

पैदावार बढाने तथा थर्मल प्लान्ट लगाने की योजना बनाई है। यमुनानगर और दूसरी जगहों पर हाईडल प्रोजैक्ट लगाने की स्कीम हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन प्रोजैक्ट खडे हो जाते हैं तो बहुत सुविधा मिलेगी। जहां पर नहरों की कमी है या बिजली की कमी है, उसे हमारी सरकार पूरा करने का प्रयत्न करेगी। कुरूक्षेत्र जिले में नहरों की कमी है इसलिए वहां पर नहर बनायी जायेगी और जो टयूबवैल्ज पर बिजली प्रयोग होती है, उसको दूसरी जगह इस्तेमाल किया जा सकेगा। सरकार चाहती है कि बिजली की बढौतरी की जाये।

अध्यक्ष महोदय, खेती के क्षेत्र में हमारे प्रदे ा ने बहुत तरक्की की है। मैं समझता हूं कि कुरूक्षेत्र जिला खेती के मामले में सबसे आगे है। यहां गेहूं और धान का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि यहां पर पानी की कमी है। यहां पर बिजली भी कम मिलती है और नहरों के पानी की सुविधा भी नहीं है। अगर यहां पानी मिल जाये तो और भी उत्पादन बढाया जा सकता है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि नहरों के बनाने में प्राथमिकता दे कर सिंचाई के साधनों का प्रावधान किया जाये ताकि धान और गेहूं की पैदावार और अधिक हो सके।

स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने कई कल्याणकारी योजनायें भी आरम्भी की हैं। इन कल्याणकारी नीतियों में बीस सूत्री प्रोग्राम भी भाामिल है। हमारी सरकार ने कमजोर वर्ग के

लोंगों को बहुत सहायता दी है और अलग अलग रूप में गरीब लोगौं को कर्जा दिया जाता है लेकिन जैसा कि हमारे और साथी भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो बोर्ड, निगम और कार्पोरे ान्ज बनी हुई हैं वे तो कर्जा मंजूर कर देती हैं। परन्तु बैंकों में आकर दिक्कत आती है। जो हमारे नै ानेलाइज्ड बैंक हैं वे कर्जा जल्दी से नहीं देते हैं। वहां पर लोगों को काफी परे ाानी का सामना करना पडता है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस विशय में सरकार की ओर से समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए कि जब हमारी कोर्पोरे ान या बोर्ड लोन मंजूर कर देते हैं तो फिर वहां पर क्यों दिक्कत होती है। सरकार को ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए या ऐसी एजेन्सी के थ्रू कर्जा दिया जाना चाहिए जिससे उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न आये।

अध्यक्ष महोदय, मैं एजूके ान के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। यह बिल्कुल ठीक बात है कि हमारी सरकार ि ाक्षा की तरफ काफी सजग है। हमारे देहात में, सभी गांवों में स्कूल हैं लेकिन इस बारे में थोडा सा सुझाव देना चाहता हूं। जैसे भाई हुकम सिंह जी ने भी कहा था कि लडकियों के स्कूलों को प्राइमरी से मिडल या हाई स्कूल बनाया जाये। लडके और लडकियां प्राइमरी तक तो एक साथ पढ सकते हैं परन्तु प्राइमरी के बाद एजुके ान नहीं चलनी चाहिए। इसलिए प्राइमरी के बाद लडकियों के लिए अलग से मिडल या हाई स्कूल बनाये जाने चाहिएं ताकि किसी लडकी को दिक्कत न हो। दूसरे लडकियां

अपनें गांव के स्कूल से दूसरे गांव के दूर के स्कूल में जाना भी पसन्द नहीं करती हैं। इसलिए दो किलोमीटर से उन्हें ज्यादा न जाना पडे। उनके लिए मिडल या हाई स्कूल बनाये जायें ताकि लडकियों की एजूके ान ज्यादा बढ सके। स्पीकर साहब, हमारी सरकार हैल्थ विभाग की ओर भी काफी ध्यान दे रही हैं। सरकार ने काफी डिस्पैंसरियां खोली हैं और आगे भी खोलने जा रही हैं। इन भाब्दों के साथ मैं इस अभिभाध्या का समर्थन करता हूं।

श्रीमती भाारदा रानी (बल्लभगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहलत तो मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे समय दिया। अध्यक्ष महोदय, चौधरी ई वर सिंह जी ने जो प्रस्ताव राज्यपाल के अभिभाशण को स्वीकार करने का और उनका धन्यवाद करने का रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खडी हुई हूं। यह अभिभाशण हमारी एक ज्वलन्त समस्या से प्रारम्भ होता है। उस समस्या को लेकर भाुरू होता है जिसकी और सार वि व की आंखें लगी हुई हैं और जो बहुत लम्बे समय से, काफी लम्बे अन्तराल से चली आ रही हैं। इसने बहुत से लोगों को प्रभावित किया है और हमारे प्रधान मंत्री जी को भी प्रभावित किया। मैं अपनी सरकार को बहुत ज्यादा बधाई देती हूं कि इसने रियाणा के हितों के लिये अपना जो स्टैंड था, उसको बहुत सही तरीके से दूसरपी सरकार के सामने, केन्द्रीय सरकार के सामने और आयोग के सामने रखा। हमारे मुख्य मंत्री जी, ने वि ोश तौर पर पब्लिक मीटिंग्ज में अथवा जहां कहीं भी आव यकता पडी,

बहुत जोर से अपने स्टैंड को स्ट्रैस कियाव, बहुत ज्यादा जोर से हरियाणा के हितों को सामने रखा और कभी भी इस बारे में झुकाव नहीं खाया। एक बार तो हम सब लोग ए0आई0सी0सी0 की मीटिंग में मौजूद थे। वहां भी हमारे मुख्य मंत्री जी ने जिस तरीके से अपना स्टैंड रखा, सारे दे ा ने उसकी सराहना की। सारे दे ा के अलावा ए0आई0सी0सी0 ने भी उसकी सराहना की। हर व्यक्ति ने उसकी सराहना की। उन्होंने हर व्यक्ति का और खास तौर पर हरियाणावासियों का सिर गौरव से ऊंचा करवा दिया, अपोजी ान वाले लोग इस बारे में चहो कुछ भी कहें। वे सोचते होंगे कि इस स्टैंड को मजबूती से रखने के लिये उनका योगदान है किन्तु हमारी सरकार जो भ्रुरू से ही स्टैंड लेती चली आ रही है, हमारी पार्टी स्टैंड लेती चली आ रही है, इसका ज्यादा योगदान है। अपोजी ान वालों ने तो कुछ भ्ाोर भाराबा मचाना था क्योंकि उनको इलैक ान नजर आ रहा है। उन्होंनें कुछ तो करना ही था। पानी के मामले में भी हमारी सरकार बहुत मजबूती से लड रही है। इसी का परिणाम है कि आज भारत सरकार ने इस चीज को माना है कि हमारी एस0वाई0एल0 के निम्रण का काम वह अपने हाथ में ले। इस चीज पर वह विचार कर रही है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि कम से कम मुझे इतना आ वासन तो मिलना चाहिये कि जब पानी हरियाणा में आयेगा तो फरीदाबाद का जो एरिड एरिया है, जिसमें से गुड़गांव कैनाल भी नहीं निकलती, इसको भी कुछ थोडा बहुत 2–4 क्यूसिक्स पानी जरूर मिलेगा। कम से कम यह तसल्ली तो हमें मिलनी चाहिये। आज भी जब मैंने

आई0पी0एम0 साहब से क्वै चन पूछा तो उन्होंने कहा कि गुडगांव कैनाल में तो पानी जायेगा मगर फरीदाबाद के एरिया के लियें वह पानी नहीं होगा। (व्यवधान) आपने यह कहा है कि जो गुडगांव कैनाल के तहत फरीदाबाद का एरिया पडता है, उसको तो मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। गुडगांव कैनाल में फरीदाबाद का एरिया तो बहुत ही कम पडता हैं (व्यवधान) मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं कि इन्होंने आ वासन दे दिया है। मैं इसके लिये इनका एक बार फिर धन्यवाद करती हूं। इसके बाद जो स्टेट में आज सबसे ज्यादा वाईटल प्रोब्लम है, वह बिजली की है। आज कहीं पर चले जाइये, हर तरफ बिजली के लिये त्राहि त्राहि मची हुई है। खास तौर से फरीदाबाद में ऐसी हालत है। वहां पर इंडस्ट्रीज बहुत लगी हुई है। फरीदाबाद हरियाणा का मानचैस्टर कहलाता है लेकिन वहां पर भी आजकल बिजली की कमी है। यह समस्या बडे ही भयंकर रूप में सामने आ रही है। आज पहली बार मैंने गवर्नर एड्रैस में पढा है कि इसके लिये सरकार ने बहुत सारी स्कीमें बनाई हैं। कई कई मैगावाट के थर्मल पावर स्टे ान, परमाणु बिजली घर और छोटे –2 हाइड्रोइलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट बनाने का प्रस्ताव है। इसी तरीके से पलवल, भिवानी वगैरा में नयी योजना के अन्तर्गत 210 मैगावाट की थर्मल पावर स्टे ान बनाने की बात कही गयी है। यह पढकर मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई है कि चलो, अब नहीं तो कुछ समय बाद ही सही, हमारी बिजली की समसरूा हल हो जायेगी। मैं हरियाणा सरकार से यह चाहूंगी कि इन योजनाओं को मजबूती के साथ चलाया जाये। इनके ऊपर

सरकार डटी रहे और काम चलता रहना चाहिये, चाहे हमें दूसरी चीजों के अन्दर कटौती भी करनी पड जोय तो भी कोई बात नहीं है। जब राज्य के लोगों की हालत अच्छी होगी तो दूसरे काम होते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि बिजली उत्पादन की बात तो इसमें कही गयी है लेकिन ट्रांसफार्मर्ज की भी समस्या है, जिसका जिक्र एड्रैस में नही है। आज जितनी बिजली हमारे पास है, उसके लिये यह समस्या मुंह बाये खडी है। ट्रांसफार्मर्ज के बारे में गवर्नर एड्रैस में कोई जिक्र नहीं है। मेरा अनुरोघ है कि अगर ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफार्मर्ज बनाने की, उनको लगाने की और उनकी कमी को पूरा करने की बात भी हल हो जाये तो जितनी बिजली आज हमारे पास है, हम उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। और जितनी बिजली आगे हमें मिलती जायेगी उसके लिये भी हमें ट्रांसफार्मर्ज की जरूरत पडेगी। इनके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, कुछ और चीजें भी मैं कहना चाहती हूं। ला एण्ड आर्डर के बारे में हमारी स्थिति पडौसी राज्य के मुकाबले में बहुत अच्छी है। इसके लिये मैं अपनी सरकार को और राज्यपाल महोदय को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देती हूं। अध्यक्ष महोदय, इस एड्रैस में मेवाल विकास बोर्ड का भी जिक्र आया है। यह बहुत खु ाी की बात है कि मेवात जो हमारा पिछडा हुआ एरिया है, वहां पर मेवात बोर्ड बना कर उसका विकास किया जाये। यह तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। लेकिन इसी तरह

का एक और पिछडा हुआ इलाका हरियाणा के अन्दर है। उसे खादर का एरिया कहा जाता है। मैं यह नहीं कहती कि उसमें मेरा ही इलाका है। उसके अन्दर दूसरे इलाके भी भाामिल हैं। पहले इस एरिया के विकास के लिये खादर विकास बोर्ड बनाने की बात कही गयी थी किन्तु वह आज तक नहीं बना। अगर वह बोर्ड बन जाता तो जिस तरीके से मेवात का विकास हो रहा है, उसी तरीके से खादर का भी विकास हो जाता। अध्यक्ष महोदय, वहां पर बडी समस्याएं हैं, मैं तो यह चाहती हूं कि आप कभी वहां पर चलें और जाकर दिल्ली की नाम के नीचे और फरीदाबाद के रो ान एरिया के इतना निकट लोग कैसे रह रहे हैं। उनके आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई सडक नही है। बिजली भी नहीं है। अगर बिजली के खम्भे कहीं पर लगे भी हुए हैं तो वहां पर बिजली वाले ठीक करने के लये जा ही नहीं सकते। अगर डिस्पैंसरी बना दी जाती है तो डाक्टर्ज नहीं जाएंगे। मेरा कहने को मतलब यह है कि वहां पर कोई भी ऐसा काम करने का फायदा नहीं है। अगर वहां मंडी बना दी जाये तो कोई अधिकारी नहीं जायेगा और न चैंकिंग करने के लिये कोई जायेगा। मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। इन्होंने भाायद चैक भी करवाया है। वहां पर एक डिस्पैंसरी है। उसमें कम्पाऊंडर भी नहीं जाता। कर्मचारी जिसकी वे वहां पर डियूटी लगा देते हैं, वे अपनी झूठ मूठ की हाजरी लगा देते हैं और सारा दिन गायब रहते हैं। पब्लिक हैथ्थ की स्कीमों के बारे में भी ऐड्रैस में कुछ कहा गया है। पीने के पानी की जो समस्या है, उसको सरकार ने सैंट्रल गवर्नमैंट की मदद से बहुत अच्छी

तरह से दूर किया है। मैं यह मानती हूं कि यह समस्या बहुत बडी है। सरकार ने इस तरफ काफी ध्यान दिया है और लोगों को काफी राहत मिली हइै। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पहले नौन प्रौब्लम विलेजिज होते थे लेकिन अब वे प्रौब्लम विलेजिज बन गये हैं। एम0आई0टी0सी0 के टयूबवैल्ज के कारण और नहर में पानी कम होने के कारण, मैं यह चाहती हूं कि कोई नई स्कीम बनाकर इन गांवों की समस्या को भी दूर किया जाये।

हुडडा के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैं मानती हूं कि हुडडा ने बहुत अच्छा काम किया है। पंचकूला बहुत अच्छा बसाया है। फरीदाबाद में भी बहुत अच्छा काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात मैंने कल भी कही थी कि कुछ एरिया ऐसा होता है जो प्लान के मुताबिक ईयरमार्क होता है, उसको मेनटेन करना चाहिये। जैसे मान लीजिये किसी जगह पर ग्रीन बैल्ट छोडी जाती है, उसको मेनटेन करना तो हुडडा का फर्ज है। आपने जी0टी0 रोड के साथ साथ ओल्ड फरीदाबाद से बाटा मोड तक और उससे आगे वाई0एम0सी0ए0 तक ग्रीन बैल्ट छोडी थीं वहां पर आज जाकर देख लीजिये क्या हालत है, हुडडा के किसी भी अधिकारी को भेज दीजिये। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को दिखाया भी था कि देखिये, क्या हालत है। उन्होंने मान भी लिया था। बल्लभगढ की हालत आज चारों तरफ खराब है। पहले जो ग्रीन बैल्ट छोडी गयी थी। वह अब बूडा बैल्ट बनी हुई है, वहां पर 5–7 साल से बहुत बुरा हाल है। अध्यक्ष महोदय, एक जगह पर तो पूरा

गांव ही बस गया है और उसका नाम अजरौंदी है। पहले वहां पर एक भी घर नहीं होता था लेकिन आज जाकर देखें, ग्रीन बैल्ट के अन्दर वह पूरा गांव बस गया है। यह तो आपकी खाली जगह का हाल है। ग्रीन बैल्ट को मेनटेन करना चाहिये। इसके आगे बाटा मोड पर देख लें वहां कूडा घर बना हुआ है। वहां पर तमाम कूडा डमप होता है। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, सैक्टर 6 के अन्दर एक पार्क छोडा गया था। आज उसमेकं 800–900 गज के प्लाट काट कर बेच दिये गये हैं। अगर मुख्य मंत्री जी ने अपने आदे ा से दिये हैं तब तो मुझे कोई एतराज नहीं है। वे चेयरमैन हैं हुडडा के बारे में उनको पूरा अधिकार है कि वे जिस तरीके से चाहें, प्लानिंग करें या प्लाट काट कर दें। लेकिन मैं यह चाहूंगी कि मुख्य मंत्री जी इस बात की इंक्वायरी करवा लें कि वह उनके आदे ा से दिये गये हैं या नहीं। चाहिये तो यह था कि उसके प्लाटस न काटते क्योंकि फैक्ट्री वर्कर्ज के बैठने के लिए वही एक मात्र जगह थी।

इसके बाद मैं एक बात पुलों की बाबत भी कहना चाहूंगी। अभी कहा गया कि 39 पुल तो निर्माणाधनी और 33 और बनाने वाले हैं। मैं यह चाहूंगी कि उनमें एक जहर नाले का पुल भी जोड लिया जाये। जहां इतने पुल बनने हैं, वहां एक जहर नाले का पुल भी बना दिया जाये तो इससे खादर के जो 12–15 गांव हैं, उनको कुछ सुविधा होगी। वहां वहीं एक मात्र पुल बनना है, उसके बनने से हालत में सुधार हो जायेगा और लोगौं को

राहत मिलेगी। मैं समझती हूं कि पुलौं का बहुत अच्छा काम हरियाणा के अन्दर हुआ है। अगर हरियाणा के उस इलाके के अन्दर एक पुल यह भी बना दिया जाये तो लोग यह महसूस करेंगे कि हरियाणा सरकार के अन्दर उनका भी कुछ भाग है।

17.00 बजे।

अध्यक्ष महोदय, हमारी अर्थ व्यवस्था में 4.1 प्रति ात की वृद्धि हुई है, यह बडी प्रसन्नता की बात है। इस वृद्धि को करने में फरीदाबाद और बल्लभगढ जो इंडस्ट्रियल टाउन्ज हैं, उनका बडा भारी योगदान है। इसलिए इस वृद्धि का कुछ हिस्स तो वहां पर खर्च किया जाना चाहिए। इन भाब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करती हूं और इस अभिभाशण का समर्थन करती हूं।

चौधरी लीला कृश्ण (फतेहाबाद): स्पीकर साहब, 17 फरवरी को राज्यपाल महोदयन ने इस हाउस में जो अभिभाशण दिया और उस सम्बन्ध में जो मो ान आफ थैंक्स आया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं। स्पीकर साहब, बहुत से सदस्यों ने कई मुद्दों पर प्रका ा डाला है। मैं समझता हूं कि इस अभिभाशण में जो कुछ कहा गया है वह सरकार की पूरी नीति को द ार्ाता हैं मेरे कई साथियों ने ला एण्ड आर्डर और एस0वाई0एल0 की बात की है। मैं इस बारे में संक्षेप में ही कहूंगा। स्पीकर साहब, लोग कुछ निरा ा थे और अब भी निरा ा हैं। लोग अभी भी कहते हैं

कि चण्डीगढ एक महीने में चला जाएगा या दो महीने में चला जाएगा। मैं उनसे एक सवाल करता हूं कि जब चण्डीगढ को ट्रांसफर करने के लिए भारत सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी और कहा गया था कि पंजाब का गवर्नर यहां झंडा लहरायेगा तो इस सम्बंध में कार्ड बांटे गए, दीपमाला मनाने का प्रोग्राम बन गया था। लेकिन हमारे मुख्य मंत्री की वकालत, कठिन परिश्रम और हरियाणा के सारे विधायकों का इस मामले में एक जुट होने के कारण सारा प्लान एक सैकिण्ड में धरा रह गया। स्पीकर साहब, अगर चण्डीगढ जाता तो 26 जनवरी को चला जाता। जब तक हमारीसारी मांगें पूरी नहीं होती चण्डीगढ पंजाब को नहीं जा सकता ? स्पीकर साहब, इसमें हमारी जीत हुई है और आगे भी हमारी जीत होती रहेगी। यह जीत मुख्य मंत्री की है। स्पीकर साहब, कई मित्रों ने कहा है कि हमें पानी नहीं मिलेगा और करोडों रूपया बेकार में खर्च किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में हमें आ ाावादी होना चाहिए। इस मामले में हमारी सरकार और मुख्य मंत्री जी दृढ़ संकल्प हैं। इसलिए पानी अव य मिलेगा और हरियाणा का किसान सुखी होगा तथा अनाज का भंडार बढेगा। हमारे साथियों को इस बात का प्रचार करना चाहिए कि पानी हमें अव य मिलेगा। कोई ताकत नहीं जो हमें पानी न दे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अबोहर और फाजिल्का तथा उसके साथ के 83 गांव भी हमें जरूर मिलेंगे। स्पीकर साहब, जिन बातों का राज्यपाल महोदय ने इस अभिभाशण में जिक्र किया है वह हरियाणा सरकार की कारगुजारियों का निचोड है। हमारा

हरियाणा दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। हरियाणा प्रदे ा सारे दे ा में हर फील्ड में प्रथम बिना जा रहा है और आगे भी प्रथम गिना जाएगा। इसका श्रेय हमारी सरकार को जाता है।

स्पीकर साहब, इस अभिभाशण में बिजली का जिक्र किया गया है। कहा गया है कि कई जगह पर प्लांटस लगाए जाएगें। थर्मल प्लांट पानीपत का विस्तार किया जाएगा। अगर यह सारी योजना पूरी हो जाती है तो हरियाणा के किसान इस सरकार के ऋणी होंगे और एहसानमंद होंगें। स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहता हूं। मैंने एक काल अटैं ान मो ान दिया था, पता नहीं उसका क्या हुआ। मैं फतेहाबाद के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे ऊपर एक मुसीबत आई। हमारे बिजली के ट्रांसफारमर्ज खत्म हो गए। बिजली न मिलने के कारण किसान दुखी हैं। हमारे यहां गांवों के लोग दो दो, चार चार दिन तक अंधेरे में रहते हैं क्योंकि उनको बिजली नहीं मिलती। मैं चौधरी सुरजेवाला जी से पर्सनली मिला था और मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया था कि हमारे यहां के लोग बहुत दुखी हैं। वहां पर बिजाई नहीं हो पा रही है और वहां के किसान विद्रोह के लिए तैयार हैं। आप उनको बिजली दीजिए। जब हम ट्रांसफारमर्ज के लिए जाते हैं तो जवाब मिलता है कि जब आएंगे तो मिलेंगे। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि कम से कम चालीस ट्रांसफारमर्ज अगर हमको मिल जाएं तो कुछ न कुछ किसानों को कम्पनसेट किया जा सकता है। स्पीकर साहब, जब कभी किसान के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमारी

सरकार उनकी मदद करने के लिए हमे ाा अग्रसर रहती है, उनको मुआवजा देती है, वसूलियांस मुल्तवी करती है और सब तरह की मदद यह सरकार किसानों की करती है। किसानों को दुखी देखकर हमारे मुख्य मंत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्पीकर साहब, पिछले सै ान में इन्होंने वायदा किया था कि जिन किसानों के घर गिर गए हैं, उनको भारत सरकार से 2500—2500 रूपए दिलवाऊंगा और जिन किसानों की फसल नश्ट हुई हैं उनको कम्पनसे ान दिलवाऊंगा। मुझे पता नहीं इन्होंने इसका कितना हल निकाला है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कोि ा ा करके सैन्टर से हमारे यहां के लोगों को सहायता दिलवाई जाए।

स्पीकर साहब, इस ऐड्रैस में सिंचाई के बारे में जिक्र आया है कि सिंचाई की नई स्कीमें चालू की जाएंगी। हमारे यहां जवाहर लाल कैनाल और लोहारू लिफट इरीगे ान स्कीम पर काफी काम हो चुका है। अगर एस0वाई0एल0 से पानी मिल गया तो और अधिक जमीन में सिंचाई हो सकेगी। स्पीकर साहब, मेरी कांस्टीच्यूएंसी की एक तकलीफ है। फतेहाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी बहुत लम्बी है। मैंने पिछले साल निवेदन किया था कि उसमें लाइनिंग नहीं हुई है और उसमें कुई फाल हैं। अगर फाल्ज को ऊंचा कर दिया जाए तो हजारों एकड जमीन में सिंचाई हो सकती है। स्पीकर साहब, फतेहाबाद के लिए कई स्कीम्ज बनी हैं। लेकिन पूरी नहीं हुई।

स्पीकर साहब, इसमें सडक्कों का जिक्र आया है और कहा गया है कि सरकार ने 98 प्रति ात सडकों को पक्का करने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार कहा है कि हमारे यहां एक माडल टाउन है जिसको बने हुए 25 साल हो गए हैं लेकिन वहां एक भी सडक ऐसी नहीं है जो चलने के योग्य हो। सडक्कों के बारे में जब हम कमेटी के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि हुडडा सडक बनाएगा। जब हुडडा के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि ये सडकें कमेटी को ट्रांसफर कर दी हैं। स्पीकर साहब, उन सडकों की बुरी हालत है। वहां पर बडी बडी और अच्छी बिल्डिंगग्ज हैं लेकिन हालत यह है कि वहां एक स्कूटर भी नहीं चल सकता। मेरी प्रार्थना है कि माडल टाउन को प्रायरिटी देकर उसकी द ाा सुधारी जाए। स्पीकर साहब, मेरी एक और प्रार्थना है कि फतेहाबाद में बाई पास का प्रावधान था। पता नहीं उस बाई पास का क्या हुआ ? फतेहाबाद ने ानल हाईवे पर है इसलिए बाई पास का होना जरूरी है। अनएम्पलायमैंट को दूर करने की जो स्कीम है, यह बहुत अच्छी है लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। सरकार ने कहा है कि बेंरोजगार नौजवानों को पच्चीस हजार रूपये की इमदाद दी जाएगी। यह बहुत अच्दी बात है लेकिन मैं सरकार के नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि जिन लोगों की सिफारि ा है या जिन लोगों का काम चल रहा है वे ही इस रूपए को ले जाते हैं और जो लडके अनएम्पलाएड हैं, उनको यह रूपया नहीं मिलता। सरकार की आरे से तो 25 हजार रूपया देने का प्रोविजन है लेकिन उनको पूरा रूपया नहीं दिया जाता।

किसी को दस हजार मिल जाता है, किसी को पन्द्रह हजार मिल जाता है। उस रूपए का प्रौपर यूटिलाइजे ान नहीं होता। कोई अपनी बहन की भाादी में लगा देता है और कोई कहीं और खर्च कर देता है। आपकी तरफ से हुकम होना चाहिए कि अनएम्पलाएड को जो कर्जा दिया जाए, उसमें से एक रूपए की भी कटौती न की जाए वरना इस स्कीम का कोई फायदा नहीं है।

स्पीकर साहब, अब मैं सो ाल वैल्फेयर विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह विभाग अनाथों, डेस्टीच्यूटस, अपंगों व अन्य गरीब लोगों को मदद देता है। लेकिन लोगों को पैन ान लेने के लिये बडी फारमैलिटीज का सामना करना पडता है जिससे उनका काफी समय खराब हो जाता है। फार्मर्ज वगैरह भी जल्दी उपलबध नहीं होते हैं। फिर कभी तहसीलदार से कभी सम्बंधित एस–डी–ओज से, कभी डाक्टर से फारमैलिटीज कम्पलीट करवानी पडती हैं। मुझे बडे ही दुख के साथ कहना पडता है कि ओल्ड ऐज पैं ान तक सैंक ान होती हैं, जब आदमी मर जाता है। मेरे पास इस तरह की बीसियों मिसालें हैं। इसलिये मेरी सरकार से रिकवैस्ट है, नम्र निवेदन है कि इस बारे में विभाग के तौर तरीके को बहुत सरल बनाया जाए और लोगों को पैं ान जल्दी स्वीकृत की जाए ताकि बूढे, गरीब, अपंग लोगों को सही रूप में सरकार से फायदा मिल सके और उनको इस विभाग के बार बार चक्कर न लगाने पडें।

इसके बाद मैं टूरिज्म के बारे में कहना चाहता हूं। हरियाणा टूरिजम की जितनी तारीफ की जाए, थोडी है लेकिन इसके साथ साथ मैं सरकार से रिकवैस्ट करूंगा कि फतेहाबाद में एक टूरिस्ट कम्पलैक्स बनाया जाए। यह हलका सी0एम0 साहब का अपना हलका है, इसको प्रयारिटी दी जाए।

अध्यक्ष महोदय, अन एम्पलायमैंट का मसला बडा ही अहम है। आज हमारे प्रदे ा में लाखों नवयुवक बेरोजगार फिरते हैं। इसके लिए सरकार के पास काफी स्कीमें हैं। उनको पैसे की मदद दी जाए ताकि वे काम सीख कर अपना काम चला सकें। एक और प्रार्थना है कि फतेहाबाद में एक आई0टी0आई0 भी खोला जाए। इन लफजों के साथ मैं स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद करता हूं और राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर श्री ई वर सिंह जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है का समर्थन करता हुआ अपना स्थान लेता हूं। जय हिन्द!

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 17 फरवीर 1986 को सदन में अपना अभिभाशण दिया और सरकार की नीतियों सरकार की पालिसीज और सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं, उन पर बहुत तफसील के साथ रो ानी डाली। माननीय सदस्यों ने सदस्य महोदय के अभिभाशण को पढा भी होगा। बोलने वाले सदस्यों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं, चर्चाएं की और सरकार के कामों की सराहना भी की। अध्यक्ष महोदय, पहले मैं दो बातों की तरफ सदन

का ध्यान दिलाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि प्रजातन्त्र में अपोजी ान का एक महत्व होता है। अपोजी ान का होना उतना ही आव यक होता है जितना सरकार का होना। अध्यक्ष महोदय, अपोजी ान का भी एक रोल होता है, उनके भी कार्यक्रम होते हैं। उनका भी इस प्रदे ा के हितों के बारे में, अपने इलाके की सेवा करने के बारे में, अपने इलाके के लोगों की समस्याओं के बारे में सदन में बोलने का अधिकार बनता है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि प्रजातन्त्र प्रणाली में जब लोग किसी को चुन कर भेजते हैं तो उन चुने हुए नुमाइंदों का यह फर्ज बनता है कि वे लोग सदन में बैठक अपने इलाके के लोगो की जितनी तकलीफें हैं, उनकी ओर सरकार का सदन में बैठकर अपने इलाके के लोगों की जितनी तकलीफें हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाएं ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन आपने अध्यक्ष महोदय, देखा होगा कि जो हमारे अपोजी ान के भाई हैं, उनका कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं है। केवल एक ही मुद्दा उनके सामने है कि प्रदे ा में वातावरण को कैसे खराब किया जाए। सिवाए इसके और कोई काम उनके पास नहीं है। जहां तक हरियाणा के हितों का सवाल है, आप जानते हैं कि जितने भाानदार तरीके से, जिस मजबूती के साथ आज की सरकार ने, हमारे सभी साथियों ने अपने केस को पुट किया है, उसको सारे प्रदे ा के ही नहीं बल्कि सारे दे ा के लोग जानते हैं। लेकिन इस मामले में अपोजी ान के भाईयों ने एक दिन भी सरकार का साथ देने की बात नहीं की कि भाई हम भी आपके

साथ हैं, हम भी आपके साथ मिल कर बात करेंगे। अध्यक्ष महोदय, उनका कर्त्तव्य तो यह बनता था कि वे सरकार के हाथ मजबूत करते। उनको इस बात का पूरा आभासा था कि यह कितना गंभीर मसला हमारे सामने था। 20 जनवरी से 26 जनवरी तक का समय बहुत ही अहम और खतरनाक था और हरियाणा की जिन्दगी और मौत का सवाल था। इन सभी बातों को जानते हुए उनका यह फर्ज बनता था कि सरकार के सामने और परे ाानियां खडी करने के बजाए सरकार का साथ देते ताकि हम अपने केस को औरद मजबूती के साथ पुट करते लेकिन इन सब बातों के बजाये इन लोगों ने सारे प्रदे ा में गडबड करने का पूरा प्रयत्न किया। रास्ता रोको आन्दोलन चलाया और लोगों को पूरी तरह से परे ाान किया। लोगों को परेाान करके सडकों पर लाया गया। यह सब करने का उनका एक ही मुददा था कि लोग तंग हों, वे सरकार और लोगों का टकराव करा सकें और प्रदे ा में गडबड मच जाए। इतना करने के बावजूद फिर भी वे कहते हैं कि हमारा बन्ध कामयाब हुआ है। मेरे अपोजी ान के भाई यह भूल जाते हैं कि हमने अपनी बसें, सरकार व्हीकल्ज स्वयं बन्द की वरना बदमा ा लोग खामखाह झगडा खडा कर देंगे और लूट मार करेंगे। लेकिन ये इन सब बातों को गलत तरीके से बतला कर इसका सेहरा अपने सिर लेना चाहते हैं। जहां तक हरियाणा के हितों का सवाल है, उसके लिये ये लोग यूं ही मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मैं इसकी बैक ग्राऊंड बताता हूं कि एक एकोर्ड श्री राजीव गांधी और लौंगोवाल के दरिम्यान हुआ। मैं इसको तफसील

में नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जो एकोर्ड राजीव–लौंगोवाल के बीच हुआ उसका सारी पार्टियों ने भरपूर स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री वाजपेयी, श्री अडवाणी, और लोकदल के श्री चरण सिंह और बहुगुणा साहब ने भी इस एकोर्ड का स्वागत किया है। यहां हमारे हरियाणा में केवल लोगों को भडकाने के लिये कहते हैं कि हरियाणा के साथ ज्यादती हो गयी है। हर पार्टी की नीति होती है, उसकी अपनी विचारधारा होती है। एक जगह पर जो कहा जाता है, कम से कम उसको तो दूसरी जगह भी स्पोर्ट करना चाहिये और कहना चाहिये लेकिन यहां सिर्फ लोगों को गुमराह करने की, भडकाने की ही बातें की गयीं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि चौधरी देवी लाल जी ने श्री प्रका ा सिंह बादल जी से यह कहा कि अगर 15 अगस्त 1986 तक यह नहर बन गई तो भजन लाल की नींव पाताल में चली जाएगी। इसलिये बादल साहब आप कुछ भी करो, लेकिन यह नहर नहीं बननी चाहिये। बादल साहब ने वहां पर किसानों को ले जाकर बैठा दिया क्योंकि वह आपस में पगडी बदल भाई बने हुए हैं। चुटाला और बादल गांव का आपस में कोई खास अन्तर नहीं है, केवल 20 मील का फासला है। पास पास ही हैं। इसीलिये ये लोग नहर के काम में भी बाधा डाल रहे हैं कि कहीं यह नहर न बन जाए। फिर यें पंजाब के अकाली भाई कहते हैं कि हमारे पास पानी की एक बूंद भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पंजाब में अभी जो इलैक ान हुआ है उसमें इस फाजिल्का अबोहर इलाके के दानों

एम0एल0एज0 भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए हैं। उनको लोगों ने इसी आ वासन पर वोट दिये कि अगर आप एम0एल0ए0 बन गये तो क्या यह इलाका हरियाणा में ले जाओगे। उन्होंने कहा कि हम आपकी वकालत करेंगे और यह कहेंगे कि यह इलाका हरियाणा में जाना चाहिये। वे एम0एल0ए0 बनकर आ गए और उन दिनों मैथ्यू कमी ान के सामने हमारा केस चल रहा था, बहस भाुरू थी। मैंने उन दोनों एम0एल0एज0 को अपने घर पर बुलाया और कहा कि आप लोगों ने वोट मांगते समय लोगों को कहा था कि हम आपको हरियाणा में लेकर चलेंगे। क्या अब आप मैथ्यू कमी ान को लिख कर दे सकते हैं कि वहां के लोगों की भावना है कि वे हरियाणा में जाने के लिए तैयार हैं। उन दोनों ने कहा कि हम खुद लिख कर देने के लिए तैयार हैं कि हम हरियाणा में जाने के लिए तैयार हैं। इस बारे में बाकायदा चिटठी तैयार हुई थी। मैंने कहा कि आप सुबह आकर दस्तखत कर देना। उन्होंने कहा कि आप कच्चा ड्राफट अभी बना लें। उनके कहने के मुताबि ड्राफट तैयार किया गया। उस चिटठी में 88 प्रति ात हिन्दी भाशी लोग लिखे गये थे लेकिन उन्होंने खुद अपने हाथ से काटर 98 प्रति ात किया और कहा कि वहां 98 प्रति ात हिन्दी भाशी हैं उनके हाथ का लिखा हुआ मेरे पास है। उन्होंने कहा था कि इसके मुताबिक आप एक बढिया सा ड्राफट तैयार कर लीजिये सुबह ही हम दस्तखत कर देंगें। वहां से वे एम0एल0ए0 होस्टल में चले गये। वहां उनको डा0 मंगल सैन मिल गए, पूछने लगे कहां गऐ थे, उन्होंने कहा कि भजन लाल को मिलने गए थे। डा0

मंगल सैन उनको कमरे में ले गए और कहने लगे कि ना ा हो जाएगा क्योंकि अगर वह इलाका हरियाणा को मिल गया तो भजन लाल की जड़ें और मजबूत हो जाएंगी। उन्होंनें कहा कि हम तो वायदा करके आए हैं और हमने लोगों को भी कहा था कि आपको हरियाणा में लेकर जाएंगे। डा0 मंगल सैन ने कहा कि नहीं यह काम बिल्कुल नहीं करना। सुबह वे दोनों 8 बजे मेरे घर पर आए और कहने लगे कि चौ0 साहब एक मजबूरी हो गई है कि हमें डा0 मंगल सैन ने रोक दिया है। आप चुपचाप हमें जहां भी ले चलो हम जाने के लिए तैयार हैं और यह बात कहने के लिए तैयार हैं। हम डा0 मंगल सैन की बात को भी भाायद न मानते मगर यही बात कृश्ण लाल भार्मा से भी कहलवा दी। डा0 मंगल सैन अगर गीता पर हाथ रख कर कह दें कि उन्होंने ऐसी बात नहीं कही थी और देवी लाल जी भी कह दें कि उन्होंने प्रका ा सिंह बादल को नहीं कहा था तो मैं अस्तीफा दे दूंगा। (तालियां) ये ऐसे लोग हैं जो हरियाणा के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। ये लोगों को गुमराह करते हैं। अब कहते हैं कि जैसे अकालियों ने सरबत खालसा किया ये सरबत हरियाणा करेंगे। इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि अकालियों के सिर पर काली पगडी और इनका अन्दर काला है। मेरे कहने का भाव है कि यह फैसला दे ा के हित में हुआ था। कितने भयंकर हालात पंजाब में थे। प्रधान मंत्री जी ने बहुत गहराई में जाकर संत लोंगोंवाल के साथ बैठ कर फैसला किया था। हमने उस फैसले का उस दिन भी स्वागत किया था और आज भी करते हैं कि यह

फैसला लागू होना चाहिए। हम चाहते हैं जिस भावना से यह फैसला किया गया था उसी भावना से यह लागू होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि उसमें एक तरफा बात हो। प्रधान मंत्री के सामने सारा दे ा एक समान है। पंजाब हमारा बडा भाई है हम नहीं चाहते कि उसके साथ ज्यादती हो लेकिन बडा भाई छोटे भाई के साथ ज्यादती करे यह मुनासिब नहीं है। कमी ान ने साबित किया है कि 83 गांव और दो भाहर हिन्दी बोलने वाले हैं। बीच में 22 गांवों का बहुत जरूरी पंजाबी भाशी है मगर कंटीग्यूटी को नहीं तोडते हैं। कमी ान ने कहा कि एक कंडूखेडा गांव की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इन्दिरा गांधी जी ने जो एवार्ड दिया था वह सही दिया था। वे हिन्दी बोलने वाले हैं और हरियाणा को मिलने चाहिएं। लेकिन एक गांव की वजह से पंजाब के लोग कहें कि चण्डीगढ तो हम लेंगे लेकिन वह इलाका नहीं देंगे, यह मुनासिब नहीं है। कोई भी आदमी इस मसले को इन्साफ के तराजू से तोलेगा तो वे सारे के सारे गांव हमें मिलेंगे। कल दिल्ली में बरनाला साहब से मेरी मीटिंग हुई। इस बारे में मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, सुरेन्द्र सिंह जी इस बारे में कह रहे थे। मैंने मिटिंग में बरनाला साहब से दोनों गृह मंत्रियों की मौजूदगी में कहा कि अगर आप मेरी जगह होते, इसको सोचकर आप फैसला कर दें, जो फैसला आप करेंगे मैं उसे मान लूंगा। मैंने पूछा कि क्या आप मेरी कुर्सी पर बैठ कर कहते हैं कि चण्डीगढ भी पंजाब को जाना चाहिए और वह इलाके भी पंजाब को जाने चाहिएं। क्या इन्साफ का तकाजा यह कहता है, क्या

आपकी आत्मा यह कहती है, तो बरनाला साहब चुप हो गए। उन्होंने कहा कि समस्या तो आपके सामने बहुत बडी है। फिर कहने लगे कि समस्या मेरे सामनें भी है। मैंने कहा कि तुहाडी समस्या तां टेम्पररी है साडी पक्की है। मैंने कहा कि आपकी समस्या तो चण्डीगढ लेने के बाद भी खत्म नहीं होगी लेकिन अगर आप दोनों चीजें ले गए तो हमें बडी भारी समस्या हो जाएगी। हमारी यह समस्या आज से नहीं है बल्कि 1970 से चली आ रही है। जो भी कांग्रेसी भाई स्टेज पर खडा होकर बोलता था तो कहता था कि चण्डीगढ के बदले में हमें अबोहर और फाजिल्का के इलाके मिलैंगे। जो भी अपोजी ान का नेता इस बारे में बात कहता था वह इस इलाके की ही बात कहता था क्योंकि इन्दिरा जी ने वह इलाका हमें दिया था। कमी ान की रिपोर्ट के मुताबिक चण्डीगढ तथा तीन सौ गांव हरियाणा को मिले हुए थे इनके बदले में इन्दिरा गांधी ने अपने एवार्ड में हमें फाजिल्का अबोहर के 107 गांव दिए और 7 गांव चण्डीगढ के साथ लगते हुए दिए। उस एवार्ड के बाद पंजाब में दीवाली मनाई गई और हरियाणा में इस बात को लेकर लोगों ने बडा भारी एजीटे ान किया और गोलियों से मरे। उस वक्त पंजाब में जस्टिस गुरनाम सिंह अकाली सरकार के मुख्य मंत्री थे। उन्होंने इस एवार्ड को माना था लेकिन आज जो बात हो रही है यह भाोभा नहीं देती। आज वे लोग कहते हैं कि चण्डीगढ भी लेंगे और वह इलाका भी नहीं देंगे। मैं आज फिर हाउस में कहता हूं कि हम चण्डीगढ तभी देंगे जब हिन्दी बोलने वाले वे इलाके हमें मिलेंगे। (थम्पिंग) वरना चण्डीगढ देने का

सवाल ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल पानी का है। यह पानी हरियाणा की जिन्दगी और मौत का सवाल है। इस पानी के बारे में भी उसी एकोर्ड में यह लिखा है कि 15 अगस्त 1986 तक यह नहर तैयार होनी चाहिए। लेकिन जिस दिन से बरनाला साहब पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं उसी दिन से नहर पर काम बन्द पडा है। वहां पर कुछ भी काम नहीं हुआ है बल्कि जो मजदूर या लेबर थी वह वहां से चली गई है। वहां पर कोई कोई सरकारी कर्मचारी ही देखने को मिलेगा। भाम ेर सिंह जी और हमारे दूसरे इंजीनियर्स तथा प्रैस के दोस्त भी वहां पर जाकर देख कर आए हैं, काम के नाम की वहां पर कोई चीज नहीं है। तो 15 अगस्त तक नहर कैसे बन जाएगी ? यह भी तो एकोर्ड का एक हिस्सा है कि 15 अगस्त तक नहर बन जाए। अगर नहर नहीं बनेगी तो हम चण्डीगढ नहीं देंगे। हमें पता है कि अकाली किसी कीमत पर भी नहर नहीं बनाएंगे। हमें उनकी नीयत पर पूरा भाक है उनकी नीयत इस मामले में साफ नहीं है। अरग उनकी नीयत साफ होती और वे वार फुटिंग पर काम करवाते तभी 15 अगस्त तक यह नहर तैयार हो सकती थी लेकिन अब तो 15 अगस्त तक इस नहर के तैयार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी कहते हैं कि पानी की एक बूंद नहीं दैंगे और कभी कुछ कहते हैं। अब सरबत खालसा ने कह दिया कि पानी नहीं देंगे। किसी धार्मिक स्थान पर धार्मिक बात तो हो सकती है लेकिन ऐसी बात नहीं हो सकती। इन लोगों की हमे ाा नीति रही है कि प्रै ार डालकर भारत सरकार से कुछ ले लें। ये एक जगह नहीं टिकते, अगर आज

इनकी एक बात मान लो तो कल को दूसरी खडी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और कहता हूं कि एकोर्ड में एक बात यह भी है कि पंजाब में भाान्ति हो। लेकिन आज पंजाब में क्या हालत है, अगर मैं कहूं कि पहले से भी बुरी हालत है तो यह गलत नहीं होगा। सारा दे ा इस बात को चाहता है कि कम से कम वहां पर भाान्ति तो हो। मैं आज दिल्ली से आ रहा था तो ट्रिब्यून के दफतर में लिखा हुआ था कि बटाला में करफयू लगा हुआ है। वहां पर दो तीन आदमी मर गए हैं और 6–7 घायल हो गए हैं। यह तो वहां पर हालात चल रहे हैं। इसीलिये साथ के राज्य का फर्ज बनता है कि वह एकोर्ड की एक एक बात को सीरियसली ले। जिस भावना से एकोर्ड हुआ है उसी भावना से वह लागू होना चाहिए संत लोंगोंवाल जी ने खुद वकीलों को एड्रैस किया था कि 55–60 गांव जरूर हरियाणा को जाएंगे बाकी भाायद न जा सके। तो 55–60 गांव उन्होंने खुद माने थे। इस बारे में बीसियों अखबारों में उनके बयान छपे थे। उन्होंने फिरोजपुर में वकीलों की बार एसोसिए ान को एड्रैस करते हुए कहा था कि अबोहर के एरिया के 55–60 गांव जरूरत हरियाणा में जाएंगे। उन्होंने 55–60 गांवों से कहना भाुरू किया था मगर वे जानते थे ये 107 गांव सारे के सारे हरियाणा में जाएंगे जो कि हमने कमी ान के सामने रखे। लेकिन वे सारी बातें उलझा करके या प्रै ार से तोडना चाहते हैं, तारपीडो करना चाहते हैं। यह उनकी मुनासिब बात नहीं है। प्रधान मंत्री जी ने ने ानल हित में एकोर्ड किया इसलिए हम चाहते हैं कि वह लागू

हो। जिस भावना से एकोर्ड हुआ है उसी भावना से लागू होना चाहिए ताकि दे ा के अन्दर वातावरण ठीक हो। जहां तक दूसरी बात का सवाल है, वह मैं यह कहना चाहूंगा कि अपोजी ान के भाई हाउस में होते तो उनके सामने बातें कहने का मजा आता लेकिन अपोजी ान के भाईयों में हमारी बात सुनने की भाक्ति नहीं है इसलिए वे हाउस में नहीं आए। अपोजी ान के भाईयों ने अस्तीफा दे कर यहां मीटिंग की। उस मीटिंग में आधे से ज्यादा मैम्बर्ज ने यह कहा कि हमें असैम्बली में जाना चाहिए कुछ ने कहा कि नहीं हमें असैम्बली में नहीं जाना चाहिए। चौधरी देवी लाल जी ने कहा कि हमें असैम्बली में नहीं जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वे असैम्बली में इसलिए नहीं आए क्योंकि उनका प्रजातन्त्र में वि वास नहीं है उनको वि वास तोडाफोडी में है। यदि उनका प्रजातन्त्र में वि वास हो तो वे हमारे साथ बैठ कर बात करें, उनका प्रजातन्त्र में वि वास ही नहीं है। आदमी असैम्बली में आकर बैठे और कोई बात कहनी हो, वह हमारे सामने कहे लेकिन चौधरी देवी लाल जी तो कहते हैं कि असैम्बली में मेरे मुकाबले का कोई आदमी ही नहीं है, इसलिए मैं उनके क्या बात करूं, अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी कहते हैं कि क्या करूं असैम्बली में मेरे ताडेगो कोई आदमी ही कोनी और न कोई मेरे मुकाबले गो आदमी। अब इस बारे में क्या कहा जा सकता है। उनके सामने बडी मु कल आई हुई है, पता नहीं उनको मुकाबले के लिए कैसा आदमी चाहिए। लोगों के सामने इस तरह की बात कहते हैं, चौधरी देवी लाल जी लौगों के सामने इस तरह की बातें

कह कर सस्ती लीडरी लेना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, अपोजी ान के भाईयों ने अपने अस्तीफ आपको दिए और आपने उसनको उनके अस्तीफों के बारे में पूछताछ के लिये बुलाया तो वे कहते हैं कि हम नहीं आते। यदि उन्होंने अपने अस्तीफ दिए हैं तो आपके बुलाने पर आपके सामने आकर कहते कि अस्तीफे हमनें दिए हैं, आप इन्हें मंजूर करो। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आप देखना एक दिन आकर वे कहेंगे कि हम अपना पिछला टी0ए0 भी लेकर जाएंगे। यदि मेरी अपोजी ान के भाईयों ने अपने अस्तीफे दिए हैं तो आपके सामने आते और आ कर अपने अस्तीफ मंजूर करवाते। उन्होंने अस्तीफे भी दे दिए और मंजूर भी नहीं करवाते, यह कोई बात है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, कल यहां पर बी0जे0पी0 के भाई आए और भाोर मचा कर चले गए ताकि उनका नाम प्रैस में आ जाए और लोगों में उनका नाम हो जाए। लेकिन लोगों में इस बात की समझ है कि ये लोग एक साल के बाद होने वाले चुनावों के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या ऐसा करने से लोग इनको वापिस चुन कर यहां भेजेंगे। मेरे अपोजी ान के भाई अपने घरों में बैठ कर लोगों की नुमायंदगी करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको यहां आकर अपने हल्के के लोगों की नुमांयदगी करनी चाहिए। अपने घरों में बैठ कर ऐसा करने से वे लोगों को गुमराह और धोखा दे रहे हैं। मेरे अपोजी ान के भाई यहां हाउस में आते और अपने हल्के के लोगों की समस्याऔं को हल करने की बात करते, हमें लोगों की समस्याओं का समाधान करने के रास्ते बताते। अपने हल्के के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के

रास्ते बताते। अपने हल्के के लोगों की तकलीफों के बारे में हमारे से बात करते। देहातों में पीने के पानी की बात करते, किसानों के लिए नहरी पानी की बात करते, बिजली के बारे में बात करते फिर तो हमें उनकी बात समझ आ सकती थी लेकिन उनके पास सिवाय लोगों को गुमराह करने के कोई दूसरी बात नहीं है। इसलिए मेरा अपोजी ान के भाईयों को इतना कहना है कि वे मेहरबानी करके लोगौं को गुमराह करने की कोि ा ा न करें। लोगों को गुमराह करने से प्रदे ा का अमन और भाांति खराब होती है। यदि प्रदे ा में अमन खराब होता है तो उसको ठीक करने के लिए सरकार को कार्यवाही करनी पडती है। अध्यक्ष महोदय, अपोजी ान के भाईयों ने कहा है कि हरियाणा में रास्ता रोको आन्दोलन में तीन आदमी मर गए। मैं एक बात कहना चाहूंगार कि हमारी पुलिस ने बहुत संयम और धैर्य से काम लिया, अगर पुलिस धैर्य से काम न लेती तो सैकडों लोग भी मर सकते थे। लेकिन हमने सोचा कि वे भी हमारे ही भाई हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बेटे हैं पिछले दिनों पंजाब के अन्दर नकोदर टाउन में वाका हुआ और वहां पर तीन आदमी मर गए। हरियाणा प्रदे ा में भी तीन जगहों पर गोलियां चलीं क्यौंकि लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसलिए पुलिस को मजबूर होकर गोलियां चलानी पडीं ताकि और ज्यादा स्थिति न बिगडे तथा प्रदे ा में अमन भाांति खराब न हो। अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और सारा हरियाणा जानता है कि प्रदे ा के अन्दर कितना अमन है। मैं अपनी एडमिनिस्ट्रे ान को इस बात की बधाई देता हूं और उनकी तारीफ करता हूं कि

उन्होंने प्रदे ा में भाांति कायम रखने के लिए बडी सूझबूझ से काम लिया। दूसरे प्रदे ा के लोग भी इस बात की बडी तारीफ करते हैं कि हरियाणा में अमन है। हमारे एडमिनिस्ट्रे ान ने प्रदे ा में बहुत अच्छे तरीके से अमन कायम रखा है जबकि पडौसी प्रदे ा पंजाब में आग लगी हुई है। कोई आदमी अपने पडौस में लगी आग से अपने घर और अपने को बचा ले यह कोई छोटी बात नहीं है। यह घर भी हमारे अच्छे एडमिनिस्ट्रे ान की वजह से बचा हुआ है। मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे अपोजी ान के भाई अपने संयम में रह करके ही हरियाणा के हितों की रक्षा कर सकते हैं। वे यहां सदन में बैठ कर हमारे साथ बात करें और हमें हरियाणा की समस्याओं को सुलझाने का कोई रास्ता बताएं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के हितों के बारे में हमारी बातचीत बहुत सदभावना से हुई है। आज भी और पहलें भी सदभावना के वातावरण में बात हुई है। मैंने बरनाला साहब से कल कहा था कि आप कंडूखेड़ा गांव के बदले में चार गांव दूसरे ले लें लेकिन एक गांव की वजह से सारे हिन्दी बोलने वाले इलाके को इस तरह से बांध कर न रखें। यह कोई मुनासिब बात नहीं है कि आप एक गांव के लिए पांच लाख की आबादी के भाहर को तो लेना चाहें और एक दो हजार की आबादी का गांव दे नहीं। क्या यह बात मुनासिब है कि 85 गांव हिन्दी बोलने वाले तो पंजाब में रह सकते हैं और एक गांव पंजाबी बोलने वाला हरियाणा में नहीं रह सकता। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं और पडोस के भाई भी जानते हैं कि उस गांव में लोगों के साथ कितना जुल्म हुआ। उस

गांव के लोगों को किस तरह से उठा कर बाहर ले जाया गया और उनके घरों में दूसरे लोगों को बैठा दिया गया। मैं कहता हूं कि ठीक है उस गांव में पंजाबी बोलने वालों की मैजोरिटी दिखा दी लेकिन मैं यह भी कहता हूं कि उस गांव में 55 परसैंट लोग हिन्दी बोलने वाले रहते हैं। पंजाब सरकार ने उस गांव में वातावरण बिगाडने की कोि ा ा की ताकि कंटीग्यूटी टूट जाऐ और हरियाणा को वह इलाका न मिले। अध्यक्ष महोदय, हमें अपने प्रधान मंत्री जी पर पूरा वि वास है कि वे हमारे साथ इन्साफ करेंगे। मैं पंजाब के भाईयों से निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब हमारा बडा भाई है और हरियाणा उसका छोटा भाई है इसलिए वे अपने छोटे भाई के साथ अन्याय न करें। हम पडोसी हैं हमैं आपस में मिल जुल कर रहना है। हम एक जगक के रहने वाले हैं इसलिए उस जगह का वातावरण ठीक रखना चाहिए ताकि हमारे आपस में तालुकात ठीक रहें। यदि दो भाई आपस में इन्साफ की बात नहीं करते तो वातावरण ठीक नहीं रह सकता। उनकी आपस में भावनाएं ठीक नहीं रह सकतीं और न ही आपस में माहौल ठीक रह सकता हैं माहौल भी तभी ठीक रहेगा जब वातावरण ठीक रहेगा। अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रदे ा की प्रगति के बारे में बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदे ा ने थोडे से अर्से में कितनी प्रगति की है। माननीय सदस्यों ने जो मांगे मांगी हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। हरियाणा प्रदे ा ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। प्रदे ा की तरक्की का तब पता लगता है जब इस प्रदे ा के लोग दूसरे प्रदे ाों में जाकर देखते हैं कि उन प्रदे ाों की क्या

हालत है। दे ा के दूसरे प्रदे ाों की तरक्की का मुकाबला हरियाणा में हुई तरक्की के साथ करें तो हर आदमी यह महसूस करेगा कि हरियाणा में बहुत तरक्की हुई है। हरियाणा प्रदे ा ने थोडे से अर्से में नहरी पानी, पीने का पानी, सडकें बनाने के बारे में, बिजली उत्पादन के मामले में, ि ाक्षा के क्षेत्र में और अनाज के उत्पादन में, किसी भी अदायरे में देख लें हर क्षेत्र में हरियाणा प्रदे ा ने महान उपलब्धि प्राप्त की है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाशण में बडे विस्तार से बताया है। मैं आपके द्वारा सदन को थोडे से आंकडे देकर बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, छठी पंच वर्शीय योजना में प्रदे ा के लोगों की भलाई के लिए 1600 करोड रूपए खर्च किये थे जबकि सातवीं पंचवर्शीय योजना में 2900 करोड रूपए खर्च करने का प्रावधान है। यह रा ि ा छठी पंचवर्शीय योजना के मुकाबले में दोगुने से सिर्फ तीन करोड रूपए ही कम है। वर्श 1986–87 की वार्शिक योजना में 80 करोड रूपए की उपलब्धि है यानी 525 करोड रूपए की वार्शिक योजना है यह पैसा प्रदे ा के लोगों की भलाई के लिए खर्च होगा। यानी एक रूपए में से 75 पैसे देहात में रहने वाले गरीब हरिजनों, बैकवर्ड क्लास के लोगों और छोटे किसानों की भलाई के लिए खर्च किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जब हरियाणा बना था उस समय यहां लगभग 26 लाख टन अनाज पैदा होता था लेकिन आज 70 लाख टन अनाज पैदा होता है जो कि एक रिकार्ड है। अगलग साल 80 लाख टन अनाज पैदा होने

का अनुमान है। यही नहीं, चावल के उत्पादन में भी हमारे प्रदे ा ने रिकार्ड कायम किया है। पिछले साल साढे 13 लाख टन चावल पैदा हुआ और इस साल 17 लाख टन चावल पैदा किया है जो कि एक रिकार्ड है। इसी तरह से गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में और दूसरे खेती के क्षेत्रों में भी ज्यादा से ज्यादा तरक्की की है। लेकिन एक बात मैं बिजली के बारे में कहना चाहूंगा। यह ठीक बात है कि आज प्रदे ा में बिजली की कमी है। जो प्रदे ा तरक्की करता है तो तरक्की के साथ साथ मांग भी बढती है। बिजली और पानी दोनों तरक्की के साधन हैं जिस समय हरियाणा बना उस समय यहां सिर्फ 340 मैगावाट बिजली तैयार होती थी। उस समय बिजली को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। आज के दिन हरियाणा के पास 1445 मैगावाट बिजली है लेकिन मांग फिर भी पूरी नहीं हो रही। आज के दिन हरियाणा में 3 लाख से ज्यादा टयूबवैल्ज लगे हुए हैं जबकि उस समय सिर्फ 20 हजार टयूबवैल्ज थे। इसी प्रकार से पहले सिर्फ 5 हजार उद्योग थे जबकि आज के दिन 60 हजार से ज्यादा उद्योग हैं। आज के दिन गांव गांव में बिजली पहुंची हुई है। प्रदे ा में दुनिया भर के कल कारखाने लगे हैं। बिजली की मांग बहुत बढी है। मांग जब बढती है तो दिक्कत भी होती है। बिजली के बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले केन्द्रीय मंत्री श्री साठे साहब पानीपत में आये थे। उन्होंने हमारी सारी बातों को बडे ध्यान से देखा। पानीपत में हमारा 110 मैगावाट का एक यूनिट इसी 31 मार्च को चालू हो जायेगा। दूसरा 110 मैगावाट का यूनिट अक्तूबर,

1986 में चालू हो जाएगा और एक 210 मैगावाट का यूनिट 1987–88 कि साल में चालू हो जायेगा। इस प्रकार से 210–210 मैगावाट के 4 यूनिट यानी 840 मैगावाट की बिजली और तैयार की जायेगी जिस पर 850 करोड रूपये खर्च आएंगे। इसके लिए वे बाकायदा मन्जूरी दे कर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इसके लिए कैनेडा से या जर्मन से एग्रीमैंट करेगी। इस योजना के लिए दोनों दे ाों के साथ बातचीत चल रही है। ये दोनौं दे ा हमारे यहां इस योजना पर पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। अब यह काम भारत सरकार का है कि किस से यह काम करवाना ठीक समझेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक 7वीं योजना खत्म होगी हमारे यहां 840 मैगावाट नई बिजली होगी। इसके अलावा यमुना नगर के अन्दर 8–8 मैगावाट के 4 यूनिट और हाईडल के चाले हो जायेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी भरसक कोि ा ा है कि किसानों को पूरी बिजली मिले। हमारे कारखाने तभी आगे बढेंगे जब उन्हें अधिक बिजली मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, पर कैपिटा जो खर्च होता है उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। सातवें पलन में हरियाणा की पर कैपिता आउटले एवरेज 2888 है जबकि सारे हिन्दुस्तान की 1442 है। इससे साफ जाहिर है कि इस मामले में भी हरियाणा सारे हिन्दुस्तान से आगे हैं आज का जो नौजवान बेरोजगार है उसको रोजगार देने के लिए भी सरकार ने कई स्कीमें बनाई हुई हैं। देहात में इंडस्ट्री लगाने के लिए सरकार एक बेरोजगार नौजवान को 25 हजार रूपये तक का लोन दे रही है। यह स्कीम भारत

सरकार की है। इस साल हमें वहां से इस स्कीम के तहत कम पैसा मिला था। इसके लिए हमने भारत सरकार से बात की है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा दें ताकि हम अपने पढे लिखे बेकार नौजवानों को रोजगार दे सकें, उनको काम दे सकें।

इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, सदस्यों को यह जानकार खु ाी होगी कि इलैक्ट्रोनिक्स के मामले में हरियाणा दे ा में प्रमुख प्रदे ा के रूप में उभरा है। जिला गुड़गांव में उद्योग बिहार में 600 यूनिट कायम किए जा रहे हैं। मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि अगले 5–6 सालों में दे ा में प्रतिवर्श इलैक्ट्रोनिक्स का जो सामान बनाया जायेगा उसका 10 प्रति ात भाग अकेला हरियाणा बनायेगा। हम इस मामले मैं दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा पहले करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, आर्थिक सहायता कार्यक्रम भाुरू किया है। सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत अपनी विकास नीति को आधार बनाया है। हरियाणा सरकार ने आई0आर0डी0पी0 की स्कीम के तहत जनवरी, 1986 तक 414.83 लाख रूपये की इमदाद दी है और 923.49 लाख रूपये के ऋण बांटे हैं। एन0आर0ई0पी0 तथा आर0एल0ई0जी0पी0 की दोनों स्कीमों के प्रोग्रामों के तहत 19.33 लाख श्रम दिनों का काम निकाला गया और लोगों को रोजगार दिया गया। इसके साथ साथ गंदी बस्तियों में 1985–86 के लिए 40 हजार के नि ााने के मुकाबिले में जनवरी 1986 तक 61627 व्यक्तियों के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया गया।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ अनुसूचित जातियों, पिछडी श्रेणियों और निम्न वर्गों को भी कई और स्कीमों के तहत अधिक से अधिक सुविधा दी जा रही है। छठी पंचवर्शीय योजना में इन वर्गों के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत 1070.90 लाख रूपये खर्च किए गए। 7वीं योजना में इन कल्याण स्कीमों के तहत 3400 लाख रूपये रखे गये हैं जो कि पिछली योजना के मुकाबले में 217 प्रति ात ज्यादा हैं। समाज के इन वर्गों की वित्तीय द ाा में सुधार के लिए हरियाणा हरिजन कल्याण निगम और हरियाणा पिछडे वर्ग कल्याण निगम ने चालू वर्श में क्रम ाः अनुसूतिचत जातियों के 15.362 परिवारों और पिछडे वर्गों के 1717 व्यक्तियों की सहायता प्रदान की है। अध्यक्ष महोदय, हमारा मेवात का क्षेत्र पिछडा हुआ हे। इसके उत्थान के लिए भी हमने अढाई करोड रूपये रखे हैं ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। हमारे प्रदे ा के जो एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाईटर हैं उनको भी हमने वि ोश रियायत दी है। एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाईटरों को जो सुविधा हमने दी हैं उसको देखते हुए दूसरे प्रदे ा के लोग कहते हैं कि हमें भी यह सुविधा हरियाणा प्रान्त के लोगों की तरह मिले। जो सुविधा हमने इन लोगों को दी है उसको देखते हुए दूसरे प्रदे ाों की सरकारें हमें कहती हैं कि हमारे लिए तो आपने आफत डाल दी है। वे कहते हैं कि हमारे यहां के एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाईटर भी आप वाली सुविधा की मांग कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमने इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की कोि ा ा की है। इसी प्रकार से हमने

ि ाक्षा, हस्पताल, पब्लिक हैल्थ, हैल्थ और पीने के पानी के लिये लोगों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान की है। अध्यक्ष महोदय, आने वाले डेढ साल में प्रदे ा को कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें पीने का पानी उपलबध न हो। इस काम के लिए हमने 7वीं योजना में 111 करोड रूपये खर्च करने के लिए रखे हैं। ताकि हर गांव को पीने का पानी मिल सके। ि ाक्षा के क्षेत्र में भी हमने वि ोश ध्यान दिया है। खासकर लड़कियों की ि ाक्षा की तरफ ध्यान दिया जा रहा है ताकि वे अच्छा पढ लिख सकें। अगली योजना में लड़कियों के लिए 500 नए प्राईमरी स्कूल खोलने जा रहे हैं। 1986–87 में ि ाक्षा पर 120 करोड रूपये खर्च किए जा रहे हैं। इस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए 63 करोड रूपये खर्च करने जा रहे हैं। इसी तरह से पर्यटन और परिवहन की तरफ भी वि ोश ध्यान दिया जा रहा है। हमारी रोडवेज की सभी प्रान्त तारीफ करते हैं। इसी प्रकार से हमारे यहां की सडकें भी दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा अधिक अच्छी हैं। जब कोई व्यक्ति बाहर से हरियाणा में दाखिल होता है तो उसे सडक से ही पता लग जाता है कि हरियाणा आ गया। उसे मालूम है कि इतनी अच्छी सडकें यहीं की हो सकती हैं। सडकों के बारे में यहां पर कई सदस्यों ने जिक्र किया था। सभी को मालूम है कि हरियाणा में आज कोई ऐसा गांव नहीं है जो सडकों से जुडा हुआ नहीं है। हर गांव तक सडक पहुंचा दी गई है।

मैं कहना चाहूंगा कि सडकों का यदि मुकाबला करना है तो दूसरे प्रान्तों की सडकों को देख कर किया जाये तभी पता चल सकेगा कि कहां की सडक ठीक है। हरियाणा की इतनी अच्छी सडकें हैं कि बस में बैठे हुए कोई झटका नहीं लगता जबकि दूसरे प्रान्तों की सडकों पर इतने झटके लगते हैं कि लोग बैठे बैठे परे ाान हो जाते हैं। हमार इंजीनियरों ने सडकें बहुत अच्छी बनाई हुई हैं। यदि कहीं कोई छोटी मोटी त्रुटि है तो उसको भी दूर करने की कोि ा ा करेंगे। कुछ माननीय सदस्यों ने अपने अपने हलकों की समस्याएं रखी हैं, उनकी चर्चा भी मैं यहां पर करना चाहूंगा। चौधरी फूल चन्द मुलाना नें यहां पर कुछ कार्यक्रमों के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने एक बात बाढ के बारे में कही। बाढ के बार में सरकार ने काफी ध्यान दिया है। पिछले दो सालों में किसी भी इलाके में बाढ नहीं आई। मैं तो यह कह सकता हूं कि बाढ की रोकथाम के लिए जितना काम पिछले दो तीन सालों में हुआ है उतना भाायद 15 सालों में नहीं हुआ होगा। उन्होंने यह भी मांग की कि टांगरी और मारकंडा बैरेजिज जल्दी बनाए जाएं। अध्यक्ष महोदय, इस पर 60 करोड रूपये से अधिक खर्च होगा। इसकी केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त होनी है। हम तो चाहते हैं कि जैसे ही पैसा मिले हम काम भाुरू करें। मुलाना साहब ने पीने के पानी और बिजली आदि का भी जिक्र किया। इन्होंने यह भी कहा कि जो ग्रामणी पढे लिखे नौजवान बेरोजगार फिरते हैं, उनको काम दिया जाए। इनकी यह बात ठीक है। इस तरफ सरकार ध्यान दे भी रही है और आयंदा भी देगी। हरिजनों

को प्लौटस देने का भी इन्होंने जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि जहां कहीं कोंई कमी है उसे सरकार जल्दी से जल्दी दूर करेगी।

चौधरी ई वर सिंह जी ने सौर उर्जा का जिक्र किया। इस तरफ भी सरकार ध्यान देगी। फिलहाल रायपुर रानी और करनाल ब्लॉक को सौर उर्जा स्कीम के तहत सिलैक्ट किया गया है। एक करोड रूपए की लागत से सौर उर्जा के 20 संयंत्र भी लगाए गए हैं। सौर उर्जा के उपयोग की कई अन्य योजनाएं भी सरकार द्वारा चालू की जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, राव निहाल सिंह जी ने कहा कि मेहन्द्रगढ में जे0बी0टी0 ट्रेनिंग की सुविधा होनी चाहिए। इस बारे में जरूर विचार करेंगे। अगर जरूरत हुई तो वहां यह सुविधा जरूर दी जाएगी।

धमीजा साहब ने कहा कि अम्बाला जिला इंडस्ट्रीज के हिसाब से पिछडा हुआ है। उन्होंने कहा कि वहां इंडस्ट्रीज चाहिएं और अम्बाला जिले को इंडस्ट्रली बैकवर्ड घोशित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हमने भारत सरकार को 1983 में लिखा, 1984 में लिखा और 1985 में लिखा। उनसे हमने बात भी की लेकिन भारत सरकार अभी मानी नहीं है। इन्होंने अम्बाला के हस्पताल का भी जिक्र किया। उसके लिए सरकार ने कुछ पैसा

दे दिया है। बाकी का पैसा देकर उस हस्पताल को हम जल्दी तैयार करवाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, बैंकों के बारेम में भी यहां जिक्र आया। यह ठीक है कि बैंकों में कुछ दिक्कत है लेकिन आप जानते हैं कि राश्ट्रीयकृत बैंकों पर हमारा कंट्रोल नहीं है लेकिन फिर भी भारत सरकार से इस बारे में हमने कहा है। समय समय पर हम मीटिंग भी करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो, जायज लोन किसान को, आम आदमी को बिना कठिनाई के मिलना चाहिए।

श्री सूबे सिंह पुनिया ने उचाना में डिग्री कालेज खोलने का जिक्र किया। उसे बारे में भी जरूर विचार करेंगे। श्री अजमत खां जी ने कहा कि नगीना कालेज में साईंस क्लासिज का प्रावधान किया जाए। इसके बारे में भी विचार करेंगे। श्री अमीर चन्द मक्कड़ जी ने हांसी कताई मिल के मजदूरों की मांगें स्वीकार करने के लिए कहा। इस बारे में भी गवर्नमैंट विचार करेगी हालांकि मजदूरौं की तरफ से कोई डिमांड नोटिस हमें नहीं आया है। इन्होंने मार्किट हालांकि के सैंस के बारे में भी जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सैंस का सम्बंध है, हाई कोर्ट तक तो हम जीत गए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें डाउन कर दिया। इन्होंने यह भी कहा कि पैसा व्यापारियें की जेबों में गया लेकिन यह बात ठीक नहीं है क्योंकि व्यापारियों से तो वह लिया गया है। इसके अलावा मैं यह भी बता दूं कि व्यापारियों को यह पैसा

वापिस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कानून में जो कमी रह गई है उसे दूर करने के कोि ा ा करेंगे ताकि यह सैंस लागू रहे क्योंकि यह लोगों की भलाई के लिए है। फिर इन्होंने कालेज के बारे में कहा। हांसी में एक प्राईवेट कालेज है। उसकी बिल्डिंग ठीक नहीं है। उसके लिए जमीन ऐक्वायर की गई थी। मुकद्दमा चल रहा है। फैसला होने के बाद इस सम्बंध में भीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

श्री इन्द्र सिंह नैन जी ने बरवाला में कालेज खोलने के बारे में कहा। इसके बारे में विचार करेंगे क्योंकि आस पास कोई कालेज न होने की वजह से वहां कालेज होना ही चाहिए। इन्होंने यह भी कहा कि उकलाना मंडी में 132 के0वी0 स्टे ान होना चाहिए। इसका प्रावधान 7वीं योजना में किया गया है। अनुमति केन्द्रीय सरकार से आनी है। उम्मीद है अनुमति जल्दी ही मिल जाएगी। उसके बाद इसका काम जल्दी ही भाुरू कर दिया जाएगा।

श्री दयानन्द भार्मा जी ने कहा कि फसलों के ऊपर छिडकी जाने वाली दवाई ठीक नहीं। इसको हम चैक करवाएंगे। समय समय पर हम चैक करवाते भी रहते हैं। मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि यदि कहीं इनकै नोटिस में यह बात आए कि फलां दफतर में या फलां जगह कोई आदमी गलत दवाई देता है तो ये हमें बताएं ताकि सरकार उसके खिलाफ आव यक कार्यवाही कर सके।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने कहा कि ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम के तहत ग्रामवासी युवकों को रोजगार दिया जाए। यह बात ठीक है। यह योजना ग्रामीण युवकों के लिए ही बनाई गई हैं। इस तरह की सुविधा उन्हें अव य दी जाएगी। एक बात इन्हौंने नैतिक ि ाक्षा के बारे में कही। इसका प्रावधान हमने पहले किया हुआ है। इसको चैक करेंगे और अगर कहीं कमी हुई तो उसे दूर करेंगे।

फिर यहां पर पानीपत और फरीदाबाद में बिजली के उत्पादन की कमी के बारे में कहा गया। समय समय पर मैंने इस बात को देखा है। कई बार मंत्री महोदय, बिजली बोर्ड के चेयरमैन और इंजीनियर्ज आदि की मीटिंग्ज भी बुलाइ हैं और बिजली का उत्पादन बढाने के लिए इन्हें कहा भी है। लेकिन बात यह है कि हमारे यहां जो प्लांट लोड फैक्टर होना चाहिए वह नहीं है। उसके कुछ कारण भी हैं। एक कारण तो यह है कि बाकी प्रान्तों में 5–5, 6–6 यूनिटस लगे हुए हैं। अगर वहां दो यूनिटस बंद भी हो जाएं तो कोई खास फर्क नहीं पडता लेकिन हमारे यह कम यूनिटस होने की वजह से काफी फर्क पडता है फिर भी हम कोि ा ा करेंगे कि बिजली का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो।

अध्यक्ष महोदय, हुकम सिंह जी ने आई0टी0आई0ज0 की संख्या बढाने की मांग की है। इस समय प्रदे ा में 39 आई0टी0आई0ज0 पुरूशों के लिए ाऔर 27 आई0टी0आई0ज0 महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त 42

व्यवसायिक संस्थान भी काम कर रहे हैं। हाल ही में एक नया संस्थान महिलाओं के लिए जींद में खोला गया है जिसमें रेडियो, टी0वी0 और सिविल प्रारूपकार की ट्रेनिंग की व्यवस्था हैं। इस पंचवर्शीय योजना के तहत हर वर्श 12 नए व्यवसायिक केन्द्र खोले जाते रहेंगे जिनमें अन्य ि ाक्षा के साथ साथ व्यावसायिक ि ाक्षा का भी प्रबन्ध किया जाएगा।

श्री दयानन्द भार्मा जी ने कर्जों के बारे में भी जिक्र किया। उन्हें मैं यह बताना चाहता हूं कि योजना के तहत जहां जिस बात की जरूरत महसूस होती है उसकी घोशणा हम आमतौर पर करते रहते हैं।

श्री इन्द्र सिंह नैन जी ने यह भी कहा था कि कर्जे देने में देरी होती है। यह बात ठीक है कि कर्जा लेने में लोगों को कई दिक्कते पे ा आती हैं लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि पिदले दो वर्शों में ही कम कर्जा देने का लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। फिर भी जो दिक्कते आती हैं उन्हें दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री दयानन्द भार्मा जी ने अध्यापकों की कमी दूर करने का सुझाव भी दिया था। यह सुझाव ठीक है। अध्यापकों की कमी अव य दूर करेंगे।

श्री हुकम सिंह जी ने प्राईमरी ि ाक्षा की ओर वि ोश ध्यान देने की बात कही। यह बात ठीक है क्योंकि बेस पक्का होना चाहिए और प्राईमरी ि ाक्षा से ही जीवन की भ्ाुरूआत होती है।

अध्यक्ष महोदय, बरवाला को तहसील बनाने, मातनहेल में सैनिक स्कूल खोलने और कई जगह प ुिओं के हस्पताल खोलने के बारे में भी यहां जिक्र आया। इन सारी बातों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। (विघ्न) श्री भले राम जी ने पंजाब एकोर्ड के बारे में जिक्र किया। इन्होंने यह भी कहा कि खालों का लैवल ठीक नहीं है। इन्हौंने यह भीह कहा कि वीकर सैक ान के लोगों को ऊपर उठाने के लिए 7वीं योजना में 54 करोड रूपया बहुम कम रखा गया है। तहसील वैल्फेयर औफिसर्ज के बारे में भी इन्होंने कुछ बातें कहीं। सडकों के निर्माण के बारें में भी इन्होंने कहा है। इन सारी बातों को हम ऐग्जामिन करवाएंगे और जो होने वाला काम होगा उसे जरूर करेंगें।

कुछ बातें सुबे सिंह पूनिया और भारदा रानी जी ने भी कही हैं। उन पर भी सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाएगा। लीला कृध्या जी ने एक बात ट्रांसफार्मर्ज के बारे में कहीं और दूसरी बात बाढ से अफैक्टिड मकानों का मुआवजा देने के बारे में कहीं। जहां तक मुआवजा देने का सम्बंध है, भारत सरकार ने इसके लिए हमें कुछ नहीं दिया कच्चे मकान का जो चार सौ रूपया और पक्के मकान का पांच सौ रूपया दिया गया है वह भी राज्य सरकार ने अपनी तरफ से दिया है।

18.00 बजे।

जहां तक पंजाब को पैसे मिलने का सम्बंध है, वहां का मामला दूसरा है। हमने स्टेट की तरफ से पैसा दिया है और जहां पर बाकी रह गया है उसे भी जल्दी देने की कोि ा ा करेंगे।

स्पीकर साहब, माननीय सदस्यों ने जितने भी सुझाव दिए हैं हम उन्हें पूरी तरह से अमलीजामा पहनाने की कोि ा ा करेंगे। अब मैं सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाशण सदन में दिया है, उसे सर्व सम्मति से पास किया जाए। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

राज्यपाल के अभिभाशण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर मतदान

श्री अध्यक्षः जब मैं मो ान पुट करता हूं।

प्र न है–

'गवर्नर साहब को एक ऐड्रस फालोइंग टर्मज में प्रजैन्ट किया जाये–

"कि इस सै ान में असैम्बल हुए हरियाणा विधान सभा के मैम्बर्ज उस ऐड्रस के लिए गवर्नर साहब के डीपली ग्रेटफुल हैं जो उन्होंने 17 फरवरी, 1986 को हाऊस में डिलिवर करने की कृपा की हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब हाउस कल सुबह साढ़े नौ बजे तक के लिए एडजर्न किया जाता है।

18.01 बजे।

(तत्प चात सदन वीरवार 20 फरवरी 1986 प्रातः 9.30 बजे तक स्थगित हुआ।)